राजस्थान विधान सभा

द्वितीय बैठक, मंगलवार, दिनांक १ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा भवन जयपुर में ८ बज कर ३५ मिनट (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १

एस. ए. एस. का चुनाव व उसमें सप्लाई विभाग के कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता:—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में एस. ए. एस. का सिलेक्शन कब किया गया?

(ख) उक्त सिलेक्शन में कितने ऑफिसर्स लिये गये?

(ग) उक्त ऑफिसर्स में सप्लाई डिपार्टमेंट के कितने आदमी हैं?

(घ) सप्लाई विभाग के एस. ए. एस. में आये हुए कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें एस. ए. एस. की ग्रेड नहीं मिल रही है?

(ङ) उक्त ग्रेड नहीं मिलने के क्या कारण हैं?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया)—

(क) सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (एस. ए. एस.) नाम की कोई विशेष सर्विस नहीं है। भिन्न-भिन्न विभागों की सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का चुनाव मार्च, १९५१ से अप्रेल, १९५२ तक हुआ।

(ख) उक्त चुनाव में कुल ६२४ व्यक्ति चुने गये।

(ग) उपरोक्त व्यक्तियों में १७८ रसद विभाग के हैं।

(घ) जो व्यक्ति सिविल सप्लाई विभाग की सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदों के लिये चुने गये थे, उनको निर्धारित स्केल का वेतन उसी समय तक मिला जब तक वे सिविल

Page No.2

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

सप्लाई में रहे। उक्त विभाग में उनकी अस्थाई (टेम्परेरी) नियुक्तियां समाप्त होने पर उनको अन्य विभागों में अन्य पदों पर लगाया गया। उन व्यक्तियों को वही वेतन दिया जा रहा है जो उन पदों के लिये स्वीकृत हैं।

(ङ) सिविल सप्लाई विभाग में एस. ए. एस. के पदों की नियुक्तियां अस्थाई होने के कारण जो वेतन उनको इन पदों पर दिया गया था अन्य विभागों के अन्य पदों पर चालू नहीं रखा जा सकता था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन की मार्फत हुआ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं, सिलेक्शन कमेटी के मार्फत हुआ था जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने एप्रूव किया था ?

श्री चांदमल मेहता—जिस कमेटी ने सिलेक्शन किया, एप्रूव किया तो क्या उसने उन्हें टेम्परेरी डिक्लेअर नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—टेम्परेरी डिक्लेअर करने का सवाल नहीं पैदा होता। केवल रसद विभाग के लिये तय किया गया था कि टेम्परेरी रहेंगे।

श्री चांदमल मेहता—रसद विभाग के लिये वह रहेंगे, क्या यह उस बोर्ड ने तय किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के ऑर्डर्स निकले थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गज़ट में जो उनके नाम निकले हैं उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गवर्नमेंट के ऑर्डर निकल गये थे।

श्री चांदमल मेहता—पहले गजट में प्रकाशित हुआ या गवर्नमेंट के ऑर्डर पहले निकले ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से ही गजट में प्रकाशित होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सप्लाई विभाग के लिये ही एस. ए. एस. को टेम्परेरी गिना जायगा, ऐसे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह दूसरी जगह होंगे तो उनकी सब्स्टेन्टिव पे (Substantive Pay) निर्धारित करने के लिये यह किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिनकी कई वर्षों की सर्विस है और जो दूसरे विभागों से इधर ट्रान्सफर हो कर आये हैं वे भी इसी में हैं।

श्री सुखाड़िया—इनको अलग अलग नहीं किया है इसमें।

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आर. ए. एस. के. सिलेक्शन में सभी विभाग के जो भी हैं उन सबको परमानेन्ट गिना गया है और एस. ए. एस. में सप्लाई विभाग के लोगों को परमानेन्ट नहीं गिना गया है, यह दुतरफा नीति क्यों अपनाई गई है।

श्री सुखाड़िया—आर. ए. एस. का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें सभी परमानेन्ट डिपार्टमेंट्स के हैं और एस. ए. एस. में जो सप्लाई विभाग के टेम्परेरी हैं वे भी हैं।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह सही है कि आर. ए, एस. का सिलेक्शन करते वक्त सभी विभागों में जो काम करने वाले ऑफिसर्स थे उन्हें सब्स्टेन्टिवली अपॉइन्टमेंट देकर परमानेन्ट गिना गया, इसी तरह एस. ए. एस. के लिये भी रखा गया है ?

श्री सुखाड़िया—इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

श्री एच. के. व्यास—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ओरिजिनल जो नोटिस गजट में शाया हुआ था उसमें सब्स्टेन्टिव अपॉइन्टमेंट का जिक्र था, टेम्परेरी का नहीं ?

श्री सुखाड़िया—जहां तक सप्लाई विभाग का प्रश्न है अलग से किया गया है।

श्री एच. के. व्यास—एस. ए. एस. का सिलेक्शन किसी विभाग के लिये नही सारे सरकारी विभागों के केडर के लिये किया गया है।

श्री सुखाड़िया—यह प्रश्न ही जवाब में आ जाता है।

श्री एच. के. व्यास—तो फिर सप्लाई विभाग के लोगों के लिये यह सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है ?

श्री सुखाड़िया—क्योंकि वे टेम्परेरी थे और पर्मानेन्टली एब्ज़ोर्ब करने के लिये तय करना था।

श्री एच. के. व्यास—क्या दूसरे विभागों के सबोर्डिनेट लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया है ?

श्री सुखाड़िया—आमतौर से सारे विभागों के लिये इन्हें टैम्परेरी कर दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है; सप्लाई डिपार्टमेंन्ट में रहें तभी तक के लिये है। दूसरे डिपार्टमेंन्ट में जायं तो सब्स्टेन्टिव पे क्या रहे, इसके लिये यह तय किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एस. ए. एस. में जो सिलेक्ट हो गये हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंन्ट्स में लोअर डिविजन क्लर्क के तौर पर भेजा जा रहा है ?

श्री सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के यह ध्यान में है कि सप्लाई विभाग में इस समय काम करने की वजह से आठ-आठ, नौ-नौ साल के सर्विस वालों की इस सर्विस को गिने बगैर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है ?

श्री सुखाड़िया—ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि इस वजह से एक एक मुलाजिम को ७०-८० रुपयों का नुकसान हो रहा है ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—How can it be replied-

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में है कि बहुत से व्यक्तियों ने अन्डर प्रोटेस्ट तनख्वाह लेना बन्द कर दिया है ?

श्री सुखाड़िया—मेरी जानकारी मे ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर आप बतलाएंगे तो जानकारी प्राप्त की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संबन्ध में लीगल नोटिस दिया है ?

श्री सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूं कि नोटिस दिये गये या नहीं ? बहुत से आदमी जो परमानेन्ट थे और सप्लाई में ट्रान्सफर किये गये उनको भी टेम्परेरी...

श्री सुखाड़िया—ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The Hon,ble Member should seek informaticn rather than give information.

श्री एच. के. व्यास—क्या अखिल भारतीय कर्मचारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने इस संबन्ध में कोई प्रार्थनापत्र पेश किया है ?

श्री अध्यक्ष—What is the use of it.

श्री एच. के. व्यास—All these points have been covered in that Memorandum. The Hon'ble Member Does not know?

श्री अध्यक्ष—But look to the scope of this question ?

श्री एच. के. व्यास–There is an all India organhization of the civil supplies Employees and they have submitted a Memorandum to the Government which the government are expected to know.

श्री अध्यक्ष—But this is information that the Hon'ble Member is giving.

श्री सुखाड़िया—The question relates to the S. A. S. and not to All India Associations.

श्री एच. के. व्यास—That relatee to the retrenchment and non-absorption of the employees of the civil supplies Dept.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २.

ग्राम नरवर, तहसील किशनगढ़ में गश्त गिरदावरी की स्लिपों का किसानों में वितरण

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम नरवर, तहसील किशनगढ़ में गश्त गिरदावरी की स्लिपें किसानों को वक्त पर नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) किसानों ने इस संबन्ध में कितने प्रार्थनापत्र किस-किस तारीख को तहसीलदार, एस. डी. ओ, किशनगढ़ व कलेक्टर, जयपुर के पास दिये व उन पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री)

(१) जी नहीं । ग्राम नरवर में गश्त गिरदावरी की स्लिपें सबकी समय पर दे दी गई, सिवाय तीन खातों के जिनके बारे में तनाजा था ।

(२) काश्तकारों में आपस में तनाजा होने के कारण गश्त गिदावरी की स्लिपें समय पर नहीं दी गई ।

(३) इस संबन्ध में ६ प्रार्थनापत्र तहसीलदार के पास पेश हुये ।

(४) इनका विवरण इस प्रकार है:—

[श्री दामोदर व्यास]

प्रार्थी का नाम	तारीख	कार्यवाही
१—भीमा जाट) दाना जाट)	२३–१०–५४	तहकीकात के पश्चात् भीमा जाट की स्लिप देने का आदेश हुआ।
२—भंवरलाल	१२–७–५४	तीनों आसामीयान एक जमीन की स्लिप चाहते हैं। इसकी तहकीकात जारी है।
३—नाथूसिंह	२२–१०–५४	
४—पन्ना रावत	८–११–५४	
५—पन्ना रावत	२२–१०–५४	२३–१०–५४ को लालू रावत की स्लिप देने के आदेश हुये।
६—लालू रावत	२२–१०–५४	

(५) जी नहीं।

(६) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—गश्तगिरदावरी कब हुई और स्लिपें कब तकसीम हुई, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब स्लिपें तकसीम हुई उसी वक्त; पहले गिरदावरी हुई और स्लिपें तकसीम हुई।

श्री चांदमल मेहता—गश्त गिरदावरी के साथ-साथ ही स्लिपें तकसीम हुई, मगर मेरा प्रश्न है कब ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब गश्त गिरदावरी हुई।

श्री चांदमल मेहता—मैं तारीख चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं तारीख तो नहीं बता सकता।

(श्री श्री दास गोयल खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—जब एक सदस्य खड़े हों तब दूसरे सदस्य को नहीं बोलना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—क्या हर एक खेत की गिरदावरी होती रही, उसी वक्त उसके साथ-साथ स्लिपें भी देते रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास—जब गश्त गिरदावरी एक गांव में खतम हुई तब स्लिपें देदी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या गश्त गिरदावरी की स्लिपें देने की रसीदें कास्तकारों से ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर ली जाती होगी तो ली गई होगी, इस संबन्ध में ठीक नहीं बता सकता।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रकार का आदेश होते हुए भी काश्तकारों से उसकी रसीदें नहीं ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर ऐसा आदेश है तो जरूर ली गई होगी। अगर किसी गांव में नहीं ली गई, अगर आप बतावेंगे तो मैं जांच करूंगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनसे रसीदें ले ली गई हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर ली गई होंगी।

श्री चांदमल मेहता—"ली गई होंगी" नहीं पूछना चाहता। ली गई या नहीं, यह डेफिनिट रिप्लाई चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—गश्तगिरदावरी क्या चीज होती है ?

श्री चांदमल मेहता—बहुत सारे नाम, जो लिस्ट दी गई है, उसमें छोड़ दिये गये हैं, जैसे छीतर जाट वगैरह।

श्री दामोदरलाल व्यास—जिनकी गश्त गिरदावरी रोकी गई उनके नाम बताये जा चुके हैं।

श्री चांदमल मेहता—छीतर जाट ने इसके लिये अन्डर पोस्टल सर्टीफिकेट (पोस्टल सर्टीफिकेट के द्वारा) शिकायत की है कि उसकी गश्त गिरदावरी की (Slips) नहीं मिली।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३

किशनगढ़ तहसील में नगदी लगान के निश्चित होने पर ग्राम पाटन व चुलीं में लटाई।

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में नगदी लगान मुकर्रर होने के बाद भी ग्राम पाटन और चुलीं में लटाई की गई ?

२. यदि हां, तो उक्त लटाई किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को की गई ?

३. उक्त ग्रामों में लटाई होने के क्या कारण हैं ?

४. क्या यह सही है कि लटाई का अनाज सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ ?

[श्री चांदमल मेहता]

५. उक्त ग्रामों की लटाई के कागजात किस किस ऑफिसर के खिलाफ हैं और कितने अर्से से किस महकमे ने दबा रखे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री)

१. जी नहीं।

(२) (३) (४) (५)—ये प्रश्न नहीं उठते।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार की जानकारी में है कि इस सदन में पहले ऐसा जवाब दिया गया है कि लटाई की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह की रिपोर्ट में बताने पर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य।

श्री चांदमल मेहता—क्या सदन की कार्यवाही से अवगत होने का सरकार प्रयत्न करेगी।

श्री अध्यक्ष— That is Presumed.

श्री एच. के. व्यास—Then why he says, he does not know ?

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक डी. ओ. लेटर से यह मांग की गई थी कि इसकी जांच की जावे ? उस पर यह हुक्म हुआ था कि कलेक्टर जयपुर उसकी जानकारी करके रिपोर्ट पेश करे।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है, जानकारी प्राप्त करके बताया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४

राजस्थान निर्माण विभाग के ओवरसियरों के पास मोटरें।

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने ओवरसियर हैं ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) उक्त ओवरसियरों में से कितनों के पास अपनी निजी मोटरें हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मोटरें उन्होंने ओवरसियर बनने के बाद खरीद की हैं ?

(४) क्या सरकार की तरफ से उन्हें कोई मोटर एलाउन्स दिया जाता है ?

(५) यदि हां, तो कितना ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कुल १७६ ओवरसियर हैं।

२. उक्त ओवरसियरों में से छः के पास निज की मोटरें हैं।

३. ६ ओवरसियरों में से ५ ओवरसियरों ने ये मोटरें ओवरसियर बनने के पश्चात् खरीद की हैं और एक ओवरसियर ने, जब वे एसिस्टेन्ट इन्जिनियर के पद पर बराबर ४-५ साल तक कार्य कर रहे थे, तब मोटर खरीद की थी। वह ही इस समय उनके पास मौजूद है।

४. नहीं, सिर्फ नियमानुसार टी. ए. मिलता है।

५. प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब मंत्रीगण भी मोटर मेन्टीनेन्स का खर्चा नहीं उठा सकते तो ओवरसियर उसका खर्चा कैसे उठाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मंत्री गण......

श्री चांदमल मेहता—मोटरों पर इतना खर्चा होता है कि मंत्री भी सरकारी मोटरें रखते हैं।

श्री अध्यक्ष—But this relates to over-seers

श्री चांदमल मेहता—मंत्रीगण भी मोटर का खर्चा...

श्री अध्यक्ष—Come to the relevant scope of the question.

श्री चांदमल मेहता—क्या मोटर मेन्टेन करने में वे अपने पॉकेट से खर्च करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—बहुत से आदमी अपनी मोटर रखते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—उनको तनख्वाह क्या मिलती है ?

श्री एच. के. व्यास—गवर्नमेंट सर्विस कन्डक्ट रूल्स के मुताबिक जितनी प्रोपर्टी है उसका स्टेटमेंट उन्होंने सरकार के पास पेश कर दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—जरूर कर देना चाहिये।

श्री एच. के. व्यास—कर देना चाहिये, यह दूसरी बात है। आपको इस बात की जानकारी है या नहीं कि उन्होंने स्टेटमेंट पेश कर दिये या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—पेश कर देने चाहिये। It is a separate question.

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार ने इस बात की जांच करने की कोशिश की कि ऐसे स्टेटमेंट ओवरसियरों द्वारा पेश किये जाने जरूरी है या नहीं।

(चुप्पी)

After you received this question; at least after that did the Government make any effort to find out whether these over-seers have been submitting such statements or not?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—They have been submitting.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्टेटमेन्ट्स में उन मोटरों की खरीद का उल्लेख है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—क्या कहा आपने?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मोटरें जो सर्विस के बाद खरीदी गई है, उनका उल्लेख उन (स्टेटमेन्टस) में है या नहीं?

श्री गुप्त—होना चाहिये। मैंने कहा कि यह सेपरेट सवाल है कि गवर्नमेन्ट कन्डक्ट रुल्स के अनुसार उन्होंने स्टेटमेन्ट्स दिये या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने अभी बताया था कि दे देते हैं।

श्री गुप्त—स्टेटमेन्ट देते हैं या नहीं, यह सेपरेट सवाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने कन्डक्ट रूल्स (Conduct Rules) के मातहत स्टेटमेन्ट जो सब्मिट किये हैं उनके द्वारा उनकी आर्थिक उन्नति कितनी तेज रफ्तार से हुई है?

How much property they succeeded in a short period of five or six years?

श्री गुप्त—मैंने आपसे कहा है कि…

श्री अध्यक्ष—But this is not within the scope of the question. I allow every latitude to ask supplementaries but that should be within the scope of the question.

Page No.11

श्री हरिकृष्ण व्यास—This can be inferred from the question. The intention of the Hon' ble Member is to point out that no paid employees of the government service are expected to acquire property at such quick rate thereby raising some doubt about their integrity. Therefore, I think that the answer to the question can only be complete if all these details are given.

श्री अध्यक्ष—If the Hon' ble Minister says that a saparate question should be tabled, then the Hon' ble Member is entitled to table a separate question The Hon' ble Member may reply on the floor of the House but prima facie this is beyond the scope of the question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to know-Is the Hon' ble Member incharge in a position to reply regarding their financial position as he made the statement ?

श्री गुप्त—I may be in such a position after enquiry, this is what I have submitted already.

श्री चान्दमल मेहता—कौन कौन हैं साहब ये ?

श्री अध्यक्ष—यदि माननीय मंत्री अभी जवाब दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—इन ओवरसियर्स के नाम क्या हैं ?

श्री गुप्त—एक हैं श्री माधोदास, ये निर्माण विभाग के इसी दफ्तर में लगे हुए हैं। दूसरे हैं मोहम्मद हामी, ये जयपुर के निर्माण विभाग में लगे हुए हैं। तीसरे हैं श्री भंवरलाल, ये भी यहीं पर लगे हुए हैं। चौथे हैं श्री चुन्नीलाल, ये भी यहीं लगे हुए हैं। पांचवे है श्री कुंजबिहारीलाल, ये सिटी डिविजन जोधपुर में हैं। एक हैं मि० त्यागी जो उदयपुर में लगे हुए हैं। I think he (Shri Vedpal Tyagi) must be knowing this. (हंसी)

श्री त्यागी— I know he was an Assistant Engineer and since then he is owning this car.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि बड़े २ केपिटल शहरों में रहने वाले ओवरसियर्स को ही इस तरह की सुविधा प्राप्त है ?

श्री गुप्त मंत्री—यह कोई सुविधा नहीं है, गर्वन्मेन्ट की ओर से सुविधा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या गर्वन्मेन्ट ने पता लगाने की कोशिश की कि मोटरों की खरीद का बड़े स्थानों में रहने से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री गुप्त—कोई सम्बन्ध नहीं है।

Page No.12

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार एक्सपेरिमेन्टल मेज़र्स के तौर पर उनको इस प्रकार के स्थानों में भेज कर जहां कि आमदनी का जरिया उतना नहीं है जितना कि बड़े शहरों में होता है, पता लगायगी ?

श्री गुप्त—आमदनी के जरियों का सवाल नहीं है ।

श्री चान्दमल मेहता—क्या ओवरसियर्स ओवरसियरी के सिवाय और कोई दूसरा धन्धा करते है ?

श्री सार्वजिनक निर्माण सचिव—यह दूसरा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ६

वर्तमान वर्ष में वर्क एजेन्ट ओवरसीयरों की नियुक्ति

श्री चान्दमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) चालू वर्ष में कितने वर्क एजेन्ट (Work Agent) ओवरसियर बनाये गये ?

(२) उक्त व्यक्तियों की योग्यतायें क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—(सार्वजनिक निर्माण मंन्त्री)

(१) इस विभाग ने चालू वर्ष में केवल २६ वर्क एजेन्टों को ओवरसियर के पद पर नियुक्त किया है । इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर जूनियर ओवरसियर के पद पर की गई है ।

(२) उक्त व्यक्तियों में से १८ व्यक्तियों ने विभिन्न इन्जीनियरिंग विद्यालयों व संस्थाओं से ओवरसियरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा ११ व्यक्ति केवल कार्यानुभवी हैं ।

श्री चान्दमल मेहता—यह सिलेक्शन किसके द्वारा किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—६ महीने का टेम्परेरी एपोइन्टमेन्ट किया है । फिर ये परसन्स पी. एस. सी. में जायगे । ६ आदमी ऑलरेडी एप्रूव हो चुके हैं ।

श्री चान्दमल मेहता—क्या कोई आवेदन पत्र मांगे गये थे ?

श्री गुप्त—आवेदन पत्र तो आते रहते है । क्वालिफाइड होते है उसी बेसिस पर चीफ इन्जीनियर अपॉइन्टमेन्ट करते हैं ।

श्री चान्दमल मेहता—किस ऑथोरिटी ने उनको वर्क एजेन्ट से ओवरसियर का प्रोमोशन देने का काम किया है और किस आधार पर किया ?

श्री गुप्त—मैंने बताया कि चीफ इन्जीनियर करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसके पीछे आधार क्या था, उन्हीं का क्या किया ? दूसरे आदमी नहीं मिलते हैं ?

श्री गुप्त—हमें आदमी मिलते नहीं हैं। जो मिलते है उनको हम रख लेते हैं।

श्री शंभूसिंह—वर्क एजेन्ट बोनाफाइड राजस्थानी कितने हैं ?

श्री गुप्त—यह अलग से सवाल पूछें।

श्री श्रीदास गोयल—चीफ इन्जीनियर ने सिलेक्शन किया तो क्या प्रोसिजर अख्तियार किया ?

श्री गुप्त—हमारे यहां वर्क एजेन्ट काम करते हैं, टेम्परेरी फॉर सम टाइम (कुछ समय के लिये) रखे जाते हैं। उस बेसिस पर फिर प्रोमोशन दिया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या चीफ इन्जीनियर के डिपार्टमेन्ट में वर्क एजेन्ट के रेकर्ड का बाकायदा रेकर्ड रखा जाता है ?

श्री गुप्त—क्वालिफिकेशन का रेकर्ड रखा जाता है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या क्वालिफिकेशन जो कुछ है उनको मानते हुए ये सिलेक्शन्स किये गये ?

श्री गुप्त—६ आदमी पी. एस. सी. से सिलेक्ट हो चुके हैं। ६ आदमी टेम्परेरी रखे गये हैं, जो पी. एस. सी. में आवेंगे। वे एप्रूव करेंगे तब फिर पर्मानेन्ट करेंगे। ये टेम्परेरी पोस्ट्स हैं और उनको उन पर लगाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—Next Question No. 5

प्रश्न संख्या ५

श्री चान्दमल मेहता—मैं नहीं पूछना चाहता।

श्री अध्यक्ष—The Questions are now over.

सदन की मेज पर रखे गये पारित विधेयक

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)—Sir. I lay on the table a statement showing the Bills which were passed by the Assembly and have been assented to either by the President or by His Highness the Rajpramukh.

Bills assented to by His the President—

1. The Rajasthan Sales Tax Bill, 1954.

[श्री मनसाराम पुरोहित]

2. The Rajasthan Medical (Amendment) Bill, 1954.

Bills assented to by His Highness the Rajpramukh—

1. The Rajasthan Appropriation (No. 4) Bill, 1954.

2. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Bill, 1954.

3. The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Second Amendment Bill, 1954.

4. The Rajasthan Colonisation Bill, 1954.

5. The Rajasthan Local Fund Audit Bill, 1954.

6. The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications)Amendment Bill, 1954.

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश

श्री अध्यक्ष—Ordinances to be laid,

राजस्थान खाधान्न (अनुज्ञापन एवं प्राप्ति) अध्यादेश, १९५५.

श्री भोगीलाल पण्ड्या (उद्योग एवं खाद्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व सत्र के पश्चात् एवं वर्तमान सत्र के प्रारम्भ के पूर्व प्रख्यापित राजस्थान खाद्यान्न (अनुज्ञापन एवं प्राप्ति) अध्यादेश, १९५५. की एक प्रति विधान सभा के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ ।

राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण अध्यादेश, १९५५.

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदरलाल व्यास ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—मैं पूर्व सत्र के पश्चात् तथा वर्तमान सत्र के प्रारम्भ के पूर्व प्रख्यापित राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण अध्यादेश, १९५५ की एक प्रति विधान सभा के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यादेश, १९५५

श्री भोगीलाल पण्ड्या (उद्योग एवं खाद्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व सत्र के पश्चात् एवं वर्तमान सत्र के प्रारम्भ के पूर्व प्रख्यापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यादेश, १९५५ की एक प्रति विधान सभा के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ ।

अंकेक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष—श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, में एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १९५१.५२ तथा ऑडिट रिपोर्ट १९५३ की एक प्रति सदन के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, में फाइनेन्स अकाउन्ट्स १९५१.५२ तथा ऑडिट रिपोर्ट १९५३ की एक प्रति सदन के सन्मुख प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री राम निवास मिर्धा ।

राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, १९५१ के अन्तर्गत गृह विभाग की विज्ञप्तियें

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर बेहिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसरण में राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, १९५१ में संशोधन करने वाली निम्नलिखित विज्ञप्तियों की एक प्रति विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं:

(१) गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १० (५) १/गृह २/T/५२ दिनांक १२ नवम्बर, १९५४, तथा

(२) गृह विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ १० (५) ६ गृह २/५३ दिनांक ८ जनवरी, १९५५.

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Sir. I Present the first Report of the Estimates Committee 1953-54 on General Abministration-

राजस्थान सामान्य खण्ड विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जनरल क्लॉजेज बिल, १९५४ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष—श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर वादविवाद । श्री गुलाबचन्द कासलीवाल धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय अध्यक्ष, चालू वर्ष में की गई प्रगति पर विचार करके ही हम आगामी वर्ष की नीति का निष्कर्ष निकाल सकते हैं । इसीलिए यह परम्परा स्थापित की गई है कि राजप्रमुख का भाषण सदन के समक्ष हो और उस पर हम विचार करें । राजप्रमुख के भाषण में बहुत लम्बे-चौडे आंकड़े बताकर जो प्रगति की गई है उसका संक्षेप में वर्णन किया गया है और

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

आगामी वर्ष में हमारी क्या पॉलिसी होगी उस ओर भी संकेत किया गया है। इन तथ्यों का विश्लेषण करने से राजकीय कार्यों से न केवल सन्तोष ही होता है बल्कि अपार हर्ष का अनुभव होता है।

सब से प्रथम तो में राजप्रमुख को अपनी राजकीय एवं मातृभाषा हिन्दी को अपनाने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ (हर्ष ध्वनि) इस सदन ने राजप्रमुख के इस कदम पर करतल ध्वनि करके अभिवादन किया और अपने हर्ष को प्रदर्शित किया है। मुझे इस तरह अपार आनन्द और हर्ष का अनुभव होता है। संविधान के अनुसार हमारी सरकार एक कल्याणकारी राज्य की ओर लक्ष्य करके आगे बढ़ना चाहती है। इस वर्ष सरकार ने जितनी उन्नति की है राजकीय कार्यों को जिस रूप में संपादित किया है उनको देखकर मुझे सन्तोष ही नहीं, बल्कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि और प्रदेशों के मुकाबले में हम गर्व से अपना मस्तक ऊँचा कर सकते हैं।

अतीत में हमारा प्रदेश शूरवीरता के लिये अग्रगण्य था। भारत के मानचित्र में आज हम जो कार्य कर रहे हैं उससे कुछ ही दिनों में हम गर्व से यह कह सकेंगे कि अन्य राज्यों की प्रगति के मुकाबले हमारी प्रगति कहीं ऊंची है।

इस वर्ष जो जो बड़ी-बड़ी योजनायें की गई हैं जिसका विवरण संक्षेप में राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया है उनमें से मुख्य भाखरा-नांगल की योजना है जो हमारा प्रधान कार्य था। इस नहर से पानी आता हुआ देखकर राजस्थान प्रान्त का ऐसा कौन निवासी है जो खुशी से न फूला हो। विशेषकर इस मरु-प्रदेश के किसानों के फीलिंग्ज़ को, उनकी आशाओं को जो एक बार भी यह नहीं सोच सकते थे कि उनके यहां कभी पीने के पानी की बहुतायत होगी बल्कि आज इस नहर से उस प्रदेश में लहलहाते खेत खड़े हैं। आज वहाँ का किसान न केवल अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण ही कर सकता है बल्कि अपने परिवार के अलावा हमारे प्रान्त को समृद्धिशाली बना रहे हैं।

चम्बल घाटी योजना का भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे यहां होने जा रहा है। जिस रूप में इस चम्बल घाटी योजना की प्रगति हो रही है उससे मुझे न केवल सन्तोष का ही अनुभव होता है बल्कि मुझे यह पूर्ण आशा है कि वह निर्धारित समय के भीतर ही पूर्ण हो जायगी। इसके पूर्ण होने से एक बहुत बड़े भाग में उससे पानी और बिजली प्राप्त हो सकेगी। बिजली हमारे लिये नितान्त आवश्यक वस्तु है। हमारा प्रदेश आज औद्योगिक विकास की देहली पर खड़ा हुआ है, उसके लिये बिजली का पर्याप्त मात्रा में मिलना आवश्यक है। उसके बिना हम औद्योगीकरण नहीं कर सकते। चम्बल घाटी योजना इस बिजली की मांग की बहुत बड़े अंश में पूर्ति करेगी।

तीसरा बड़ा कार्य जवाई बान्ध का है जो करीब करीब समाप्त हो चुका है। उसमें केवल थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। यह भी एक ऐसे स्थान पर है जो मरुप्रदेश है। जवाई बांध जोधपुर से करीब १०० मील दूर मरू प्रदेश में है। वहां पर एक ऐसी योजना का बनाया जाना और उसको कार्यान्वित कर देना, यह सरकार के लिये धन्यवाद का ही नहीं बल्कि इस प्रदेश की जनता के बहुत बड़े दुख को दूर करने वाला कार्य है।

Page No.17

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

इन तीनों योजनाओं से हमारे प्रदेश की जो उन्नति होने जा रही है वह इतनी बड़ी चीज हो रही है कि जिसको हम केवल आंकड़ों से नहीं आंक सकते। इससे न केवल हमारा प्रदेश धन धान्य से ही समृद्ध होगा, न केवल औद्योगीकरण का विकास ही होगा बल्कि आम तौर पर जितनी उन्नति होगी उसका कोई पैमाना नहीं है।

विश्व के अन्य प्रदेशों में भारत ही एक ऐसा देश है जो सड़कों में पिछड़ा हुआ है और उसमें भी हमारा प्रान्त बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए चालू वर्ष में ७०० मील लम्बी-चौड़ी सड़कें बनायी जाकर हमारे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में यातायात के प्रबन्ध किये गये हैं। जहां हमारे प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, जहां मार्ग बिल्कुल नहीं है, रेल के यातायात बिल्कुल अपर्याप्त है वहां सड़क ही ऐसा जरिया है जिससे हम प्रदेश के कोने कोने में पहुँच सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सड़कों के बनाये जाने पर सरकार न केवल आगामी वर्ष में ही पैसा व्यय करेगी बल्कि आगामी पंचवर्षीय योजना में भी इसको स्थान देगी।

रेल मार्गों के लिए अभी अभी हम लोगों ने सुना है कि एक छोटा सा टुकड़ा फतहपुर से चूरू तक बनाया जाने वाला है। आगामी पंचवर्षीय योजना के लिए हम यह पढ़ रहे हैं कि इस अगली स्कीम में रेल-विस्तार के लिए बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार खर्च करने जा रही है। मुझे आशा है कि हमारी सरकार, भारत सरकार को इस प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करने के लिए तैयार कर सकेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार के दबाव से भारत सरकार, रेल मार्गों के अतिरिक्त और मार्ग भी हमारे प्रदेश में बनावेगी।

राजस्थान प्रदेश के बनने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या कानून और व्यवस्था की हमारे सामने उपस्थित हो गई थी। हजारों डाकू मालूम नहीं कहां से पैदा हो गये और किन कारणों से पैदा हो गये। इसका अन्वेषण करना तो इस समय आवश्यक नहीं, परन्तु हमारे प्रदेश में, यह सच है कि कुछ हिस्सों में यह महसूस सा होने लग गया था कि जैसे कोई सरकार है ही नहीं, वहां की जनता ने अपना आत्म-विश्वास खो दिया था। इस बारे में पिछले वर्षों में जो प्रगति की गई है उस पर विचार करने और आकड़ों पर सोचने के बाद ऐसा आभास होता है कि हमारी इस सरकार ने इस सारी लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पर सारे प्रदेश में पूरी तौर से काबू कर लिया है। बड़े बड़े जुर्मों में बहुत बड़ी कमी हुई है और डाकुओं में जो कमी हुई है वह विशेष उल्लेखनीय चीज है। पर इससे भी विशेष उल्लेखनीय तो है डाकुओं का अपने आप आत्मसमर्पण कर देना, जिसकी स्वप्न में भी आशा हम नहीं करते थे। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी रीति-नीति पर हमेशा आगे बढ़ती चली जावेगी और डाके और लूटमार का हमारे प्रान्त में नाम-निशान भी बाकी नहीं रहेगा।

श्रीमन् राजप्रमुख ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ही तरह से नहीं बल्कि अलग-अलग तरह से हम प्रगति कर रहे हैं। सैकन्डरी एजुकेशन, टैकनीकल एजुकेशन, इन्डस्ट्रियल एजुकेशन और पुस्तकालयों के द्वारा जनजागृति और जनता को शिक्षित करने की ओर हम प्रगति कर रहे हैं। मुझे साथ ही यह जानकर बड़ा सन्तोष हुआ कि सरकार के सामने एक ऐसी बड़ी स्कीम है जिसके जरिये

[श्री गुलाब चन्द कासलीवाल]

से सेन्ट्रल लाइब्रेरी और डिविजनल लाइब्रेरियां और सारे जिलों के पुस्तकालयों की स्थापना से जन शिक्षा का काम हाथ में लिया जा रहा है। यह भी बताया गया कि हरेक ग्राम में पहुंच सकने के लिए मूविंग पुस्तकालयों की स्कीम भी सरकार कार्यान्वित करने जा रही है। छोटे-छोटे गांवों तक में शिक्षा की यह ज्योति इन चलते-फिरते पुस्तकालयों द्वारा पहुंचाने का प्रयास अवश्य ही बहुत प्रशंसनीय है और साथ ही कठिन भी बहुत है लेकिन ऐसे कठिन काम की ओर भी सरकार मजबूती से कदम बढ़ा रही है। इस माने में भी यह बहुत ही धन्यवाद की पात्र है।

इस शिक्षा के अतिरिक्त हमें यह भी बताया गया है कि इन्डस्ट्रियल एक्सपेन्शन (industrial expension) पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सच्ची बात तो यह है कि जब तक हम अपने इस प्रदेश के भूगर्भ में छिपे अतुल कच्चे माल को बाहर न निकाल लें तब तक हमारी इस दिशा में उन्नति हो नहीं सकती। हमारे प्रदेश में इसकी कमी नहीं है। सारे अरावली पहाड़ों में जहां—तहां अनेकानेक बड़ी बड़ी खानें दबी पड़ी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पर और भी अधिक ध्यान दें और इसका पर्याप्त फायदा उठावें। इस ओर भी बहुत बड़े कदम उठाये जा रहे हैं। यह बताया गया है कि सिन्दरी फेक्टरी को तो हम ऑलरेडी (already) बहुत बड़ी मात्रा में जिप्सम (gypsum) यहां से भेजते हैं। यह भी बताया गया है कि हम इस जिप्सम का उपयोग और दूसरे प्रोडक्ट्स (Products) का उपयोग अपने यहां फर्टीलाइजर (fertilizer) की फेक्टरी बनाकर काम में लावेंगे। यह फेक्टरी यहां राजस्थान में बन जाने से यहां की किसान जनता के लिए बहुत बड़ी राहत हो जावेगी और उनको पर्याप्त मात्रा में, आसानी से, कम दामों में खाद मिल जाने से पैदावार की उन्नति भी बहुत हो सकेगी।

इसी तरह से अन्य खनिज पदार्थों के लिए भी बारबार कोशिश की जा रही है और आशा है कि बहुत ही शीघ्र अन्य बड़ी–बड़ी खानों पर काम शुरू हो जावेगा। इसमें यह जरूर है कि समय लगता है और पैसा भी। अन्वेषण करने में भी समय लगता है और इसके बाद काम शुरू करने में भी समय लगता है। पर सरकार जिस तरह से इस काम में दिलचस्पी ले रही है उससे हम पूरी–पूरी आशा कर सकते हैं कि बहुत जल्दी हम माइनिंग (mining) के काम में भी तरक्की कर जावेंगे।

श्रीमन् राजप्रमुख ने ४० पैरों (paras) के लम्बे भाषण में अलग अलग बातों पर प्रकाश डाला है। इस पर विवेचना करना बहुत लम्बा–चौड़ा काम है। फिर भी एक दो और बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एग्रीकल्चर के विस्तार के लिए जो अलग २ कदम उठाये जा रहे हैं उनमें सबसे पहले तो कदम उठाया गया था वह है लैण्ड रिफार्म्स और जागीरदारी एबोलिशन की दिशा में। सरकार को इस महान् कार्य के सम्पादन में जो कदम उठाने पड़े उसकी श्रीमन् राजप्रमुख ने तारीफ और सराहना भी की। मैं उससे भी ज्यादा सराहना करने के लिए तैयार हूं और आपके सामने इसके लिए उपस्थित हूं। जागीरदारी का प्रश्न जिस शान्त वातावरण में हल कर लिया गया है उस शान्ति से और उस वातावरण में और प्रदेशों में कहीं नहीं हो पाया है। यह जरूर है कि कुछ रिट पिटीशनें (Writ petitions) सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और उनकी सुनवाई आजकल हो रही है। आशा है कि वे भी बहुत जल्दी ही फैसल हो

[श्री गुलाब चन्द कासलीवाल]

जावेगी और सरकार के इस ओर कदम बढ़ाने में जो थोड़ी बाधा उपस्थित हो गई थी वह भी दूर हो जावेगी। इसके बावजूद भी सरकार ने ५०० जागीरों को ले लिया है यह बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। इससे उन जागीर प्रदेशों में रहने वाली जनता को राहत मिलेगी और इससे उनको भूमि समस्या का हल होगा। जागीरों के अतिरिक्त और हिस्सों में जो कृषक की समस्या भूमि की है उसको हल करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। भूमिहीन किसानों को भूमि देना सरकार का परम कर्त्तव्य है और जितनी भी बेकार मैन पॉवर (Man power) है उसको पूरा पूरा काम देना बहुत जरूरी है जिसके लिए सरकार हर तरह से सतर्क है। इसके बिना हम किसी तरह का अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सरकार इस दिशा में बराबर कदम आगे बढ़ा रही है।

साथ ही बड़ी सन्तोष की बात है कि एग्रीकल्चर की उन्नति के लिये भी सरकार पूरा-पूरा ध्यान दे रही है जिसकी बड़ी आवश्यकता है। एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए पशुबल पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए सरकार द्वारा वेटेरिनरी कॉलेज जहां तहां खोले गये हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। वेटेरिनरी (Veterinry) से ही काम नहीं चलता। गांव-गांव में किसान को इसकी उपयोगिता के बारे में पूरी-पूरी जानकारी देना भी नितान्त आवश्यक है। सरकार को इसके लिए काफी प्रोपेगेन्डा (propaganda) करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रोपेगेन्डा पर भी ध्यान देगी।

इसके अतिरिक्त नेशनल एक्सटेन्सिव सर्विसेज़ जिस पर कि राजस्थान तथा भारत सरकार काफी जोर दे रही है, वह भी एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इस समय तो राजस्थान में करीब-करीब १/५ भाग में नेशनल एक्सटेन्सिव सर्विसेज ब्लॉक्स (राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड) खुल गये हैं, बाकी ४/५ भाग में से बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि जिनको हमें अपने विचार में करीब-करीब छोड़ देना ही पड़ेगा। वह हिस्से हमारे पश्चिम के रेतीले मैदान हैं जहां कि आबादी करीब करीब नहीं के बराबर है और उनको छोड़ देने के बाद, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही सारे राज्य भर की कुल भूमि नेशनल एक्सटेन्सिव सर्विसेज ब्लाक्स (राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड) के अन्दर आ जायेगी। यह काम पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा, इसमें मुझे कतई सन्देह नहीं है, कोई संशय नहीं है।

और छोटे-मोटे कार्य, अर्थात् टेकनिकल ट्रेनिङ्ग सेन्टर्स, नेशनल केडेट कोर इत्यादि और किये जा रहे हैं। यहां स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ उन्नति की जा रही है, उनमें बी० सी० जी० कम्पेन तथा एन्टी मलेरिया यूनिट्स आदि की भी सन्तोषजनक प्रगति है।

गत कुछ महीनों में जो विशेष तौर से प्रगति की गई है वे भी उल्लेखनीय हैं। उनकी एक विस्तृत जानकारी तो आपके सामने उपस्थित करना बेकार सा है क्योंकि प्रत्येक दिन हम उस प्रगति को देख रहे हैं। इस वर्ष भर में जितने भी कार्य किये गये हैं उनका पर्यवेक्षण करके मैं सन्तोष ही नहीं बल्कि अपार आनन्द का अनुभव करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ कि श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण हमारे सामने दिया था उसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाय। मेरा जो प्रस्ताव है वह इन शब्दों में है :—

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

"आज यहां उपस्थित सदस्य, यह सदन, श्रीमन् राजप्रमुख को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ ।"

श्री खेत सिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे पूर्ववक्ता, जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन् राजप्रमुख ने जो हमारे सामने अभिभाषण दिया था उसमें उन्होंने यह बतलाने का प्रयत्न किया था कि हमारी सरकार ने गत वर्ष में क्या किया और आगामी बजट तक वह क्या करने वाली है । इस अभिभाषण से यह साफ मालूम होता है कि हमारी सरकार दिन प्रति दिन कल्याणकारी कार्यों में और जनहितकारी कार्यों में संलग्न है ।

सबसे प्रथम मैं एक बहुत ही महत्व का कार्य जो कि अब राजस्थान में होने वाला है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; वह है राजस्थान केनाल । सतलज नदी पर बनने वाले बांध, हरीके डेम, से एक नहर राजस्थान के भूभाग में आयेगी और आज जहां पर हमारे यहां ३५० फीट की गहराई पर पानी मिलता है और वह भी खारा, और जहां कि एक प्रतिशत फसल होती है और बाकी सारी जमीन बेकार पड़ी रहती है, जहां सदियों से टिड्डियों के अन्डे पैदा करने के सिवाय और कोई चीज पैदा नहीं होती है हमारी सरकार एक नहर ला रही है और उस नहर से उस इलाके को सरसब्ज बनायेगी । यह हमारे लिये बहुत ही गौरवशाली बात होगी । उस इलाके में इस नहर से करीब करीब ७८ लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी (नोट बुक देखकर) और जिससे ३०,३५ लाख जमीन सिंचित होगी ।

एक सदस्य—एकड़ या बीघा क्या है ? (हंसी)

श्री खेतसिंह—एकड़ ।

(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो जमीन सदियों से बेकार पड़ी रहती थी उसमें स्थान स्थान पर फसलें होंना प्रारम्भ हो जायगा, और जो अभी तक डाकुओं के अड्डे बने हुए रहे हैं, जहां कि टिड्डियां हो पैदा हुआ करती थीं वहां आबादी होना शुरू हो जायगा । वह इलाका वैसा ही हो जायगा जैसा कि आज गंगानगर है । इस नहर से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि चूंकि यह बोर्डर के करीब करीब चलेगी और करीब ४५० मील लम्बी यह नहर होगी और ३००-३५० फीट चौड़ी दरिया की तरह हमारे इस देश में आयेगी जिससे रेगिस्तान जो कि अभी बढ़ रहा है और जो कि उत्तरप्रदेश और मध्यभारत के लिये बड़ा भारी हेवक (havoc) पैदा कर रहा है, उसमें कमी हो जायगी । वह सरसब्ज हिस्सा होने की वजह से जो बीच का रेगिस्तानी इलाका रहेगा उसमें भी बारिश की वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार इस इलाके के सिन्चित हो जाने से राजस्थान की खाद्यान्न समस्या बिलकुल ही मिट जायेगी ।

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा जो कार्य हो रहा है वह भाखरा नांगल का है। भाखरा-नांगल से करीब करीब ७-८ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी और इससे हमारी बीकानेर की कुछ तहसीलें जिनमें खास तौर से सूरतगढ़, हनुमानगढ़, भाखरा आदि हैं उनमें यह नहर आने से यह इलाका बड़ा सरसब्ज हो जायगा, जैसा कि गंगानगर है।

इसके अलावा और भी कई छोटी-छोटी स्कीम्स हमारे यहां हैं। जवाई और चम्बल के मुताल्लिक मेरे पूर्ववक्ता ने काफी कह दिया है। इनके अलावा मोरेल, पार्वती आदि नदियों पर कई ऐसे बांध बनाये जा रहे हैं कि जिनकी वजह से काफी एकड़ जमीन सिन्चित होगी।

इन बड़ी-बड़ी योजनाओं से बिजली में बहुत प्रगति होगी और उन गांवों में जहां कि लालटेन भी नसीब नहीं होती है वहां बिजली नसीब होने लगेगी। वहां का काश्तकार कितना खुश होगा जिस वक्त कि वहां बिजली जायेगी, यह आप अनुमान कर सकते हैं।

थरमल पॉवर स्टेशन कई कई स्थानों पर नये कायम करने की योजना बनी है और मुख्यतया जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, सीकर आदि में यह स्टेशन खोले जायंगे और इनके लिए सामान भी मंगाने के लिए, जहां तक खयाल है, हमारी सरकार ने ऑर्डर्स दे दिये हैं। ज्योंही यह सामान यू० एस० ए० से आ जायेगा यह कर दिया जायेगा।

इसी प्रकार कृषि में हमारी सरकार ने काफी वृद्धि की है। कृषि में केटल ब्रीडिङ्ग फार्म दुर्गापुरा और नागौर में अभी बनाये जा रहे हैं। इनके बनने पर केटल में काफी इम्प्रूवमेंट होगा। इसी प्रकार हमारी सरकार स्थान-स्थान पर पंचायतों को सांड का वितरण कर रही है। किसी भी ग्राम पंचायत को सांड की आवश्यकता हो तो वह ले जा सकती हैं। इस प्रकार गायों की नस्ल इन सांडों के वितरण से बहुत अच्छी हो जायेगी। राजस्थान में नागौर के सांड बहुत महत्व के हैं। यदि उन सांडों को यहां पर गायों का क्रोस ब्रीडिङ्ग कराया जायेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी गायों की नस्ल बहुत सुधरेगी।

इसी प्रकार से सरकार ने एक वेटरनरी कॉलेज बीकानेर में स्थापित किया है। उसमें उसकी ट्रेनिङ्ग दी जायेगी। इससे हमारा पशुधन बढ़ जायेगा, जिसका राजस्थान में सदियों बड़ा महत्व रहा है। यदि पशुधन बढ़ेगा तो काश्तकारों का लिविङ्ग स्टेन्डर्ड भी बहुत अच्छा बन जायेगा।

इसी प्रकार से हमारी सरकार ने एग्रिकलचर कॉलेज भी खोलने की योजना बना ली है और उसको भी एक्सपेन्शन (Expansion) देगी।

इसी प्रकार हमारी सरकार स्थान-स्थान पर डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स पर एग्रिकलचर स्कूल्स भी कायम कर रही है और उन एग्रीकल्चर स्कूलस में नये-नये एपरेटस वगैरह भी देगें जिनकी वजह से हमारे यहां के विद्यार्थी एग्रीकल्चर में पारंगत हो सकेंगे और कृषि की देश में वृद्धि कर सकेंगे।

[श्री खेतसिंह]

हमारी सरकार ने रेवेन्यु के सिलसिले में जो टिनेन्सी बिल पास किया है और जो हाल ही में एक्ट बन चुका है उस पर सारे भारत के अच्छे से अच्छे लेजिस्लेटर्स के क्रिटिसिज्म जो आये हैं उनको देखने से मालूम होता है कि हमारी सरकार ने जितना अच्छा और प्रगतिशील यह कानून बनाया है मेरे ख्याल से उसके जैसा कानून भारत की किसी भी अन्य सरकार ने नहीं बनाया है। हमारी सरकार जमींन का सीलिङ्ग फिक्स करने वाली है। सीलिङ्ग कमेटी काफी पहले बन चुकी है और उसने अपनी रिपोर्ट भी तैयार करली है। ज्योंही उस पर कार्यवाही मुक्कमिल हो जायगी उसके माफिक सीलिङ्ग कायम हो जायगा। खेती की भूमि का वितरण इतने बहतरीन तरीके से हो जायगा कि हर काश्तकार के पास लड़ने योग्य भूमि हो जायगी और कोई भी ऐसा काश्तकार नहीं रहेगा जो लाखों या हजारों बीघा जमीन अपने पास रख सके। इस प्रकार के भूमि वितरण से भूमि-हीन किसान बिल्कुल नहीं रहेंगे।

हमारी सरकार ने सेटलमेन्ट का कार्य भी बड़ी देरी से चलाया है। इतना बड़ा प्रान्त होने पर भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सेटलमेन्ट का कार्य बहुत कम इलाकों में बाकी रहा है और जो इलाके बकाया रहे हैं उनमें भी कोई काश्तकारी झगड़े नहीं थे। जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके जिनमें काश्त की भूमि वैसे ही १ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी उनमें भी हमारी सरकार जल्दी से जल्दी पैमायश का कार्य समाप्त करवायेगी।

इसके अलावा हमारी सरकार ने शिक्षा की ओर भी काफी ध्यान दिया है। यदि आप राज-प्रमुख महोदय के अभिभाषण को देखेंगे तो उससे आपको मालूम होगा कि स्कूलों में शिक्षा की प्रगति हुई है और मेरा जहां तक ख्याल है राजस्थान में एक भी ऐसा गांव नही है जहां कि आबादी २००० से अधिक हो और वहां स्कूल नहीं है। करीब-करीब सभी गांवों में जिनकी आबादी २००० या इससे अधिक है वहां स्कूल खुल चुके हैं और इस वर्ष भी करीब करीब २०० स्कूलें और खुलेंगी और पूरे प्रान्त में शिक्षा का प्रचार काफी हो जायगा। उन गांवों में जहां पहले शिक्षा का नाम भी नहीं था अब वहां पर बच्चे बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं, यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है।

इसके अलावा हमारी सरकार ने उसके पास ज्यादा मीन्स नहीं होते हुए भी जन-स्वास्थ्य की ओर काफी ध्यान दिया है। जगह जगह डिसपेन्सरीज़ खोली गई है। जहां पर डिसपेन्सरीज़ खोलना संभव नहीं था वहां पर आयुर्वेदिक एड पोस्ट खोले गये हैं जिनसे ग्रामीण जनता को चिकित्सा के क्षेत्र में फायदा होता रहेगा।

यदि हम हमारे यहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखें तो मालूम होगा कि आज से २ वर्ष पहले जब हम इस सदन में सम्मिलित हुए थे उस समय हमारे अधिकांश सदस्यों ने कहा था कि चाहे हमारे यहां स्कूलें पहले नहीं खुलें, अस्पताल न खुलें, या जो हैं वे भी बन्द हो जायें लेकिन जैसे भी हो हमारे यहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधरनी चाहिये और हर नागरिक यह सोचने लग जाय कि मैं कभी किसी के द्वारा लूटा नहीं जा सकता या मुझे किसी से किसी प्रकार का डर नहीं है। यदि हम आज की हालत से पहले की हालत की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत में काफी फर्क पड़ा है। एक वह समय था जब डाकुओं के बड़े-बड़े गिरोह थे। भरतपुर,

[श्री खेतसिंह]

धौलपुर आदि में इनके बड़े-बड़े गिरोह थे और शंकर आदि ऐसे ऐसे नाम थे जैसे बड़े-बड़े नेताओं के नाम हो (हँसी) । सब की जुबान पर उसके नाम थे । ये इतने मशहूर हो गये थे, या कहिये इतने नोटोरियस की तौर पर मशहूर हो गये थे·················

श्री हरीकृष्ण व्यास—अपने नेताओं को भी आप इन्ही में शामिल कर रहे हैं ?

श्री खेतसिंह—नेताओं के नाम तो अच्छों में तारीफ के साथ लिये जाते हैं लेकिन उन डाकुओं का नाम **नोटोरियस लोगों में लिया जाता है जैसे आप हैं** । मैं कह रहा था कि अलवर में बनवारी नाम का डाकू था ।

श्री वेदपाल त्यागी—Mr. Speaker, Sir, I object to this sort of language being used for an Hon' ble Member. This is unparliamentary.

(करतल-ध्वनि)

श्री हरीकृष्ण व्यास—No. I am quite willing to take it on, provided the other party will also take it on if needed. .

श्री खेतसिंह—यह आपने कहा है उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं (Mutual exchange) के लिये हमेशा तैयार रहता हूं ।
(To Shri Tyagi)

श्री खेतसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—मैं कह रहा था कि एक जमाना था जब कि अलवर, भरतपुर और जोधपुर में रहने वाले बड़ी मुश्किल में थे । कई महाजनों ने अपने-अपने गांव छोड़ कर शहरों में रहना शुरू कर दिया था । खातूड़ा, बदनसिंह आदि कई ऐसे डाकू थे जिनके नाम से लोग कांपते थे । इनमें से अधिकांश डाकू पकड़ कर समाप्त कर दिये गये हैं । यह बहुत अच्छी बात है । अब दो-तीन गिरोह डाकुओं के और रह गये हैं जिनको हमारी सरकार और गृह मंत्रीजी शीघ्र ही खत्म करने में संलग्न हैं । पुलिस को अच्छी-अच्छी जीपें दी हैं । पहले पुराने रियासती जमाने की जीपें छकड़े जैसी मिली हुई थीं जो ५ मील चलने के बाद खड़ी हो जाती थीं, अब उनके स्थान पर नई जीपें दी गई हैं और नये नये इक्विपमेन्ट्स दिये गये हैं जिनके कारण डाकुओं को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी । हर पुलिस स्टेशन में वायरलेस सेट लगा दिये जायेंगे जिनसे अमन-चैन में बहुत कुछ सुधार हो जायगा । जहां पहले कच्चे झोपड़ों में पुलिस स्टेशन्स थे वहां स्थान-स्थान पर पक्के पुलिस थाने बन रहे हैं, जहां पर मजल लोडिंग गन्स थीं वहां अब थ्री नोट थ्री की रायफल्स दी गई हैं और जगह-जगह ट्रेन्ड आदमी रखे जा रहे हैं । इन सबसे अमन-चैन में काफी सुधार होगा । यही कारण है कि आज हम कल्याणकारी बातें सोच रहे हैं । अब हम यह कह रहे हैं कि हमारे यहां स्कूलें होनी चाहिये, सड़कें होनी चाहिये आदि आदि । हमारी सरकार ने अपने भगीरथ प्रयत्न से सारी समस्याओं को हल कर लिया है ।

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा हमारी सरकार ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी काफी प्रगति की है और करीब ७५० मील सड़कें पक्की बन चुकी हैं। उन इलाकों में जहां देशी-रजवाड़ों के जमाने में कुछ नहीं था और राजस्थान बनने के बाद फेअरवेदर ट्रैक्स बने थे जहां पर मोटरें चल सकती थीं वहां पर आज पक्की सड़कें बन गई हैं। मैं यह कहूंगा कि उन इलाकों में आज टार रोडस बन गई है।

श्री संतोषसिंह—शेरगढ़ में बन गई होंगी।

श्री खेतसिंह—जिन पर साइकिलें भी चल सकती हैं। इन सड़कों की वजह से गांव भी तरक्की कर सकेंगे और अच्छे कस्बे बन सकेंगे।

हमारी सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्ज़ के लिये एड सेन्टर से मिले थे जिनके अन्तर्गत कई बिल्डिंग्ज बन गये हैं, कहीं पक्की तहसीलें बन गई हैं और कई दूसरी बिल्डिंग्ज बन गई हैं। रोड्स पर कई जगह डाकबंगले बन गये हैं जिनमें हमारे मित्र अगर टूर में जावें तो अच्छी तरह ठहर सकते हैं। ये सारी सहूलियतें हमारी सरकार दिन-दिन दे रही है।

इसके साथ ही मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने मिनरल्स के बारे में काफी प्रयत्न किया है लेकिन अब तक कोई खास नतीजे पर नहीं पहुँची है। मैं चाहता हूं कि सारे राजस्थान का इस दृष्टि से सर्वे हो, खास कर रेगिस्तानी इलाकों का जहां पर पेट्रोल और कोयला मिल सकता है। इन स्थानों का सर्वे किया जाय और यह मालूम किया जाय कि कहीं पर कौन-कौन सी धातु प्राप्त हो सकती है। हमारे यहां गूँगा में पहले कोयले की खान खोदी गई थी लेकिन फिर एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि कोयला इन्फीरियर है इसलिये उसे खोदना बन्द कर दिया गया। यदि उसे फिर देखा जाय तो हो सकता है कि ऊपर इन्फीरियर निकल जाय और नीचे अच्छा कोयला भी निकल जाय। फलसूंड में जिप्सम अच्छा निकल सकता है लेकिन उसकी ओर कोई खास तवज्जोह नहीं दी गई। इसलिये निवेदन करूंगा कि वहां एक्सपर्ट्स को भेजा जाय और इसकी जांच करवाई जाय।

इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन हो जाने की वजह से हमारे यहां पर मीडियम साइज़ की इन्डस्ट्रीज़ चालू हो जायेंगी। जहां तक मुझे पता चला है इस कार्पोरेशन के पास एक करोड़ रोकड़ रुपये हैं जो कर्ज देगा। इस कर्ज देने से मीडियम साइज़ की इन्डस्ट्रीज़ भी शुरू होंगी।

यह राजस्थान बनने के बाद पहला मौका है जब कि राजस्थान के अन्दर बड़ी शान्ति के साथ पंचायतों के चुनाव पूरे हो रहे हैं। अब बहुत कम इलाका ऐसा रहा है जहां पंचायतें बननी बकाया हों, बाकी सब जगह अमन-चैन के साथ पंचायतें कायम हो गई हैं।

यह पंचायत-राज्य कायम हो जाने से मुझे विश्वास है कि हमारे ग्रामीण महसूस करेंगे कि वास्तव में स्वतन्त्रता आई है और हम उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इन पंचायतों के पूरा होने के बाद ही जल्दी से जल्दी तहसील पंचायतों के चुनाव भी पूरे कर दिये जांय ताकि हजारों

[श्री खेतसिंह]

केस जो चीफ पंचायत ऑफिसर्स के पास पड़े हुए हैं उनको भी तहसील पंचायतों में भेज दिया जाय और उनका फैसला जल्दी से जल्दी हो सके।

जिन जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम नहीं हुए हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कायम कर दिये जांय।

अब यह बातें हो जाने के बाद हमारे राज्य में हर ग्रामीण व नागरिक यह महसूस करेंगे कि हमारी सरकार दिन प्रतिदिन कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दे रही है और कल्याणकारी कार्यों की तरफ बढ़ रही है।

गत वर्ष इस बात पर सदन में माननीय सदस्य हंसे थे कि हवाई जहाज से बीज डालने पर क्या रेगिस्तान रोका जा सकता है। गत वर्ष वन मंत्री ने, जहां बीज डाले गये उन जमीन को, एक्वायर नहीं किया था, इस साल एक्वायर करके बीज डाले हैं। मैं खुद देखकर आया हूं कि दरख्त लगे हैं। इतने बड़े तो नहीं हैं और इतनी संख्या में भी नहीं हैं कि सारा रेगिस्तान रोक दिया जाय, लेकिन फिर भी दरख्त लगे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या यह पुराने वन मंत्री की बात है ?

श्री खेतसिंह—हां, पुराने वन मंत्री की बात है।

इन सब बातों को देखते हुए हम यह कहेंगे कि हमारी सरकार दिन प्रतिदिन जन-कल्याणकारी कार्य की ओर लगी हुई है और श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में बताया है कि इस सरकार ने गत वर्ष, राजस्थान भू-दान यज्ञ, टिनेन्सी. राजस्थान लेण्ड रिफॉर्मस एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर के कानून पास किये हैं, वे जनता के लिये कल्याणकारी और प्रगतिशील कानून हैं। एड्जोर्नमेंट जो कोर्ट में आ रहा था वह भी पूरा हो रहा है, कल ही आखरी बहस का दिन है और इस बहस के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जागीरें खत्म हो जायेंगी और जागीरें खत्म होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि काश्तकार अपने को अच्छा महसूस करेंगे और जो जागीरें वर्षों से, पीढ़ियों से चलती आ रही थीं वे जल्दी ही खत्म हो जायगी और किसान अपने आप को स्वतंत्र और अपनी जमीनों का मालिक समझेगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—कोई समय की अवधि लगाने की आवश्यकता है या नहीं और कितना समय सदन चाहता है ? आज का और कल का समय है ······················

श्री हिम्मत सिंह (अटरू)—समय का बंधन लगाने की आवश्यकता नहीं दिखती।

श्री अध्यक्ष—यह देखने के लिये कि कितने आदमी बोलेंगे और कितना समय लेंगे।

श्री एच. के. व्यास—अभी जो समय लग रहा है उससे तो अवधि लगाने की जरूरत नहीं है।

दोनों ओर के कुछ सदस्य—अभी तो चलने दो साहब।

श्री अध्यक्ष—ऑल राइट। यह देख लिया जाता कि दो दिनों के अलावा तीसरा दिन भी शामिल करने की आवश्यकता है या नहीं।

श्री हिम्मत सिंह अटरू—कल देख लिया जावे और आवश्यकता हो तो बढ़ा दिया जावे। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देने के प्रस्ताव को ऑप्रोज करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

(विरोधी दल की ओर से करतल-ध्वनि)

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में केवल २ बातें ही बताई; एक तो आर्थिक दशा इस राज्य की अच्छी होना कहा गया और दूसरे लॉ एन्ड ओर्डर में सुधार होना बताया गया। इन दो बातों के सिवाय और कोइ ऐसी खास बात उनके अभिभाषण में देखने में नहीं आई। गत वर्ष श्रीमन् राज प्रमुख ने अपने अभिभाषण में फरमाया था कि कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं पर अभिभाषण को देखने से पता चलता है और जो अभिभाषण सुना उससे अन्दाज लगता है कि कल्याणकारी राज्य का कोई खास जिक्र इसमें नहीं किया गया है कि कौनसा कल्याणकारी कार्य किया है ?

कहने के लिये तो सब बातें दर्ज कर दी हैं कि यह काम हुआ, वह काम किया, यह किया जा रहा है पर वास्तव में देखा जाय तो पेपर हो पेपर पर ज्यादा है, वास्तविकता में कुछ नहीं है।

सबसे पहले मैं कानून की व्यवस्था के बारे में जिक्र करूंगा कि डकैती, लूट-मार, कत्ल और चोरियें आदि की परसेंटेज में कितनी कमी हो गई है, ऐसा वे अभिभाषण में फरमाते हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

एक कहावत है कि 'गार के नगारे, घर के बजाने वाले' पुलिस वालों ने लिख कर रिपोर्ट भेज दी कि इतनी कमी हो गई है और यहां हाउस में सुना दिया कि कमी हो गई है पर इसका बैकग्राउन्ड क्या है जिससे दुनियां अच्छी तरह से परिचित है।

स्थिति यह है कि पुलिस में रिपोर्टें दर्ज तक नहीं होतीं। कोई डकैती हो जाती है तो डाकू डकैती करके चले जाते हैं और पुलिस वक्त पर पहुंच भी नहीं पाती। मैं कोटा का ही आपको जिक्र करूँ कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में जहां वर्षों से डकैती का नामोनिशान नहीं था आज कोटा डिस्ट्रिक्ट के मध्य बारां के आस-पास भयंकर डकैती हुई जो हमने हमारी उम्र में कभी सुनी नहीं। पुलिस वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, पर पुलिस की कोई कार्यवाही उसके बाबत नहीं हुई। बाद में पकड़ा-पकड़ी हुई, किसी को पकड़ा

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

और कह दिया कि डकैती (पकड़ने) में हमने सफलता प्राप्त की है। ऐसे भी उदाहरण देखने में आये हैं कि रोबरी (Robbrey) हुई, थाने में रिपोर्ट को गई लेकिन थाने वालों ने रिपोर्ट दर्ज तक नहीं की और चोरियें तो इतनी बढ़ गई हैं कि इस वजह से गांव-गांव में लोग परेशान हैं। गांवों में ही नहीं बल्कि शहरों में दिन-दहाड़े लोग रास्ते चलते लोगों को लूट कर चले जाते हैं। क्या इससे यही समझा जावे कि दरअसल कानून और व्यवस्था की हालत का सुधार हुआ है ?

श्रीमन् राजप्रमुख ने इस साल १५ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड (नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज ब्लॉक्स) खोलने का अपने भाषण में जिक्र किया है कि ये १५ नये खण्ड खुल रहे हैं, और कुछ समय में कुल राजस्थान में जगह-जगह राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड (National extension serres blocks) खुल जावेंगे लेकिन ब्लॉक्स के एक्टेन्शन से काम नहीं चलेगा। हमको तो डेवलपमेंट ब्लॉक्स पर चलना है। नेशनल एक्सटेन्शन ब्लोक्स तो हमारे लिये प्राइमरी वर्क है, हमें डेवलपमेंट ब्लॉक्स पर पहुँचना है। नेशनल एक्सटेन्शन सर्विसेज ब्लॉक्स खोले जा रहे हैं और डेवलपमेंट ब्लॉक्स नहीं खोले जा रहे हैं। नेशनल एक्सटेन्शन ब्लोक्स कोटा में भी हैं। ये तो बहुत सारे खोल दिये गये, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड में कोई उन्नति नहीं की गई और डेवलपमेंट ब्लॉक्स कोई नहीं खोले गये। इसके अलावा देखा जावे तो इन एक्सटेन्शन ब्लोक्स और डेवलपमेंट ब्लोक्स में जितना रुपया खर्च होता है उतना काम नहीं हो रहा है। मौके पर जाकर देखने से इसका अन्दाजा हो सकता है कि जितना रुपया खर्च हो रहा है अधिकतर व्यर्थ जा रहा है। जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है और सेन्टर मदद दे रही है उसका ५० प्रतिशत का भी फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में हम कैसे मान लें कि हम वेलफेअर स्टेट बनाने जा रहे हैं।

आगे चल कर श्रीमन् राजप्रमुख ने यह फरमाया कि बन्दोबस्त शीघ्र ही पूरा हो जावेगा। बन्दोबस्त के बारे में मैं आपको बताऊँ कि वह काम किस तरह से चल रहा है। बन्दोबस्त की एक अजीब हालत है। गांव वालों को मामूली काम करने वाले और अमीन कहते हैं कि जो कुछ करवाना हो तुम हमसे अभी करवा लो आगे जो हम कर देंगे वही सही हो जावेगा फिर पीछे कोई सुधार नहीं होगा। अगर ऐसा ही बन्दोबस्त अच्छा बन्दोबस्त माना जावे तो इसको किसी प्रकार का बन्दोबस्त नहीं कहा जा सकता है और यह बात फेक्ट है कि जो अमीन मौके पर जाकर कर देते हैं उसकी पीछी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब यह है कि ऊपर से कोई निगरानी नहीं है। नीचे के कर्मचारी जो भी अपना उल्लू सीधा करके कर देते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं।

भूमि-सुधार के बाबत दो मुख्य बातें श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहीं। सबसे पहले जागीर रिज़म्पशन एक्ट के बारे में कहा। उसमें उन्होंने यह फरमाया कि बहुत सारी जागीरें तो जब्त कर ली गई हैं और बहुत सी जागीरों के विषय में रिट पिटीशन्स पेश की हैं, उनका भी जल्दी ही फैसला होने वाला है। रिज़म्पशन ऑफ जागीर के बारे में मैं ज्यादा कहना पसन्द नहीं करता क्योंकि इसके बाबत तो जागीरदारों ने पहले ही समझौता कर लिया है। अच्छा है कि इससे हमारे देश को लाभ हो, इससे बढ़ कर दूसरी बात नहीं हो सकती, लेकिन कहाँ तक देश को लाभ होगा यह अंदाज करने की बात है। वास्तव में काश्तकारों को पूछा जावे कि उनको कितना लाभ हुआ है। मारवाड़ की तरफ की

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]
तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अपने देश की बात तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर काश्तकारों को किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ है।

श्री मोतीलाल चौधरी—आपका कौन सा देश है।

श्री हिम्मत सिंह—मेरा देश हडौती है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया कि हमने भूमि सुधार में काफी कदम बढ़ाया और इस संबन्ध में टैनेन्सी बिल पास किया। मगर में यह कहूंगा कि इस बिल से कोटा के काश्तकारों को तो कोई फायदा नहीं होगा। हमने बहुत कोशिश की कि इस बिल में ऐसी बातें नहीं रहें जिससे काश्तकारों को फायदा नहीं पहुँचे। लेकिन जब यह बिल अमल में आवेगा तो साफ मालूम हो जावेगा कि काश्तकारों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अभी तक यह बिल स्वीकार होकर नहीं आया लेकिन जब आवेगा उस समय इसका परिणाम सामने आ जावेगा।

पशुधन सुधार के लिये प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए एक सदस्य ने फरमाया कि जगह-जगह नागौर के बैल भेज कर पशुओं की नस्ल सुधारी जावेगी। मगर नागौर के सांड नागौर में ही ज्यादा सफल हो सकते हैं, दूसरी जगह वे काम नहीं दे सकते हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि इस क्रॉस ब्रीडिंग से अच्छी नसल पैदा होगी तो यह तो प्रकृति का नियम है कि इस प्रकार खच्चर पैदा होते हैं और उनकी औलाद ज्यादा नहीं चल सकती। वाइल्ड लाइफ प्रिज़र्वेशन के बाबत यह कहा गया कि पशु संरक्षण बोर्ड कायम किया जा रहा है। ऐसी कहावत है कि "वर्षा भई जब कृषि सुखाने;" राजाओं के जमाने में जंगल में काफी जानवर रहते थे पर अब एक चूहा भी नहीं निकलता हुआ नजर आवेगा। खरगोश तो खेतों में ही रहते हैं। सांभर और सूअर दो इस किस्म के जानवर हैं जो घने जंगलों में रहते हैं। लोग-बाग सांभर और सूअर का शिकार खेला करें। लेकिन आज-कल न्युरिच बहुत से हो गये हैं, मोटर और बन्दूक लेकर जानवरों को मारने के लिये निकल जाते हैं। वे जानवरों को घायल कर देते है और बेचारे दुःख पाते हैं और न मालूम कहां जा कर मरते हैं। उनकी फरयाद हमारे पास आती है और उसको सुनकर हमें दुख होता है। इसका नतीजा यह होता है कि जानवर उधर खत्म होते हैं और उधर शेर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शेरों को मारने वाले नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि शेरों की तादाद बढ़ती जा रही हैं और वे जंगलों से गांव में आने लग गये हैं। जब उनको जंगलों में जानवर नहीं मिलते तो वे गांवों में गायें और मनुष्यों पर धावा बोलते हैं। इस प्रकार शेर भी लॉ एन्ड आॅर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं।

नये उद्योग एवं खनिज पदार्थ निकालने के बाबत अभी तक सर्वे चलेगा और इस सर्वे का क्या नतीजा निकलेगा, कब तक सोना और चांदी खोद कर सम्पन्न बनावेंगे, यह समय ही बतावेगा।

आगे श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में नेशनल केडेट कौर और ए. सी. सी. ट्रेनिंग स्कूलों में देने का जिक्र फरमाया। इससे, उन्होंने फरमाया कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना बढ़ेगी।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

हिन्दुस्तान एक पीस लविंग कन्ट्री है। हमारी पॉलिसी यह है कि न हम किसी से लड़ें और न हम, इसके लिये तैयारी करें। महात्मा गांधी ने, यह आदेश दिया था कि पुलिस का जाब्ता तकात नहीं रहेगा। इसलिए नेशनल केडिट कोर और ए. सी. सी. की ट्रेनिंग के लिए इतना खर्चा करना समझ में नहीं आता है कि इसका क्या परिणाम होगा। महात्मा गांधी के उद्देश्य पर चलेंगे या हम किसी से भिड़ जावेंगे ?

आगे चल कर श्रीमन् राजप्रमुख ने दवाइयों में एडल्ट्रेशन रोकने के बाबत कानून बनाने के लिये, फरमाया है और बी. सी. जी वगैरह और एन्टी मलेरियल युनिट्स स्टेट में जगह जगह भेजे जाकर बीमारियां कों रोकने के बाबत जिक्र फरमाया। मैडिकल डिपार्टमेन्ट का यह हाल है और जो कई दफा हाउस के सामने आ चुका है कि डाक्टर्स तो ज्यादा है और दवाइयां कमती हैं, खर्चा डाक्टर्स पर ज्यादा होता है और दवाइयों पर कम होता हैं। अगर पहले के आंकड़े देखे जावें तो मालूम होगा कि हॉस्पिटल्स की अटेन्डेन्स वहां कम होती चली जा रही हैं और जगह जगह नये डाक्टर्स जिनके पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं हैं प्रेक्टिस करके लोग-बागों का इलाज कर रहे हैं और दुनियां की जान खतरे में पड़ रही है। अगर सफाखाने में बीमार जाता है तो या तो उससे पैसा मांगा जाता है या दवाइयों के लिये दूकान अपनी बतायी जाती है कि वहां से जाकर दवाई खरीद लावे और इलाज करावे। यह मेडिकल डिपार्टमेन्ट की व्यवस्था है। यहां तक कि पट्टी भी बांधने के लिये बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है। क्या इससे यह समझा जावे कि यह कल्याणकारी काम कर रहे हैं।

बी. सी. जी. कैम्पेन बड़ा जोर-शोर से चलाया जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम दुनियां से कितने पीछे हैं। आई. एन. एच. दवाई निकल गई है। वहां ट्युबरक्यु लोसीस के वार्ड्स कमती होते जा रहे हैं और यहां कंजम्पशन के वार्ड्स नये बनाने की जरूरत पड़ रही है।

डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को इमदाद देने के लिये २५०० मकान और एक हजार दूकानें बनी हैं। अगर जगह जगह देखा जाय शहरों में, जहां कि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स बसे हुए हैं तो मालूम पड़ेगा कि सरकार ने रहने के लिए मकान और दूकानें बनाई है उनमें से कितने मकान खाली पड़े हुए हैं और उनके काम में नहीं आ रहे हैं। यह रुपया बिला वजह खर्च किया जा रहा है।

सड़कों के निर्माण के बाबत श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि ७०० मील की सड़क बन चुकी है। राजस्थान बड़ा-लम्बा चौड़ा देश है। यह सात सौ मील की सड़कों से तो कैसे कवर हो सकता है। कम से कम सात सौ मील के ऊपर दो सिफर और लगाई जाय तो में कहूंगा कि राजस्थान को यह सड़कें कवर कर लेंगी। लेकिन ७०,००० मील की सड़कें राजस्थान में बनाने में कितना खर्चा होगा और मेंन्टीनेन्स में भी खर्चे रखना होगा या नहीं, यह भी सोचने की बात है।

एक रेलवे लाइन फतहपुर से चूरू, जरुर सुना है कि इस साल बननी शुरु हो गई है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पुकार सुन कर एक २०-२५ मील का रेल का टुकडा हमको दिया है। लेकिन २०-२५

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

मील के टुकड़े से तो काम नहीं चल सकता है। राजस्थान में हजार दो हजार मील की और लाइन बनाने की जरूरत है और हमारी सरकार को चाहिए कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को काफी कोशिश करके तैयार करें।

पेरा ३४ में श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया है कि गावों में ग्राम पंचायते, नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड बनाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के बाबत में आपको अर्ज करूं कि पंचायतों के इलेक्शन्स हमारे इलाके में तो पहले कभी के हो चुके है और अब शायद दूसरे और तीसरे के लिए कहीं २ चुनाव का काम होने वाला है। लेकिन जहां ग्राम पंचायतो का चुनाव नहीं हुआ है और जहां शुरु किया गया है वहां की जो सूचना मुझको मिली है उससे पता चलता है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में कितनी धींगा-धींगी चल रहीं है। वह भी नहीं, मैंने खुद ने इस बात का अनुभव किया है कि जहां हमारे यहां ग्राम पंचायतों हो चुकी थीं वहां भी यह हालत है कि अफसर नियुक्त किये जाते हैं, वे मनमानी ग्राम पंचायत चुनाव कर देते है, तारीख तो कोई•नियत होती है और दूसरी तारीख पर चुनाव हो जाता है, नाम कि का आता है, चुनाव किसी दूसरे का होता है; नाम किसी दूसरे आदमी का निकलता है। ग्राम पंचायत एक्ट बना है, काफी अर्सा हो गया है। उसके बाबत नियम, रूल्स हैं। वे अब अंग्रेजी में जारी हुए हैं और ग्राम पंचायतों में अब तक पहुंचे नहीं है और अगर अंग्रेजी में पहुंचे हैं तो वे समझ ही नहीं सकते हैं। इतना विलम्ब इस काम के लिए होना तो एक बड़े अफसोस की बात है। किस तरह से ग्राम–पंचायतों का काम ठीक तरह से चल सकता है जब कि ग्राम पंचायतों में, जो राजस्थान सरकार ने नियम बनाये हैं वे अभी तक हिन्दी में अनुवाद होकर वहां नहीं पहुंचे हैं।

ग्राम पंचायतों के साथ साथ तहसील पंचायतें भी बनी है और काफी इलाके में तो, करीब–करीब पूरा ही समझिये ना, तहसीलों में पंचायतें बन चुकी हैं। लेकिन उन तहसील पंचायतों का काम चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न आगे कोई ऐसी आशा नजर आती है कि कोई इसके बाबत विचार किया जावेगा। किस तरह से ये तहसील पंचायतें फक्शन करेंगी, उनके पास अर्थव्यवस्था क्या होगी, इसके बावत सरकार ने न विचार किया और न कोई उनको इस बात की सूचना दी?

रुरल वाटर सप्लाई के बाबत कहा जाता है कि लाखों रुपया खर्च किया जावेगा। बड़ी शर्म की बात है कि मारवाड़ जैसे देश में पानी पीने के लिए लोगों को मिल जावे तो उनको बिलकुल जीवन के लिए एक बड़ी भारी सहायता मिलेगी, वरना उनको हर साल बिना पानी के दुख उठाना पड़ता है।

श्री मोतीलाल चौधरी—आपके कोटा में नहीं है।

श्री राज हिम्मतसिंह अटरू (जारी)—भ्रष्टाचार की बाबत श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि सरकार ने एक बोर्ड इसके लिए मुकर्रर किया है। वैसे यहां भ्रष्टाचार–निरोध-डिपार्टमेंट कई बर्षों से काम कर रहा है जो पुलिस के हाथ में है। तो इसके लिए एक कहावत मशहूर है "जलेबी की रखवाली पर कुतिया" भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस को मुकर्रर किया गया है! इस बोर्ड के निर्माण करने से यह साफ साबित हो गया है, जो कि राजप्रमुख के भाषण में है कि

Page No.31

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

उस भ्रष्टाचार निरोध विभाग से काम चला नहीं, तब यह खासतौर से बोर्ड का निर्माण किया है ताकि बोर्ड ज्यादा निगरानी रख सके। यह ठीक है कि बोर्ड का निर्माण किया गया है। बोर्ड के क्या क्या फंक्शन होंगे, यह तो तभी पता चलेगा जबकि बोर्ड के नियम बनेंगे। बोर्ड को क्या क्या अधिकार होंगे, बोर्ड क्या क्या सजा दे सकेगा यह तो नियमों के बनने पर ही उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। केवल बोर्ड के मुकर्रर कर देने से ही भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये केवल बोर्ड के निर्माण से ही काम नहीं चल सकता। उसके लिये आदमियों की मोरल्स (नैतिकता) को सुधारने की जरूरत है। मोरल्स का सुधार धर्म से ही हो सकता है, जिस ओर हमारी सरकार का कतई ध्यान नहीं है। धर्म ऐसी चीज है जिससे आदमियों के मोरल्स सुधर सकते हैं पर इस बाबत गवर्नमेन्ट का कतई ध्यान नहीं कि लोग-बागों का मोरल्स किस तरह सुधर सके। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रोज-ब-रोज सिनेमाओं के खुलने के समाचार मिलते हैं। सिनेमा देखने से आदमी का मोरल कितना गिर जाता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जैसा कि हमने सुना है यहां २१ तारीख को होने वाले क्रिकेट मैच से मिल सकता है। शहर वालों का सिनेमा देखने से मोरल कितना बढ़ गया है यह इस बात का प्रमाण है।

फिर राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया है कि हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल्स पास कर दिये हैं और बहुत सारे पास होने वाले हैं। खाली बिल्स के पास कर देने से, उनकी लाइब्रेरी भर देने से गवर्नमेन्ट का सुधार नहीं हो सकता। हमें तो यह देखना चाहिये कि इनका एक्जीक्युशन कितना हो रहा है। जब तक उसके अनुसार आचरण नहीं होता तब तक देश की उन्नति और हालत नहीं सुधर सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर हमारी सरकार का कतई ध्यान नहीं है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने इतनी बातें फरमाईं जिनका कि मैंने जिक्र किया। इससे यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना कल्याणकारी कार्य हुआ है। कहने के लिये तो काफी कहा गया है किन्तु वास्तव में कितना हुआ है, यह सोचने की बात है।

हम तो यह आशा करते थे कि श्रीमन् राजप्रमुख अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते कि हम एक्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को जल्दी से जल्दी अलग कर रहे हैं। आज वर्षों से लोगों की यह मांग हो रही है कि एक्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को सेपरेट किया जाय। इस बाबत कतई श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में प्रकाश नहीं डाला, हमें इसका बड़ा अफसोस है। जब तक जुडिशियरी एक्ज़ीक्युटिव से अलग नहीं होगी तब तक लोगों के साथ यह दकियानूसी बर्ताव चलता रहेगा और जुल्म और ज्यादतियां होती जायंगी। इसलिये जल्दी से जल्दी जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट कर देना चाहिये, खासतौर पर इस डेमोक्रेटिक जमाने में जहां कि हम अन्य बातों में और देशों की नकल कर रहे हैं वहां हमें इसको सबसे पहले लेना चाहिये।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी की ओर कुछ भी नहीं कहा और इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया। एक तरफ तो हमारी सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपया

[हिम्मतसिंह् अटरू]

खर्च करती चली जा रही है, शिक्षा का विस्तार होता चला जा रहा है और शिक्षित होते जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके एम्पलॉयमेन्ट के साधन नहीं दे रहे हैं। युनिवर्सिटी और स्कूल्स और कॉलेजों से हजारों की तादाद में नवयुवक निकलते हैं पढ़ लिखकर लेकिन बगैर धन्धे के इधर उधर मारे-मारे फिरते हैं। उनको प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान सरकार कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। अच्छा होता यदि राजप्रमुख इस सम्बन्ध में अपने भाषण में कुछ प्रकाश डालते।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह नहीं बतलाया कि इस जमाने में जिन चीजों के रेट्स गिरते जा रहे हैं उससे हमारे प्रान्त पर क्या असर पड़ेगा। आज हमारे कोटा के इलाके में कोटा डिस्ट्रिक्ट में जवार का भाव ४ और ३॥ रुपये प्रति मन रह गया है। अगर इन भावों के साथ साथ अन्य चीजों के भी भाव गिरते जाते तो हमें समझ में आ सकता था। आज हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ किसान जिस चीज को पैदा करता है उसके भाव गिरते जा रहे हैं, दूसरी और कपड़े और एग्रीकल्चर के इम्पलीमेन्ट्स् हैं उनके भाव वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। समझ में नहीं आता इस बारे में राजप्रमुख ने अपने भाषण में प्रकाश क्यों न डाला। अगर इस तरह इनके भाव गिरते गये तो ८० फी सदी काश्तकारों की क्या हालत होगी, यह सोचने की बात है। जो कीमती चीजें, जैसे जीरा, अलसी वगैरह जो काश्तकार पैदा करते हैं, उनके भाव भी गिरते जा रहे हैं। इन चीजों के भाव भी ठीक होते तो भी काश्तकारों को कुछ राहत मिलती और वे अपना गुजारा चला सकते। इन भावों के गिरने से काश्तकारों की स्थिति दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। जो कुछ पिछले अरसे में इन्होंने थोड़ा बहुत कमाया था वे थोड़े ही दिनों में उसको गमा बैठेंगे। इससे और ज्यादा फायदा पहुंचने वाला नहीं है। सरकार को चाहिये यह था कि इस बाबत भी कोई योजना सामने लाते कि किसानों को इससे बचाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में टेक्सेशन की बाबत जिक्र किया कि कस्टम ड्युटी १ अप्रेल से उठा दी जायेगी और इसके बजाय सेल टेक्स लागू हो जायगा; इससे हमें नुकसान रहेगा, इसलिए हमें टेक्सेज़ का दूसरा जरिया ढूंढ़ना पड़ेगा। वैसे ही राजस्थान में अन्य प्रान्तों के मुकाबले ज्यादा टेक्सेज लगे हुए हैं। इस बात से कि टेक्सेज़ को बढ़ाने के साधन ढूंढ़े जायेंगे इससे हमें बहुत दुख हुआ। हमें यह देखना है कि क्या हमारी जनता और ज्यादा टेक्सेज़ के भार को सहन कर सकेगी, यह सोचने की बात है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में सोश्ययलिस्टिक स्टेट बनाने के बारे में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला, जो कि कांग्रेस की एक नीति है। हमें पता नहीं कि किस प्रकार सब का स्तर एक सा बनायेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मनुष्य अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन एक कुदरत भी कोई चीज होती है। पेड़, पौधे, घास आदि कई चीजे हैं, जो पेड़ हैं वे पेड़ ही रहेंगे, घास और पौधे पेड़ नहीं हो सकते। आम का जो पेड़ है वह पेड ही बना रहेगा वह कभी घास नहीं हो सकता, झाड़ झाड़ ही रहेंगे और पौधे पौधे ही। फिर भी मनुष्य सबको एक करने की धुन में है। यह प्रकृति के खिलाफ प्रयत्न है इसके परिणाम क्या होंगे यह समझदार आदमी ही समझ सकता है, सामान्य आदमी की बुद्धि के बाहर की बात है।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

जिस जमाने में एटोमिक इनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है उस जमाने में जमीन में से कोयला निकालने तथा और और चीज निकालने की बात करना एडवान्समेन्ट समझते हैं, यह हमारी कोई तरक्की नहीं हैं। जिस जमाने में हमें एटोमिक इनर्जी मिल सकती है वहां हम जमीन के अन्दर घुसकर कोयला निकालने की बात करते हैं, इससे क्या लाभ होगा ? एटोमिक इनर्जी से मशीनरी चल सकती है, एग्रीकल्चर में भी लाभ होगा और मेडीकल साइन्स में भी मदद मिलेगी। अतः अगर राजप्रमुख अपने भाषण में इस एटोमिक एनर्जी का जिक्र करते तो यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती और हम समझते कि हमारा प्रदेश विशेष कल्याणकारी राज्य बनने जा रहा है।

अन्त में विशेष समय न लेकर अपना भाषण समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि राजप्रमुख के भाषण में कोई ऐसी खास बात नहीं आई कि जिसके लिए वह बधाई के पात्र हों।

इतना में जरूर कहूंगा कि राजप्रमुख ने इस समय अपना भाषण हिन्दी में करके इस हाउस की, जो एक पुरानी मांग थी, उसको जरूर पूरा किया है; लेकिन साथ ही साथ इस बात का दुख होता है कि हम इस हाउस में बैठे हुए सदस्यगण आज भी बजाय हिन्दी में बोलने के अंग्रेजी में बोलने का प्रयत्न करते रहते हैं। मुझे आशा है कि इस दिशा में भी सरकार प्रगति करेगी और इस सदन का तमाम कार्य भी हिन्दी में ही होगा और अंग्रेजी बोलने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह विधान सभा का तीसरा वर्ष है, जब कि माननीय श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण हमको सुनने को मिला।

यह बात हमको सान्त्वना देने वाली जरूर है कि इस वर्ष गत वर्ष की भांति राजप्रमुख ने अपना भाषण अंग्रेजी में नहीं बोल कर हमारी भाषा में भाषण दिया, लेकिन जो मिश्रित भाषा वह बोले वह यह बताती है कि शायद उनको हमारी भाषा अच्छी तरह बोलने में कुछ समय और लगेगा। अब आप यह बता सकेंगे कि कितना समय लगेगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास : मिक्स्ड इकोनॉमी है।

श्री वेदपाल त्यागी : जो प्रस्ताव जयपुर के माननीय सदस्य ने रक्खा कि जो भाषण श्रीमन् राजप्रमुख ने पढ़ा उसके लिए सदन की ओर से उनको धन्यवाद दिया जावे, उस प्रस्ताव का मैं विरोध करना चाहता हूं,

(श्री हरिकृष्ण व्यास : हियर, हियर)

इसलिए कि जिन बातों का उनके भाषण में समावेश होना चाहिये था वह मुझे नहीं मिलतीं। जिस प्रकार की कांग्रेस की पॉलिसी रही है और जो उनकी डिक्लेअर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार वे एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं और जिसके लिए इस राजस्थान प्रदेश की शासन की बागडोर उन्होंने संभाली है, उसका कतई उल्लेख इस भाषण में नहीं मिलता कि किस प्रकार से वे ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं।

[श्री वेदपाल त्यागी]

मैं निवेदन करूंगा कि इस भाषण में दो बातों पर जोर दिया गया है; एक तो यह कि इस राज्य की आर्थिक उन्नति हो रही है और दूसरी बात यह कि ला और ऑर्डर की हालत दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त तीसरी बात जो कि आज देश के सामने मुंह बाये खड़ी है, उसका कतई उल्लेख इसमें नहीं है। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेकारी की है जिसको भारत सरकार अरबों रुपया खर्च करके हल करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए पंचवर्षीय योजना चला रही है और करोड़ों अरबों रुपया इसमें लगा रही है। वही बेकारी की समस्या हमारे इस प्रदेश में भी मुंह बाये खड़ी है, पर इसके बारे में एक शब्द भी राजप्रमुख के भाषण में नहीं कि हमारी सरकार क्या करने जा रही है इस दिशा में क्या योजना है हमारी सरकार के सामने जिससे वह इस भयंकर बेकारी की समस्या का हल करना चाहती है ? एक तरफ यह कहा जाता है कि इस वर्ष में सरकार ने बहुत से काम खोले हैं, इससे लोगों को बहुत अच्छी तरह का काम मिला है और यह भी दूसरी तरफ कहा गया है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, पर इस वक्त हम यह देख रहे हैं कि जिस अनुपात में ये प्रोडक्शन के बढ़ने की बात करते हैं उसी अनुपात से यह बेकारी भी बढ़ती जा रही है। यह ऐसा फेनोमेना (Phenomena) है कि जिसका अगर समय पर हमने पता नहीं लगाया और जिसको हमने समय रहते हल नहीं किया तो हमें यह बेकारी की समस्या निगल जाने वाली है। हमें इसका पता लागाना चाहिये कि किस जगह गलती है, फॉल्टी प्रोसेस हमारा किस जगह है, जिसकी वजह से यह बेकारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, और हमारे ये नौजवान और वे जौजवान जो मैकॉले के दिमाग की उपज की शिक्षा संस्थाओं से हर साल दनादन निकलते चले जा रहे हैं और चारों तरफ नारा लगाते हैं बेकारी का। राजप्रमुख ने एक शब्द जरूर अपने भाषण में इसके लिए कहा है कि योजना हमारी जरूरी है जिससे बेकारी की समस्या हल होगी, पर किस प्रकार यह हल होगी इसका इसमें कोइ उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार के सामने किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है कि इस समस्या को यह सरकार किस तरह से सुलझाना चाहती है। मेरे ख्याल से यह इतनी बड़ी समस्या है कि जिसको अगर ठीक तरह से इस समय नहीं सुलझाया गया तो आगे यह ऐसा भीषण रूप धारण कर लेगी कि जिसे सुलझाना इस सरकार के लिए असम्भव होगा और केओस होगा और इस केओस के अन्दर से किस तरह की क्या चीज निकले बाहर, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस अभिभाषण के लिए, जो आज की समस्याओं पर कतई प्रकाश नहीं डालता, अगर धन्यवाद देना सदन मन्जूर कर लेता है तो यह सदन अपने साथ एक प्रकार का अन्याय ही करेगा।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में, जिसके ऊपर शासन चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, आज जिस प्रकार की एक संकुचित विचारधारा पैदा हो गई है और जिसके कारण शासन की अनेकानेक समस्याओं पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाता है और जिनको ठीक हल नहीं कर सकता, एक चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। वह संकुचित विचार-धारा यह है कि जो लोग जहां से आये हैं उनको अपने प्रदेश विशेष से इतना ज्यादा मोह पैदा हो गया है कि वे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर सारे राजस्थान के हित के दृष्टिकोण से विचार कर नहीं सकते।

[श्री वेदपाल त्यागी]

प्रादेशिक भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ और दूसरी खतरनाक बुराइयाँ भी पैदा हो रही हैं जिनमें सबसे खतरनाक बुराई है कॉम्युनलिज्म की। यह कॉम्युनलिज्म उग्र रूप धारण करता जा रहा है।

सन् ४७ से पहले हमने देखा कि हमारे सामने मुस्लिम समस्या पैदा हो गई थी और उसी के कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ। पर इस बंटवारे के बाद भी जब हम आजाद हुए और जब हमने यह समझ लिया कि चलो अब यह कॉम्युनल समस्या हल हो गई, पर हमारा वह समझना ठीक नहीं निकला और यह समस्या और उग्र रूप से हमारे सामने आती दिखाई दी। चुनाव हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इससे भी एक सबसे बड़ी खराबी पैदा हो रही है कॉम्युनिटी के बेसिस पर चुनाव हम लड़ रहे हैं। साम्प्रदायिकता बड़ी तेजी से पनपती जा रही है और इसी के आधार पर छोटे से लेकर बड़े-बड़े चुनाव तक लड़े जा रहे हैं। यह बुराई बजाय दूर होने के, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए आज इस एडमिनिस्ट्रेशन को बजाय ठीक करने के, यह दिन-प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जा रहा है। इसलिए जो समस्याए आज हमारे सामने खड़ी होती हैं उनको हम ठीक तरह से हल नहीं कर पाते हैं, जो सोचते हैं उसे कार्यरूप में परिणित नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज की यह जो समस्या है उस पर हमारे राजप्रमुख महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई भी विचार नहीं किया है और उनको सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया है कि आज की हमारी सरकार इस साम्प्रदायिक समस्या को किस प्रकार हल करने जा रही है। इस साम्प्रदायिकता से हमारी प्रतिष्ठा काफी गिरती जा रही है।

आगे अपने विचार व्यक्त करूं इससे पहले यह कहना चाहता हूं कि आगे यह कहा गया है कि सहकारिता से इस देश में खेती की उन्नति हो सकती है और सहकारिता हमारे यहां बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने आंकड़े भी बताये कि हमने इतने लाख रुपये, १४ लाख रुपया तो सहकारी समितियों को कर्ज दिया है और २५ लाख रुपया अगले साल देना चाहते हैं। पर मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसा डिपार्टमेन्ट राजस्थान में है जिसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया हो तो वह विभाग है सहकारी विभाग। इसे तो एक तरह का ऑर्फन विभाग खोल रखा है कि जिसको और कहीं नहीं लगा सकते उसको इस विभाग में भेज देते हैं। आपने सहकारी विभाग का अध्यक्ष मुकर्रर किया है। वह सहकारिता के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे पहले के व्यक्ति जो इस ओहदे पर काम करते थे उनको बाहर भेज दिया। इसी काम के लिए राजस्थान के खर्चे पर वे ट्रेन्ड कराये गये पर वापिस आने पर तबादला कर दिया गया। कहा यह जाता है कि पहले यह पोस्ट आई. ए. एस. केडर की थी अब आर. ए. एस. केडर की कर दी गई है। यह इसलिये किया गया कि उनका तबादला करना उनको मन्जूर था और दूसरे आदमी को यहां भेज दिया गया जो आर. ए. एस. सर्विस का आदमी था।

हो सकता है कि विभाग के अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी के हों इसलिए आपने उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं देकर उनको रखा, लेकिन सहकारी विभाग के जो रूल्स बनाये गये उनमें यह है कि डिप्टी डाइरेक्टर टेक्निकल होगा, और डिप्टी डाइरेक्टर वे लोग होंगे जो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद से बढ़ाये जायेंगे। वे आर. ए. एस. केडर के नहीं होंगे। लेकिन कुछ थोड़े दिनों के बाद एक आर. ए. एस. को डिप्टी डाइरेक्टर मुकर्रर किया गया क्योंकि उनके लिए और कोई जगह

[श्री वेदपाल त्यागी]

नहीं थी, और उनको हमारे मन्त्री महोदय को यहां रखना मन्जूर था। उनको जब दूसरी जगह प्रोवाइड कर दी तो वह जगह एब्रेंयेंस में रख दी गई। और किसी असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को डिप्टी डाइरेक्टर नहीं बनाया गया, जो कि उसके लिए ट्रेन्ड था। मंत्री महोदय को दूसरा आदमी मन्जूर हुआ तो उसको डिप्टी डाइरेक्टर बना कर भेज दिया। यह मैंने मिसाल के तौर पर बयान किया है। यह मिसालें इस प्रकार की हैं जिससे यह पता लगता है कि इतने बड़े विभाग को जो कि हमारे निर्माण कार्यों में बहुत सहायक हो सकता है किस प्रकार डम्पिग ग्राउन्ड बना रखा है, जिसको चाहते हैं बढाना उसको वहां लाकर बिठा देते हैं।

यह कहा गया है सहकारिता के आधार पर कृषि की उन्नति हो रही है अगर सहकारिता के आधार पर कृषि की उन्नति करना है तो सहकारी विभाग के ढांचे को बदलना पड़ेगा और वहां उन आदमियों को, जो सहकारिता के सिद्धान्तों को जानते हैं, सहकारिता के टेक्निकल ग्राउन्डस को जानते हैं कि किस प्रकार सहकारिता चलाई जाती है, उन्हें बिठाना होगा।

इसके उपरान्त अब जो सहकारी सभाएं बन रही हैं, उन सहकारी सभाओं के नम्बर में वृद्धि तो जरूर हुई है, लेकिन उनका हाल वहां जाकर देखें कि क्या हाल है। वे बराबर एकाउन्ट्स नहीं रखते हैं और हजारों रुपया जो बैंक से कर्ज दिया जा रहा है वह बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों की सहकारी सभाएं बनाकर खराब किया जा रहा है।

इसके अलावा एपेक्स बनाया है। जिस तरह का एपेक्स का ढांचा बनाया गया है वह ढांचा जिस रूप में कार्य रुप में परिणत हो रहा है उससे पता लगता है कि वह हड्डियों का ढांचा बनाकर रखा गया है। यह एपेक्स करोड़ों रुपया रिजर्व बैंक से ले सकता था लेकिन वह आज इससे महरूम रहा सिवाय इसके कि ५ लाख के शेयर सरकार ने खरीदे हैं और कुछ सहकारी समितियों पर लाद दिये गये हैं, पब्लिक के किसी एक आदमी ने एक भी शेयर नहीं खरीदा है क्योंकि उसके अन्दर लोगों का विश्वास नहीं है। हमारी सरकार के अन्दर से भी लोगों का विश्वास उठा जा रहा है, क्योंकि हमारे कार्य करने के तरीके इस प्रकार के हैं कि हम उनमें विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। लोग यह समझते हैं कि हमारे हर एक कार्य में स्वार्थपरायणता छुपी रहती है। जो भी काम होता है वह बाद में साबित होता है कि उसमें स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं था। एपेक्स बैंक के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बारे में मैं जानकारी रखता हूँ और उसे मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारे कोटा में एक सहकारी बैंक है जिसके पास में रुपया बहुत ज्यादा रिजर्व में है जिसको बहुत अच्छा उन्नतिशील एपेक्स बैंक बना दिया जा सकता था, लेकिन हममें यह संकुचित विचारा-धारा काम कर रही थी कि कोटे में क्यों हो, वह जयपुर में रहना चाहिए। इस कारण से इतनी बड़ी संस्था को आपने छोड़ दिया। उसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के एम्प्लॉईज् निकाले जा रहे हैं और उसकी हालत खराब हो रही है और जो एपेक्स बैंक ५ लाख रुपये स्टेट ने देकर स्थापित किया है उसकी दशा यह है कि वह बढ़ नहीं रहा है, शेयर्स नहीं बिक रहे हैं और हमारी सहकारिता जिस पर राजप्रमुख नाज करते हैं वह खत्म होती जा रही है इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि यह जो कहा गया है कि सहकारिता के आधार पर खेती की उन्नति हुई है यह सिर्फ कहने मात्र के लिये

[श्री वेदपाल त्यागी]

है, इसमें तथ्य नहीं हैं, सत्यता नही है । मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की बातें दुनियां को भुलावे में नहीं डाल सकती हैं। दुनिया के सामने हमें अपने कार्यों को रखना चाहिए, और हमारे कार्यों को बताना है। यों तो सेक्रेटेरियेट में कुछ न कुछ कार्य करते ही हैं, सुबह से शाम तक कार्य होता ही है। कुछ काम का उल्लेख हो सकता है कि इतने डाकू मारे गये, सहकारी बैंक खोला गया है, लेकिन वास्तविकता क्या है ? वास्तविक महत्ता ही धन्यवाद की पात्र है।

इसके अतिरिक्त राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमने आई.ए.एस. केडर और आर.ए.एस. के केडर बनाये हैं और इस वर्ष आर.ए.एस. और आर.पी.एस. के इम्तिहान लिये। वास्तवमें यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर इन सब चीजों का विश्लेषण किया जाय, इसके अन्दर जा कर देखा जाय कि इसका नतीजा क्या हुआ, इस पर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने इस रूप को देखा जिस रूप की वजह से यह समस्या बढ़ गई हैं। कुछ अफसरों की तनख्वाह ३००से४०० थी उनकी हजार–बारह सौ की तनख्वाह कर दी गई । उनका केडर आई. ए. एस. का हो गया और उनको क्लेक्टर बना दिया गया; लेकिन आपने यह नहीं देखा कि हमारी एफिशियेन्सी कितनी बढ़ी है। आई. ए. एस. बनाने के बाद जिन लोगों को आर, ए. एस में रखा है उनसे भी वही काम लिया जा रहा है लेकिन आई. ए. एस को तनख्वाह ज्यादा मिलती है तो उनके दिलों पर क्या बीतती है। आर. ए. एस. ऑफिसर यह समझता है कि काम वह वही कर रहा है लेकिन उसको वह तनख्वाह नहीं दी जा रही है। एक डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर यह देखता है कि जो उसके नीचे था और जिसकी अपील मैं एज. ए. क्लेक्टर (as a Collector) सुनता हूँ उनको तो बारह पन्द्रह सौ मिलते हैं और मुझे छै सात सौ ही तनख्वाह मिलती है। उनको हार्ट बर्निंग (heart burning) होता है और हार्ट बर्निंग का एफिशियेन्सी पर कितना असर पड़ता है। यह खुश होने की जरूरत नहीं है। आपने आई. ए. एस. बनाये लेकिन आई. ए. एस. बनने के बाद कितनी एफिशियेन्सी इन्ट्रोड्यूस हुई है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में यह देखने की बात है। मैं यह निवेदन करूँगा इस सदन से माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा कि आई. ए. एस. का केडर बनने के बाद या आर. ए. एस. या आई. पी. एस. के केडर बनने के बाद किसी तरह की कोई एफिशियेन्सी)आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आई हो, यह जनता का कोई भी आदमी सार्टीफिकेट देने को तैयार नहीं है, बल्कि दिन–प्रतिदिन हमारी एफिशियेन्सी गिरती जा रही है। दिन–प्रति दिन एडमिनिस्ट्रेशन में डिटेरियोरेशन (deterioration) हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि आज ऊपर से नेपोटिज्म और फेवेरेटिज्म और सर्विसेज को डिमोरेलाइज़ करने का तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्विसेज़ में इन्टर्फियरेंस बढ़ रहा है। यहां तक कि बहुत सी जगह कांग्रेस के अध्यक्ष जाकर कहते हैं कि इस काम को ऐसा नहीं करें। उससे उन लोगों के दिलों में काम करने में जी नहीं लगता है । उनके ऊपर यह डर रहता है कि कहना नहीं मानेंगें तो खराब जगह तब्दील कर दिये जायेंगे। आज उन लोगों को कॉस्टीट्रयुशन की गारन्टी जरूर है, लेकिन यह बात उनके हाथ में जरूर है कि जिस जगह चाहें ट्रान्सफर कर सकते हैं, और किया जा सकता है। मिनिस्ट्री के बदलने पर ट्रान्सफर की बड़ी २ लिस्टें हमारे सामने आई हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि ट्रान्सफर से कितना नुकसान होता है। उन लोगों के दिल मर जाते हैं। उनके भी बालबच्चे हैं। उनका कभी जनवरी में ट्रान्सफर होता है तो कभी जुलाई में ट्रान्सफर होता है और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है

[श्री वेदपाल त्यागी]

कि एक एक साल में ३-४ ट्रान्सफर्स होते हैं। वे न तो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और न काम में उनकी तबियत लगती है और न वे काम को समझ सकते हैं।

यह जो तरक्की की चीज का उल्लेख किया गया है यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से जमाते कि लोगों में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास जमता कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को साउन्ड रूप से चलाते हैं। यह कहा जाता है कि हम मिनिस्ट्री में अभी आये हैं, हमारी इसकी जिम्मेवरी नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप पर उसकी भी जिम्मेदारी थी और इसकी भी जिम्मेदारी है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि वे वही तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अभी तक चले आ रहे हैं। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि बजाय यह लिखने के कि आई. ए. एस. और आर. ए. एस. के केडर बनाये, अगर यह लिखते राजप्रमुख अपने अभिभाषण में कि किसी तरह का कोई इन्टरफियरेन्स सर्विसेज के वर्क में नहीं होगा, उसनें वह किसी रूप में नहीं किया जायगा, तो वास्तव में हम यह समझते कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को ऊंचा लाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ऊंचा चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़े दिन हुए यहां पर जयपुर हाई कोर्ट से फैसला हुआ है जिसमें कोटा के कांग्रेस प्रेसिडेन्ट ने अधिकारियों को यह चिट्ठी लिखी थी कि जो मकान बना रहा है उसको रोक दिया जाय। उनकी चिट्ठी के आधार पर इमारत का बनना रोक दिया गया, हालां कि कानून में उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि इस प्रकार से रोकने का कोई अधीकार नहीं है। कॉंस्टिट्यूशन में सिटिजन्स (नागरिकों) को अधिकार दिया गया है कि वे अपने फंडामेन्टल राइट्स का हस्तेमाल कर सकते हैं। यही कारण है कि इस मुकद्दमे में उन अधिकारियों से पर्सनल कॉस्ट दिलाई गई है। कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को यह कहा गया है कि आप पर्सनली कॉस्ट दीजिये, स्टेट से नहीं। इन अधिकारियों ने कॉंग्रेस प्रेजिडेन्ट के कहने पर इमारत बनाना रोक दिया था, (शेम, शेम) मैं इस तरफ सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूँगा, उधर बैठने वाले सदस्यों का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यदि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप (tone up) नहीं किया और सर्विसेज को यह आवश्वासन नहीं दिया कि वे किसी के इन्टरफियरेन्स को बर्दाश्त न करें और यदि कोई इन्टरफियरेन्स करना चाहता है और वे उसको करने नहीं देते हैं तो उनकी रक्षा करने के लिये आप लोग हर समय तैयार हों, तब तक आपका एडमिनिस्टेशन ठीक नहीं हो सकेगा, न आपको इससे फायदा होगा और न एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा। यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करना चाहते है तो आपको उसे टोन अप (सुव्यवस्थित) करने की जरूरत है।

आप यह कहते हैं कि हमने इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया है और इसके लिये इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन की स्थापना की है। यह तथ्य की बात है कि इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन नाम की एक स्टेचुटरी बोर्ड बनाई गई है जिसको १ करोड़ रुपये दिये गये हैं। रिजर्व बैंक ने भी इसको कुछ रुपये दिये हैं और राजस्थान सरकार ने भी रुपये दिये हैं, लेकिन जब हम इसके कांस्टिट्यूशन को देखते हैं, इसके पर्सनल्स को देखते हैं तो हमें दुख होता है। मैं निवेदन करूंगा कि बोर्ड के चेयरमेन पर राजस्थान सरकार के लाखों रुपये कर्ज हैं। जब हमारे यहां अलग अलग युनिट्स थे तब उन्होंने लाखों

[श्री वेदपाल त्यागी]

रुपये सरकार से कर्ज के तौर पर लिये थे और एक पैसा भी वापिस नहीं दिया। वे लोग बोर्ड के चेयरमेन बनाये जा रहे हैं जिन्होंने हमारे रुपयों के साथ खिलवाड़ की है। उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे रुपयों का सदुपयोग करेंगे। आप यह कहते हैं कि छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज का भी निर्माण किया जायगा, लेकिन छोटी इन्डस्ट्रीज उन लोगों के लिये बनाई जायेंगी जो उनके रिश्तेदार हैं या पिट्ठू हैं। यह भी मैं मान सकता हूं कि उन इन्डस्ट्रीज से कुछ लोगों को फायदा होगा। लेकिन आज जो नारा हमने अवाडी कांग्रेस में लगाया है कि सोशियल पेटर्न पर हम चलना चाहते हैं तो उसका नमूना यह नहीं होगा। सोशियल पेटर्न का यह नमूना नहीं होगा कि यह काम हम इतने बड़े केपिटेलिस्टों को एन्ट्रस्ट करदें।

अभी हमने देखा कि खादी बोर्ड बनाया गया है। उसमें भी यही बात सामने आ रही है। एक टांटियाजी या और किसी श्रीमान्जी के सुपुर्द इसे कर दिया है और कह दिया है कि वे लोग रुपये खर्च करें। हो सकता है कि मारवाडी रिलीफ सोसायटी में उन्होंने अच्छा काम किया हो, लेकिन सरकार के रुपये इस तरह से उन लोगों के हाथ में दे देना मुनासिब नहीं है। इसके चेअरमेन सिर्फ मिनिस्टर रहेंगे और बाकी लोग उन्हीं केपिटेलिस्टों के रहेंगे। वे लोग उन रुपयों का दुरुपयोग करें या न करें लेकिन यह सोशियेलिस्टिक पेटर्न का रूप नहीं है। यह सोशियेलिस्टिक पेटर्न के नाम पर केपिटेलिस्टिक पेटर्न बनाया जा रहा है और उन केपिटेलिस्टों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको उभारा जा रहा है कि वे आकर अपने हित कायम रखें। यह चीज ऐसी नहीं है कि जिस पर हमारी सरकार आज गर्व कर सके।

इसके अतिरिक्त माननीय राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये हम पॉवर का डिसेन्टर्लाइजेशन कर रहे हैं। ग्राम पंचायतें बनाई जा रही हैं, जगह जगह पंचायतों के इलेक्शन्स हो रहे हैं और डिस्ट्रीक्ट बोर्डस के इलेक्शन होंगे। इस तरह से हम पॉवर को डिसेन्टर्लाइजेशन करेंगे। वैसे तो वास्तव में यह ठीक है कि ग्राम पंचायतें बन रही हैं, लेकिन जिस रूप में ग्राम पंचायतों का निर्माण हो रहा है वह नग्न रूप सदन के सामने आवे तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों की यह राय होगी कि ये डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर सकेंगी। गंगानगर के चुनावों की कई बातें सुनने को मिली हैं। आंखों देखा हाल तो गंगानगर से आये हुए लोग ही बयान करेंगे, लेकिन यह निश्चय है कि सत्ता का दुरुपयोग अपने आदमियों को रिटर्न करवाने के लिए हो रहा है। यह वास्तव में एक खटकने वाली चीज है। क्या सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी सुरक्षित है? मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के चुनाव नियम बनाये हैं उनमें बहुतसे लूप होल्स है। इनमें सत्ताधारियों की कहीं पकड़ नहीं होती। जो वहां जाकर चुनाव कार्य-सम्पन्न करते हैं उनके खिलाफ कई जगहों से शिकायतें आई हैं, जिनकी वास्तविकता का पता तो जांच करवाने से ही चलेगा, लेकिन यदि आप उन्हीं लोगों से जांच करवायेंगे जो यह कहते हैं कि हमको यह हिदायत है कि फलां आदमी को हराओ, यदि उन लोगों के सुपुर्द जांच का कार्य करेंगे तब तो सच्चाई आपके सामने नहीं आयेगी। इस तरह के इन्स्टान्सेज भी मौजूद हैं कि एक आदमी को ११०० वोट मिले और दूसरे को ३००, लेकिन ३०० वोट लाने वाला सक्सेसफुल डिक्लेअर कर दिया गया। इस तरह की मन-मानी की जा सकती है

[श्री वेदपाल त्यागी]

क्योंकि इसका रेकार्ड नहीं रखा जाता। जब शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि हारने वाले ही शिकायत करते हैं, जिनके पीछे बहुमत नहीं होता है वे ही शिकायत करते हैं। यह ठीक है, लेकिन हारने वालों में से वे ही शिकायत करते हैं जो नाजायज तौर से हराये जाते हैं, जो सच्चाई पर होते हैं वे ही झगड़ते हैं। यदि इस प्रकार की हरकतें राज्य के कर्मचारी करते रहे और ऊपर से उनको प्रोत्साहन मिलता रहा तो मैं यकीन दिला सकता हूं कि यह डेमोक्रेसी नहीं टिक सकेगी। आज हमारी आंखें लगी हुई हैं आंध्र की ओर, जहां नये चुनाव हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां गरीबी बहुत है। पंच वर्षीय योजना चल रही है, लेकिन गरीबी बढ़ रही है। अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था बेकारी ज्यों ज्यों बढ़ रही है त्यों त्यों लोगों का कॉम्युनिज्म की तरफ अट्रेक्शन होता जा रहा है। हम यह जानना चहते हैं कि आंध्र में क्या नतीजा निकलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आंध्र में चाहे जो हो, कुछ भी नतीजा हो लेकिन यदि इस तरह की हरकतें हमारे यहां होती रहीं, लोग शिकायतें करते हैं और आपको उनकी परवाह नहीं है तो मैं आपको हिदायत कर दूं कि पब्लिक आप को मानने वाली नहीं है (हियर, हियर)। आप फेक्ट्स को इगनोर नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि अखबार निकालनेवाले यों ही चिल्लाते है। यह कह कर आप बच नहीं सकते। आपको अपने आपको निर्दोष साबित करना पड़ेगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जो चिल्ला रहे हैं उनके पीछे मेजोरिटी नहीं है। जब हमारे यहां जयपुर में इलेक्शन चल रहा था तब एम. एल. ए. और डिप्टी मिनिस्टर के बीच कुछ तनाव हुआ था। सचाई किधर है, यह मैंने जाकर नही देखा; लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेन्ट्स निकालना मिनिस्टर के लिये शोभा की बात नहीं है। इसी तरह का स्टेटमेन्ट दूसरों के लिये क्यों नहीं निकला। जनमत ऐसा क्यों बनता है? फलां मिनिस्टर इस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है, यह क्यों कहा जाता है? कहीं आप सत्ता हाथ में लेकर इन छोटे-छोटे चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं? गंगानगर में ५-६ ऐसी पंचायतें थीं जहां कांग्रेस के सदस्य नहीं जीत सकते थे। आपने उन स्थानों पर इलेक्शन्स को पोस्टपोन करवा दिया। यदि मिनिस्टर साहब चाहें तो मैं उन स्थानों के नाम भी बता सकता हूं। अब यह सुनते हैं कि वहां पर नोमिनेशन्स होने वाले हैं। इस प्रकार की हरकतों से आप बुनियादी उसूलों पर कुठाराघात करते हैं, वास्तव में जो सत्ता का उपयोग करते हैं यह बोनाफाइडी नहीं है। वास्तव में यदि आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़े और मजबूत हो तो छोटी-छोटी बातों में हथकंडे काम में नहीं लाना चाहिये, वरना डेमोक्रेसी को खतरा है। डेमोक्रेसी को खतरा होने का नतीजा यह होगा कि डेमोक्रेसी उठ जायगी।

इसके अलावा लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या पर मैं अपने विचार अवश्य प्रगट करना चाहता हूं। श्रीमन् राजप्रमुख ने कुछ आंकड़े देकर यह प्रकट किया है कि हमारे यहां लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या दिन-प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। क्योंकि डाकू अनैतिक कार्य करते हैं, वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, और इस तरह (डाकू) लोगों का मारा जाना एक अच्छी बात है। यह हर्ष का विषय है कि ५२ के वक्त जबकि सदन का जन्म हुआ था, उस वक्त उग्र रूप से जैसी समस्या थी वैसी अब नहीं है। ५२ में उधर बैठने वाले लोगों का इशारा इधर बैठने वाले लोगों की तरफ था कि इधर बैठने वाले लोग इसे पनपा रहे हैं। पर कल ही मैंने एक पत्र में पढ़ा और एक माननीय

मंत्री महोदय के लिये पढ़ा; उनके लेटर का फोटो था कि फलां आदमी है उसका वकील हमको बदलना है, उस आदमी का परिचय था कि वह डाकू है। मैं निवेदन करता हूं कि यह ठीक है, गर्व की बात है कि आपने इतने डाकू पकड़े हैं, पर इतना प्रोत्साहन डाकुओं को हमारे लोगों के द्वारा जिनके हाथ में सत्ता है। दिया जाता है तो यह कोई गर्व की बात नहीं ; यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके...

श्री मथुरादास माथुर—Does the Hon' ble Member rely on the statement made by him ?

श्री एच. के. व्यास—The Member can certainly make a Statement on the printed matter which is widely circulated and it is for the Government to contradict it.

श्री वेदपाल त्यागी (जारी)—अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो यह एतराज नहीं करते। मैं अभी बता देना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि अगर वह बात वाकई में गलत है तो न केवल यहां पर स्टेटमेंट देकर गलत बतायें बल्कि जिसने इसे शाया किया है उस पर मुकदमा चला कर प्रोसीक्यूट करें उसे और फिर यह साबित करें कि अखबार में जो उल्लेख हुआ है वह गलत है।

बात यह है कि एक लेटर सामने आया है और उस पर श्री कुंभाराम आर्य के दस्तखत हैं। उसका उल्लेख करते हैं तो उसको गलत साबित करने का तरीका यह नहीं कि आप दूसरे स्टेटमेंट दे दें। इसके तरीके हैं जिससे कि इसे गलत साबित किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खाली उस अखबार में शाया हुआ है, उसी तरफ मेरा ध्यान गया हो और मैंने यह बात कही हो, यह बात नहीं है, एक और दूसरा इन्सीडेन्ट भी मेरे ध्यान में आया है, वह इन्सीडेंट मैं क्वोट करता हूं। अभी कुछ दिनों पूर्व खबर निकली कि राजगढ़ से एक सेठ के लड़के को उड़ाया गया और थोड़े दिनों बाद वह अपने घर आया। रेन्सम हजारों रुपयों की तादाद में उस लड़के को छुड़ाने के लिये दिया गया, पर कौन छुड़ाने वाले हैं; अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। चूरू राजगढ़ जाइये वहां आम लोगों में यह चर्चा है कि इसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे और इसीलिये पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही है क्योंकि वह जान रही है कि उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो ऊपर से कार्यवाही होगी। अगर सत्यता, वास्तविकता इन बातों में है तो यह कोई गर्व की बात नहीं कि हमारी पुलिस ने कुछ डाकुओं को भरतपुर में पकड़ लिया है या और कहीं पकड़ लिया है।

ऐसे जो एलीमेंट्स हैं उनको पकड़ना चाहिये, गिरफ्तार करना चाहिये; उनको सजा देनी चाहिए। जो लोग हमारे नहीं हैं उनको मार गिरावें और जो हमारे हैं उन्हें संरक्षण दें; यह कोई गर्व की बात नहीं है। इस समस्या का तो पूर्ण रूपेण हल उसी वक्त होगा जब हम यह कह सकें कि आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्लीन है, हम क्लीन हैं, ऐसा कोई गेंग न हो। तभी हम कह सकते हैं कि इस समस्या का हल किया गया है। आपने उल्लेख कर दिया कुछ डाकुओं को मार कर आज करोड़ों रुपये आप पुलिस पर खर्च

[श्री वेदपाल त्यागी]

करते हैं। डाकुओं को मारने और पकड़ने के लिये करोड़ों रुपये खर्च करते है; पुलिस की ड्यूटी है कि उनको मारे। पर एक भी घटना ऐसी होती है कि राज्य-सत्ता जिनके हाथ में है, उनका इन डाकुओं के संरक्षण में हाथ है तो इसको क्लीअर करने की जरूरत होती है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या राजस्थान सरकार के सामने है, राज्य के सामने है, जिसका उल्लेख श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है। वह समस्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की गिरती हुई कीमतों की समस्या है, जो ग्रामीणों के लिये और राज्य के लिये एक भयंकर समस्या है।

आज दूसरी चीजों की कीमतें वार के खत्म होने के बाद जो बढ़ी हुई थीं वही अब तक मौजूद हैं; इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। पर जो हमारी एग्रीकल्लर प्रोड्यूस हैं, जिनको किसान पसीना बहा कर पैदा करता है, उनकी कीमतें घट गई हैं। जिस इलाके से मैं आया हूं वहां कीमतें इतनी घट गई हैं कि काश्तकारों के पास कटना (मालगुजारी) तक देने को पैसा नहीं है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

पेप्सू में एक रिजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदेगी और वितरण करेगी ताकि वह समस्या उग्र रूप धारण नहीं करले।

श्रीमन् राजप्रमुख ने इस समस्या का अपने अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया है। इससे ग्रामीण जनता महसूस करती है कि राज्य सरकार हमारे प्रति उदासीन है। तो ग्रामीण जनता जिसके बारे में कि हमें सबसे पहले ख्याल करना चाहिये, उनका भी उल्लेख राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में नहीं किया है तो फिर उनको कैसे धन्यवाद दें।

एग्जीक्युटिव से जूडिशियरी को अलग करना जरूरी है, जूडिशियरी बिल्कुल सेपरेट हो ताकि आम लोगों को यह विश्वास हो कि जो अधिकार हमें कॉन्स्टीट्यूशन ने दे रखे हैं उनकी रक्षा होगी। जूडिशियरी नीचे लेवेल पर इस प्रकार से कार्य कर रही है जिससे इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वह बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट कार्य कर रही है, उन पर दबाव आता है। इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गंगानगर से आने वाले जो माननीय एम. एल. ए. हैं, उन पर ७ तारीख को ३ गोलियां चलाई गई। उन्होंने ७ तारीख को रिपोर्ट पुलिस में लिखाई। ३ घंटे बाद पुलिस आई और उन्होंने नाम बताया कि इन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई। तरीख ७ और ८ को कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, एस. पी. कहते हैं कि डी. आई. जी. से इस सिलसिले में बात-चीत करलें। आखिर ८ को २ आदमी गिरफ्तार होते हैं। १८ तारीख को चालान होता है तो वे लोग कहते हैं कि २४ तारीख को मिनिस्टर आने वाले हैं, हमारी जमानतें हो जायेंगी और २४ तारीख को मिनिस्टर साहब जाते हैं और उनकी जमानतें हो जाती हैं।

[श्री वेदपाल त्यागी]

(ऑपोजिशन की ओर से 'शेम-शेम' की ध्वनि)

वे लोग दुहाई देते हैं मिनिस्टर साहब की। मिनिस्टर साहब के आने से उनकी जमानतें हो गई, यह बात मैं नहीं कहता। आज इस चीज की जरूरत है कि जुडिशिअरी को एग्जिक्युटिव से अलग किया जावे ताकि अधिकारी किसी के दबाव में नहीं आवें और दबाव से कोई वर्क नहीं हो और इन्साफ बगैर किसी भेद-भाव के प्योरली हो सके। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार कई बड़ी-बड़ी जो समस्यायें हैं उन पर श्रीमन् राजप्रमुख शान्त हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि वे इस योग्य नहीं हैं कि हम उन्हें धन्यवाद दें। हां, इस बात पर जरूर कि आपने अंग्रेजी से बदल कर अंग्रेजी मिश्रित हिन्दी को इस बार अपना लिया, अगर इसके लिये धन्यवाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री एच० के० व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, कल और आज दोनों दिनों से मैं बहुत उत्सुकता से यह राह देख रहा था कि हमारे सदन के सदस्य जो तैयार हुए हैं, शायद वे चुने नहीं गये लेकिन राजस्थान राजपत्र में उनके नाम के आगे एम. एल. ए. की डिग्री लगी है कहीं सदन में शपथ लेने के लिए नहीं आ जावें। मेरा यह कहने का मतलब श्रीमान् गोकुलभाई भट्ट के नाम से है जिनके नाम को आपने गजट में शाया करते समय एम. एल. ए. की डिग्री दी। मुझे इस बात का गर्व हो रहा था कि कहीं वे राजस्थान सरकार की मदद की वजह से शपथ लेने के लिए न आ जावें। मगर वे नहीं आये अब उनकी एम. एल. ए. की डिग्री का क्या होगा यह तो सरकार जाने या सदन में बैठने वाले कानून के विशेषज्ञ ही जानें! आया कॉन्टेम्प्ट की कार्यवाही होगी या नहीं...

श्री मथुरादास माथुर—It denotes 'Member of Leprosy Association'.

श्री वेदपाल त्यागी—It applies to my friends also sitting on that side.

श्री मथुरादास माथुर—Matters relating to Lepers Association.

श्री एच. के. व्यास—मैं यह कहूंगा कि उनके नाम के आगे सदस्य विधान सभा भी लिखा है, उसका क्या इलाज होगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित प्रेस नोट जो भेजा गया उसमें सदस्य विधान सभा लिखा है, उसकी जांच माननीय सदस्य करेंगे तो मालूम होगा।

श्री मथुरादास माथुर—M. L. A. is not a degree.

एक माननीय सदस्य—डिग्री नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—Order!

श्री एच. के. व्यास—डिग्री तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों को इससे मोह बहुत ज्यादा है।

श्री मथुरादास माथुर—आपको भी बहुत ज्यादा मोह है ।

श्री एच. के. व्यास—कल श्रीमन् राजप्रमुख के हिन्दी-अंग्रेजी मिश्रित भाषण को सुनने के बाद यह कहें कि कम से कम उनको इस भाषा के लिये तो धन्यवाद दिया जावे । अगर उनको इस प्रकार की हिन्दी अंग्रेजी मिश्रित भाषा के लिये धन्यवाद दिया जावे तो जिन्होंने फौज में लोगों को थोड़ी बहुत हिन्दी सिखाई वे भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं । हां, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जो भाषा उन्होंने बोली, उसमें मुझे ऐसा मालूम हुआ कि हिन्दी की हिन्दी जरूर की गई । यह आकस्मिक बात नहीं है । यह अचानक हुई हो, ऐसी भी बात नहीं है । जो सर्क्यूलर राजस्थान में निकला कि काम हिन्दी में हो वह सर्क्यूलर अलबत्ता अंग्रेजी में निकला और मुख्य मन्त्री के दस्तखतों से निकला और इस राजस्थान में हिन्दी की हिन्दी किस हद तक होती है उसकी एक बहुत ही गम्भीर मिसाल मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके सामने रखता हूं । राजस्थान सरकार के अक्टूबर ३१, १९५३ के राजपत्र में पंचायत एक्ट छपा है और उसी पंचायत एक्ट की धारा ८ है उसका ताल्लुक एपोइन्टमेंट ऑफ पंचाज से है; उसमें यह लिखा है कि चीफ पंचायत ऑफिसर पंच को नामजद कर सकता है, प्रोविजो यह है कि:—

'Provided that the person so appointed shall not hold office for a period exceeding six months unless duly elected.'

२६ दिसम्बर १९५३, को यह पंचायत एक्ट राजस्थान के राजपत्र में हिन्दी में प्रकाशित होता है । उसकी धारा ८ में चीफ पंचायत ऑफिसर द्वारा एक अथवा एक से अधिक............नियुक्त करेगा, ऐसा लिखा है और इस प्रकार से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति ?.........। इसमें प्रोविजो गायब है । अंग्रेजी के एक्ट में धारा ८ भी है और प्रोविजो भी है लेकिन हिन्दी के एक्ट की धारा ८ में प्रोविजो गायब है । दोनों एक्ट राजस्थान राजपत्र में छपे हैं । एक अक्टूबर में छपा है और दूसरा दिसम्बर में, मगर हिन्दी और अंग्रेजी में इतना फर्क हो जावे और कानून को हिन्दी में करने में इस प्रकार का प्रोविजो गायब हो जावे तो राजस्थान सरकार को इसके लिए बार बार और शत बार बधाई है । यह निकम्मेपन का और कानून के मामलों में अनजान में या जानबूझ कर गड़बड़ करने की बात है और राजप्रमुख के भाषण की भाषा से यह प्रतीत होता है कि हिन्दी की हिन्दी अवश्य की गई है । मैंने खास तौर से इस पर इसलिये कहा कि मेरे मित्र जो जोधपुर कांस्टिट्युएन्सी से आये हैं उन्होंने राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का वातावरण बनाने की कोशिश की कि श्रीमन् राजप्रमुख ने इस बार हिन्दी में भाषण दिया । उन्होंने जो कुछ कहा उसमें तथ्य तो कम नजर आया, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता क्योंकि उन्होंने तीन साल के बाद जो नहर बनेगी और उससे जो पानी आवेगा और उससे खेती लहरावेगी उसके स्वप्न में होने वाली चीज की मौज में लौट कर अपनी राय व्यक्त की । इसके अलावा १॥ बजे तक कुछ लोग खींचा तान में लगे हुए थे इसलिये वे इसे ठीक नहीं कर सके हों । लेकिन श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण जिन लोगों ने तैयार किया उनके प्रति सहानुभूति उसमें रही, किन्तु खामियों के लिए शिकायत करने की गुंजायश है । इसलिये मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करूंगा । जिसके लिए राजप्रमुख को धन्यवाद देने की बात कही जाती है, उसको देखने से उसकी सेन्सर (Censure) करने और आलोचना करने, उनके भाषण

[श्री एच० के० व्यास]

की कटु आलोचना करने की स्थिति पैदा होगी। उनके सारे के सारे भाषण को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होगा माननीय उपाध्यक्ष, जैसे एक जमाने में नीरो के बारे में कहावत कही गई है कि रोम का राजा नीरो जब रोम जल रहा था, रोम का नगर जल रहा था, उस समय सारंगी के तार बजा रहा था। रोम जल रहा था लेकिन नीरो के तार तो बज रहे थे। राजस्थान की वर्तमान सरकार का यह हाल है कि एक के बाद एक भयंकर समस्या सरकार के सामने खड़ी हो रही है। राजस्थान सरकार आगे कार्य करने की जो योजना है उसके लिये कह रही है। राजस्थान में चैनल बनेगी। उस पर २ करोड़ ५७ लाख रुपया खर्च होगा, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी रुपया मिल जावेगा लेकिन यह कब मिलेगा और कब होगा ?

जहां कुछ किया है उसकी सत्यता के बारे में मैं ५-७ नजीरें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जोर तो लॉ एण्ड ऑर्डर पर दिया गया और मैंने कई बार भाषण में डकैतियों और चोरियों के फैक्ट्स एण्ड फीगर्स को, परसेन्टेज के केलकुलेशन में देखा। २५ फीसदी, ३५ फीसदी कम हुए। मेरी समझ में नहीं आया कि चोरियां और डाकुओं का परसेन्टेज कैसे किया गया ? कितना माल ले गये, कितने गांवों को लूटा, कितना लोगों का नुकसान हुआ, आपने कौनसे परसेन्टेज से केल्कुलेट किया ? जहां तक मैं समझ पाया हूं, घटनाओं के आंकड़ों से यह परसेन्टेज निकाला गया है और इस परसेन्टेज को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि राजस्थान सरकार की हालत एक उस वैज्ञानिक जैसी है जो नदी के किनारे पर जाकर खड़ा होता है और सोचता है कि खड़ा होने के बाद नदी पार करना है; कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। दस जगह नदी को नपवाता है, किनारे पर ३ फीट गहराई है, आगे जाकर १५ फीट और आगे जाकर तीस फीट गहराई है और उसका औसत लगाता है कि किनारे पर छः इंच और कुल मिलाकर ४॥ फीट औसत आती है। मैं छः फीट का वैज्ञानिक हूं और नदी की औसत गहराई ४॥ फीट है, मैं पार कर लूंगा। किन्तु वह चार-पांच फीट चला और आगे जाकर नदी की धारा में बह गया। वैसे ही आंकड़े नदी की गहराई के समान राजस्थान सरकार ने चोरियों और डकैतियों के लिए बनाये, ऐसा मालूम होता है; जो वस्तु स्थिति से मेल नहीं खाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी अखबारों में पढ़ा कि ४० हजार का पीपला में डाका पड़ा है। केवल डाका ही पड़ता हो, यह बात नहीं है लेकिन गांवों में १॥ बजे, २ बजे तसल्ली से डाकू लोग आते हैं, घंटे दो घंटे तक गांवों, कस्बों को लूटते हैं, शाम को आराम से जाते हैं। किसी की बस रास्ते में मिल जाय तो बस को पकड़ ले जाते हैं और गांवों के नजदीक छोड़ते हैं। दूसरे दिन पुलिस जीपों को लेकर जाती है। बकौल खेतसिंह जी जीपें अच्छी होती होंगी, जीपें अच्छी होने वाली नहीं हैं, होती हैं और मिली हैं किंतु उसके पीछे तो एक सतत् प्रयत्न होता है और उसका आंकड़ों से सबूत नहीं मिलेगा। किंतु सबूत तो इस बात से मिलेगा कि छः महीने में कितनी वारदातें हुई हैं, माली कितना नुकसान हुआ है, इन्सानों की जानों का कितना नुकसान हुआ है और मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे आंकड़े प्रस्तुत करें कि पिछले छः महीने में कितने माल का नुकसान हुआ है, घटनाओं के रुख में कितनी कमी हुई है ? लॉ एन्ड ऑर्डर की वस्तु स्थिति तब उनके सामने आयगी।

अभी अभी एक चीज का जिक्र किया गया। मेरे माननीय मित्र नाराज हो गये, गुस्से हो

[श्री एच० के० व्यास]

गये। किंतु मैं यहां उसका जिक्र करूंगा। लॉ एण्ड ऑर्डर का राजप्रमुख के भाषण में जिक्र होता है कि लॉ एन्ड ऑर्डर सुधरा है और सरकार ने सतत् प्रयत्न किया है, ऐसा उनका कहना है। क्रांतिदूत नाम के अखबार ने राजस्थान के मन्त्री के ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि वे डाकुओं से सलाह मशविरा करते फिरते हैं, वकील रद्दोबदल करते फिरते हैं। या तो अखबार पर मुकदमा चालू करें या सोच लें कि जिनका डाकुओं के वकील बनने का काम बन गया है वे लॉ एन्ड आर्डर क्या रखेंगे। इसमें जांच पड़ताल की जाय। एक बात है कि अगर गैर जिम्मेदारी से चीज छपी है तो उसका सुबूत दीजिये। अगर जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुकदमा चलायें और अगर मुकदमा नहीं चलाते हैं तो सुबूत दीजिए कि दरअसल हम ऐसे नहीं जैसा कि दुनिया हमारे बारे में कहती है। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये घटनायें मामूली घटनायें नहीं हैं। अभी दस दिन पहले गंगानगर की घटनाओं के बारे में सुना। उदयपुर की घटनाओं और बनेड़ा की घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। उधर बैठने वाले माननीय मित्र के साथ कैसा व्यवहार हुआ है? समाज के विरोधी लोगों ने घर से उठाकर बुलाया और बुरी तरह से मारा। भूलते हैं क्या, जूतों से थप्पड़ों से उनको मारा। थाने पर रिपोर्ट लिखायी। लेकिन शर्म की बात है कि राजस्थान सरकार अपने सहयोगी के लिए इन्तजाम नहीं कर सकी। उधर बैठने वाले मित्र को दिन दहाड़े पीटे और शिकायत करें, दस दिन हो जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं।

("शेम शेम" की विपक्ष से आवाज)

इसका ताल्लुक है लॉ एन्ड ऑर्डर से। श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि लॉ एन्ड ऑर्डर में सुधार हो गया है। तो उसका नमूना आपने इतना देख लिया है।

मैं इसी प्रकार श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण का एक दूसरा अंश अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कितना टाइम लेंगे?

श्री हरिकृष्ण व्यास : टाइम तो बंधा ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो लिस्ट आयी है उसमें बोलने वाले काफी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास : मेरी अर्ज है कि......

श्री उपाध्यक्ष : काफी तादाद में बोलने वाले हैं इसलिए......

श्री हरिकृष्ण व्यास : मैं बोल चुकूं तब लिस्ट का ध्यान रखें।

मैं अर्ज कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, कि इस भाषण में कहा गया......

श्री उपाध्यक्ष : जो आपके मेन स्पीकर थे धन्यवाद के प्रस्ताव के, उसी अन्दाज से आप बोलेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास : अगर धन्यवाद देने वाले इसलिए जल्दी बैठ जायं कि उनके धन्यवाद कहने के पक्ष में तथ्य न हो, इसलिए मेरे साथ यह ज्यादती क्यों हो कि धन्यवाद न देने वाले के पक्ष में भी तथ्य न होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसका अन्दाज तो होजाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास : थोड़े में ही समाप्त कर दूंगा, आप फिक्र न करें।

में अर्ज कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष, कि इस भाषण में यह दावा किया गया है कि मजदूरों की हालत सुधारने के लिए दो हजार मकानों की योजना भारत सरकार को भेज दी है। आप गौर फरमाइये कि क्या किया गया है कि दो हजार मकान बनाने की योजना तैयार करके भारत सरकार को भेज दी गई है और धन्यवाद दो। मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार सफाई पेश करे, एक्स्प्लेनेशन दे कि तीन साल तक बैठे बैठे उन्होंने क्या किया हैं? मक्खियां मारी है। यह मकान बनाने की योजना भारत सरकार ने सन् ५० में शुरू की थी। सन् ५०–५१ में बम्बई राज्य ने योजना पेश कर दी। इतना ही नहीं और डेढ करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से मदद के रूप में ले लिया और लगातार मजदूरों के मकान बनाने का कार्य चला। राजस्थान सरकार ने पूरे तीन साल तक यह काम किया कि योजना तक पेश नहीं की और चार साल में जाकर योजना पेश की और भारत सरकार की स्कीम के चालू साल में राजस्थान सरकार की यह हिम्मत होती है। तीन साल तो कुछ नहीं किया इसलिए सदन से माफी मांगने के लिए दो हजार मकानों की योजना केन्द्रीय सरकार को भेज दी और फिर धन्यवाद दें। ऐसा धन्यवाद देना पार्टी के लोगों को मंजूर हो सकता है लेकिन अपना दिमाग अपने कन्धों पर रखने वाले लोग धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं।

मैं और अर्ज करूं माननीय उपाध्यक्ष, कि भाषण में यह कहा गया है कि हमारे बन्दोबस्त का काम करीब २ पूरा हो गया और करीब १४ फी सदी जमीन बन्दोबस्त करना बाकी है और शेरगढ़ से आने वाले माननीय मित्र जहां बन्दोबस्त नहीं हुआ, लेकिन बन्दोबस्त के नाम से ही जोश में आ रहे थे। बन्दोबस्त की जो समस्या है वह राजस्थान की सबसे गम्भीर समस्या है। में आपसे अर्ज करूं कि राजस्थान के अन्दर एक विचित्र हालत हो रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए राजस्व मंत्रीजी को जबाब पेश करना है। लेकिन हकीकत है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पिछले तीन साल से दौड़ लगी हुई है। लगान की दरें बन्दोबस्त द्वारा मुकर्रर होती हैं। दौड़ लगी हुई है इस रिपोर्ट में नहीं है। मैं आपको दो-चार जगहों के आंकड़े प्रस्तुत करूं। कुछ साल पहले नागौर में ३ रु० १४ आना चाही दर निकाली थी और आप देखिये कि जोधपुर में ४।।।), सोजत में ५।) पाली देसूरी में ६।।) फुलेरा के खारे पानी में ८।।), बांदीकुई से मित्र बहुत बोलते हैं वहां १३), जमुआ रामगढ़ १७) और अचरोल में २५) फी बीघा है। पच्चीस-पच्चीस रुपया फी बीघा चाही का है। यह राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर की हुई दरें हैं।

क्या इन्हीं हालतों पर नाज किया जा रहा है? इस बन्दोबस्त से दूसरी ओर क्या हालत हो रही है उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। हालत यह है कि आज अनाज के भाव जो किसानों के पैदावार की चीज है उसके भाव इस रफ्तार से गिरते जा रहे हैं जिसको राजस्थान सरकार नहीं

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सोच रही है। आज वह सरकार जो राजस्थान के किसान के नाम का ब्लेक मार्केट कर मुनाफा कमा रही है तो आज जब किसानों के ऊपर इतना जबरदस्त संकट आया है तो उनके लिये इस भाषण में एक शब्द तक नहीं। राजस्थान राजपत्र में शाया हुए भाव जो सितम्बर, १९५३ के मुकाबले ५४ तक जवार, बाजरा और मक्की के निकले हैं, जो खरीफ की फसल के पहले निकले हैं उसको देखने से पता चलता है कि उस एक साल के अर्से करीब में ३५ से ४० प्रतिशत तक भाव गिर गये हैं, जो खरीफ की फसल आने के पहले शाया हुए हैं। फसल आने के बाद नवम्बर ५४ तक बाजरा और मक्की के भाव ४७ से ५३ फी सदी तक गिर गये हैं, यह मैं राजस्थान राजपत्र में शाया हुए भावों के अनुसार कह रहा हूं। नवम्बर के बाद कांग्रेसी-पत्र राष्ट्रदूत में जो भाव शाया हुए हैं उनका मुकाबला करने से आपको पता चलेगा कि गेहूं में १७ फीसदी बाजरा में ५६ फी सदी, मक्का में ५३ फी सदी, चने में ६६ फी सदी, तिल में ६४ फी सदी कमी हुई है। यह कुछ चीजें हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसमें एक तिहाई कीमतें रह गई हैं। अभी इसी सिलसिले में मेरे एक माननीय मित्र ने कहा है कि उनके इलाके में ज्वार के भाव ३॥ और ४ रुपया मन तक गिर गये हैं। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं जैसा कि मैं अभी देख आया हूं जैतारण और ब्यावर में किसानों से बाजरा ४॥ रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है। आपने जो लगान की दर तय की है वह ६ रुपये मन से २७ रुपये मन तक है। वह दर, ४४, ४५ से लगाकर १९५१, ५२ के जमाने के भावों के अन्दाज से बनायी गयी है, जिस समय कि लड़ाई के बाद भाव काफी ऊंचे थे। उन्हीं भावों को ध्यान में रखकर ये दरें तय की हैं, ढाई साल पहले के भावों के हिसाब से ये दरें कायम की हैं। आज गेहूं का भाव १० रुपये मन हो रहा है जबकि अभी तक रबी की फसल आई नहीं है। रबी की फसल के बाद तो मालूम नहीं क्या भाव होंगे। पहले लगान दर ऊंचे थे क्योंकि भाव भी उस समय जिन्सों के ऊंचे थे। आज जबकि किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली चीजों के भाव गिरते जा रहे हैं तो हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इधर राजप्रमुख फरमाते हैं कि बन्दोबस्त का काम करीब-करीब खत्म कर दिया गया है, केवल १४ फी सदी बाकी रह गया है और इधर अनाज के भाव निरन्तर गिरते जा रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं अपने पड़ौसी प्रान्त मध्य भारत की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जहां कि सरकार ने तय कर लिया है कि यदि इससे जिन्स के भाव ज्यादा गिरे तो सरकार उनके अनाज को खरीदने की जिम्मेवारी (वह सरकार) लेती है। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि सन् ४९ के अन्दर कांग्रेसी सरकार ने लेवी की दर बढ़ाने के कारण सुवाणा में गोलीकान्ड किया था उस समय सरकार ने यह कहा था कि शहरों में रहने वालों के लिये आप अनाज पैदा करें। आज का किसान उस कान्ड को भूला नहीं है। आज जबकि किसान का भविष्य अन्धेरे में है तो हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक ओर तो यह हालत है कि किसान का जीवन दूभर होता जा रहा है और दूसरी ओर लगान की दरें सरकार इतनी ऊंची कर देती है, जो किसानों पर बड़ा संकट पैदा कर देता है। लेकिन चुप है हमारी सरकार इस मायने में। बन्दोबस्त का काम जो खत्म हो चुका है, जैसा कि राजप्रमुख के भाषण में कहा गया है। वह काम वास्तव में खत्म नहीं हुआ। जहां यह खत्म हो चुका है उन पर, उन दरों पर कई साल पहले दस्तखत हो चुके हैं और उस बीच में कीमतें काफी कम हो गई हैं। अगर इस विषय का कुछ राजप्रमुख के भाषण में जिक्र होता तो हम भी यह सोच सकते कि राजप्रमुख ने अपने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

भाषण में किसानों की भयानक स्थिति का जिक्र किया है और उनको किसी प्रकार का राहत दिया जा रहा है, लेकिन इस ओर बिल्कुल इशारा तक नहीं। यह आज हमारे राजस्थान की भयंकर समस्या है। यह हमारे किसान वर्ग के आर्थिक ढांचे को बरबाद कर रही है। इस मायने में सरकार का उदासीन रहना, सरकार की आंखें मुन्दी हुई होना रोम के नीरो से भी बदतर स्थिति को बताने वाली है; जो वर्ग किसानों के नाम पर काम कर रहा है, जो किसानों को राहत देने के नाम पर एक भी कलम नहीं चलाता। यह स्थिति हमारे बन्दोबस्त के सिलसिले में हमारे प्रान्त की है।

अब मैं एक-दो और चीजों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि सरकार इन बातों के लिये अपने आपको धन्यवाद का पात्र समझती हो। राजप्रमुख के भाषण में यह जिक्र है कि भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड कायम किया गया है। इस प्रकार की घोषणा मैंने भी राजस्थान राजपत्र में पढ़ी थी। मुझे तो यह ताज्जुब होता है कि इससे सरकार अपने आपको धन्यवाद का पात्र क्यों समझती है। दो-तीन साल से लगातार भ्रष्टाचार का सिलसिला काम कर रहा है। पहले तो राजस्थान सरकार ने एक भ्रष्टाचार समिति बनायी थी.........।

श्री कपिल देव--भ्रष्टाचार समिति नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई थी।

श्री व्यास--भ्रष्टाचार समिति, यह मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि भ्रष्टाचार समिति के अध्यक्ष की तरफ से जो पत्र मेरे पास आया है उसमें भी यही लिखा है। चाहे नाम कुछ भी हो किन्तु इस समिति के अध्यक्ष ने मुझे सूचना दी थी कि वे भ्रष्टाचार समिति के अध्यक्ष हैं। यह जो भ्रष्टाचार समिति बनाई गई उसके बाद सरकार द्वारा सारी दुनियां से अलग एक नया महकमा खोला गया जिसका नाम भ्रष्टाचार का महकमा है। यह मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं बल्कि इस विषय में मैं आपका ध्यान टेलीफोन डाइरेक्टरी के पेज ७१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस विभाग के टेलीफोन का नम्बर २०७६ है, एम्बेज़लमेन्ट डिपार्टमेन्ट। उसके लिये एक अफसर भी मुकर्रर है जिसके दफ्तर में भी फोन है और घर पर भी फोन है। पहले तो भ्रष्टाचार समिति बनी और उसके बाद भ्रष्टाचार महकमा चालू हुआ, और उसके बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड बना है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तीन साल और दो साल के अरसे में जो कमेटी बनी और जो महकमा बना, अफसर मुकर्रर हुऐ, बोर्ड बना तो क्या आज तक किसी को भी सजा हुई है ? क्या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। हकीकत तो यह है कि जो एम्बेजलमेन्ट सन् १९५०-५१ में होते हैं जैसा कि एप्रोप्रियेशन अकाउन्टस की रिपोर्ट से मालूम होगा जो कि आज ही मेरे मित्र ने सदन के सामने रखी उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उस ऑडिट रिपोर्ट का उद्धरण देकर मैं आपको बताऊं कि उस ऑडिट रिपोर्ट में पेज ३४ पर पैराग्राफ ३१ में जिक्र किया गया है कि सन् ५१ में रिहेबिलिटेशन विभाग के एक दफ्तर का इन्सपेक्शन होने वाला था तो उस दिन अचानक उस दफ्तर में आग लग गई, उसके कागजात जल गये। कुछ रुपया भी जल गया और परिणाम इसका यह हुआ कि १॥ साल का हिसाब ऑडिट नहीं हो सका। सरकार ने इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की। वह कमेटी इस नतीजे पर पहुँची कि यह आग किसी ने जान बूझ कर लगाई है और केमिकल एक्शन द्वारा लगाई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थी, लेकिन इसमें किस की जिम्मेदारी है इस पर कमेटी अपनी राय न दे सकी, चूंकि इसमें कुछ गजेटेड अफसर भी इन्वोल्व मालूम होते हैं। यह ऑडिट रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है। इसी में से में पढ़ रहा हूं। मार्च ५३ में राजस्थान-सरकार ने सूचना दी अकाउन्टेन्ट जनरल को इस रिपोर्ट के आधार पर कि चूंकि इसमें गजेटेड आफिसर्स की शिकायत है इसलिए एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के आला अफसर को यह काम सौंप दिया गया है, जांच करके वह रिपोर्ट देगा। पर आज तक उसकी जांच का नतीजा नहीं निकला। जिस दिन इन्सपेक्शन होने वाला था उस दिन आफिस में आग लगती है। इसमें सब कागज जल जाते हैं, रुपया भी जल जाता है और ५१ से ५५ तक पूरे चार साल होने आये अभी जांच पर जांच चलती चली आ रही है, पर सजा अब तक किसी को नहीं दी गई है। यदि इसी रफ्तार से कार्य हो रहा है तो मैं नहीं मानता कि सरकार क्या प्रगति कर रही है ? मैंने यह एक मिसाल दी है। इस ऑडिट रिपोर्ट में तो कम से कम ऐसी १३ मिसालें हैं कि ५०–५१ के अन्दर जो भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये उनमें से एक को भी सजा नहीं दी गई। एक मजेदार चीज़ में आपको और बताऊं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि एक श्रीमान् रिहेबिलिटेशन के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गये। इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई, केवल उनका तबादला करके तहसीलदार के रूप में धौलपुर भेज दिया। वे सज्जन धौलपुर से १॥ लाख रुपया सरकार का लेकर पाकिस्तान चले गये और राजस्थान सरकार की अभी इस पर जांच चल ही रही है। मुझे उम्मीद मालूम होती है कि यह जो नया बोर्ड बनाया गया है भ्रष्टाचार विरोधी, वह इन मामलों की जांच शुरू करेगा और ५५ में अब तक के केसों के लिए राजस्थान सरकार फिर कोई हाई पॉवर कमेटी बनावेगी और मुमकिन है इस पर भी अगर काम न चला तो अमेरिका से या विलायत से कोई एक्सपर्ट बुलाने के लिए भी निश्चय करेगी कि वह एक्सपर्ट वहां से आकर इस भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी ओपीनियन दे। छोटा सा हिसाब है, इलाज भी छोटा सा है, पर जब तक यह इलाज नहीं होगा तब तक चाहे भ्रष्टाचार कमेटी बिठाओ, जांच कमेटी बिठाओ या एक्सपर्ट बुलाओ, कुछ होने का नहीं है। वह इलाज लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और वह इलाज है कि जो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जावें उनको तुरन्त जल्दी से जल्दी सख्त सजा दी जावे। पर हाथ जब रक्खा जाता है तो किसी की सिफारिश आ जाती है, किसी का दबाव आजाता है और मामला दबा दिया जाता है। यहां बिजली घर में बड़ा भारी धोखा हुआ परन्तु अभी तक इसका पता नहीं लगा। प्लान्ट प्रोटेक्शन के महकमें में लाखों रुपये चम्पत कर दिये गये। उस अफसर को सस्पेन्ड किया गया, जांच जो चल रही है वह पूरी भी नहीं हुई कि पंजाब सरकार ने उनको अपनी सर्विस में वापिस बुला लिया जहां से वे पहले यहां आये थे। वे वापिस चले गये हैं और मौज से वहां अफसरी कर रहे हैं। पर राजस्थान की हमारी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया।

मैं एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकता हूं कि जिसमें कहीं भी कोई सख्त कदम ऐसे कामों में नहीं उठाया गया। ऐसी स्थिति में जिस भ्रष्टाचार विरोधी मण्डल की स्थापना करके आप धन्यवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर आप भ्रष्टाचार के बहुमण्डल बनायेंगे और यह स्थिति पैदा होगी, अगर आपने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती से लोगों को सज़ा नहीं दी तो।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस भाषण में कहा गया है कि हमने शिक्षा की उन्नति के लिए, टैकनिकल शिक्षा की उन्नति के लिए, कई-कई योजनाएं बनाई हैं, और एक कृषि कालेज खोलने का भी जिक्र है। मेरे माननीय मित्रों ने उसको बड़े सब्र के साथ सुन लिया, पर उनका ध्यान उसकी गहराई में नहीं गया। मेरा कर्तव्य है कि मैं पूरी बात सदन के सामने प्रस्तुत करूं। यह बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार ने एक नया कृषि कॉलेज खोलने का निर्णय किया पर ऐसा अन्देशा प्रतीत होता है कि जिस समय एक नया कॉलेज खोलने का निश्चय किया गया है उसी समय एक दूसरे चलते हुए कृषि कॉलेज को पोटाशियम साइनाइट देने का भी निश्चय कर लिया गया है। यह जोबनेर में है जहां ऑलरेडी एक कृषि कॉलेज चल रहा है और उसका हाल यह है कि सरकार उसको ८० प्रतिशत एड देती है, पर वहां इस तरह का आला दर्जे का इन्तजाम है कि रिपेयर के नाम से काफी रकम बंधी हुई है और खर्च भी कर दी जाती है, पर जिसकी मरम्मत की जाने को है उस ट्रेक्टर का पता नहीं। तो भी वहां के विद्यार्थी किसी तरह से महनत करके पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह कि किसी तरह से वह कृषि-कॉलेज चल रहा है, उसकी अपनी बिल्डिंग भी है, उसका छोटा-मोटा ट्रस्ट भी है; जिसकी आमदनी का क्या होती है यह पता नहीं।

सरकार अगर उसकी थोड़ी बहुत भी देखभाल कर ले तो आमदनी आ सकती है। इसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेन्सेज (non-recurring expenses) को आप छोड़ दीजिये पर रेकरिंग ८ हजार, दस हजार रुपया सरकार को और खर्चा करना पड़ेगा। यह खर्चा अगर सरकार करती रहे तो वह कॉलेज चलता रहेगा। पर इसके बारे में यह बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा है कि सरकार कहती है कि हमें इसके बारे में फिक्र नहीं, हम दूसरा कॉलेज खोल रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि एक जो चल रहा है इसको क्यों बन्द होने दिया जावे। दूसरा ही क्यों फिर तीसरा खोला जावे, चौथा खोला जावे, पर आठ हजार, दस हजार, के नॉन-रेकरिंग एक्सपेन्सेज के लिये एक चालू कॉलेज को बन्द कर दिया जावे यह कौन सी बुद्धिमता सरकार की है, यह कौनसा राहत है? हां, अगर आप यह जानते हैं कि इसका इन्तजाम ठीक नहीं है तो क्यों नहीं सरकार खुद इसका इन्तजाम अपने हाथ में ले लेती है और चलाती है? इसको भी चलाते रहें और एक और खोल दें तब तो हम समझते हैं कि हां, सरकार ने उन्नति की है, प्रगति की है, वर्ना एक को बन्द करके दूसरा चला दिया तो यह तो उन्नति नहीं मानी जावेगी। यह तो ऐसी ही हालत हुई कि एक तराजू के तोल इधर से उधर दूसरे तराजू में रख दिये।

अब मैं एक ऐसे विषय की ओर इशारा करना चाहूँगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना ही नहीं लेकिन राजस्थान सरकार की नीति से भी इसका बहुत सम्बन्ध है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, चाहूँगा कि माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय बहुत बाकायदा नोट लेकर, अगर उनके लिए मुमकिन हो तो, ठोस रूप से उसका उत्तर कल दे देंगे; यह वे प्रयत्न करें। इस भाषण में राजप्रमुख महोदय एक दो जगह फरमाते हैं—पैरा ८ में—कि भूमि देने के लिए नये नियम लागू करके तथा खेती की भूमि की सीमा निर्धारित करके सरकार भूमि-हीन किसानों के सवाल को हल करना चाहती है। भूमिहीन किसानों का उल्लेख इस सरकार द्वारा किया जाता देखकर मुझे थोड़ा जोश आया। मैंने सोचा कि भूमिहीन किसानों की समस्या का भी सरकार के दिमाग में असर पड़ तो गया है। लेकिन फिर जब पढ़ा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गया तो यह मालूम हुआ कि यह उल्लेख तो कुछ दूसरा ही उल्लेख है, क्योंकि अभी जमीन देने के सम्बन्ध में नियम जो हैं, फिर ये दूसरे नियम कौन से होंगे, मालूम नहीं; पर जो कुछ भी नियम हों उसके मातहत कार्यवाही बराबर चल रही है सरकार की। पर यह जो कार्यवाही चल रही है इसमें भूमिहीन किसानों का कहीं पता नहीं।

अलवर का मैं आपको दृष्टान्त दूँ। अलवर में वाटर वर्क्स चलाने के लिए, शहर के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने जमीन एक्वायर की। जरा ग़ौर से सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीन एक्वायर की गई। वहां जो बेचारे किसान खेती कर रहे थे उनकी वह जमीन उनसे ले ली जाने की वजह से वे भूमिहीन हो गये। दूसरी ओर सरकार के एग्रीकल्चर विभाग के पास पोलो ग्राउन्ड की एक जमीन थी। अचानक एग्रीकल्चर विभाग को यह महसूस हुआ कि यह जमीन अपने लिए आवश्यक नहीं है। आचानक ही एग्रीकल्चर विभाग ने वह जमीन रेवेन्यु विभाग को दे दी और रेवेन्यु विभाग ने, जब कि मन्त्री महोदय दोनों विभागों के एक ही सज्जन थे, नये मन्त्री महोदय नोट कर रहे हैं मैं तारीख भी बता रहा हूँ उस विभाग की, तो एग्रीकल्चर विभाग ने वह जमीन रेवेन्यु विभाग को दे दी और रेवेन्यू ने उन भूमिहीन बेचारे किसानों को, जिनकी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली और जिस सरकार की वजह से वे भूमिहीन बने उस सरकार ने उन बिचारे भूमिहीन किसानों पर इतनी दया दिखाई कि वे तो टापते ही रह गये, उस पोलो ग्राउन्ड की जमीन को पाने को और वह जमीन श्री शोभारामजी एम. पी. को अलॉट कर दी गई। एक ओर सरकार के द्वारा गरीब किसानों की जमीन छीनी जाती है और वह एक-एक से चार-चार पांच-पांच बीघा छीनी जाती है सार्वजनिक काम का नाम लेकर, उसकी आड़ में यह छीना-झपटी की जाती है। पर दूसरी तरफ रेवेन्यु विभाग के पास जो जमीन आती है उसके बंटवारे के वक्त वे भूमिहीन किसान, जो सरकार के द्वारा भूमिहीन बनाये गये, जमीन के लिए टापते रह जाते हैं और श्रीमान् एम. पी. महोदय शोभारामजी को, जिनका नाम भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड में भी दर्ज किया गया है, चुपके-चुपके बगैर किसी सूचना के वह जमीन अलॉट कर दी जाती है।

एक ही ऐसी बात हुई हो ऐसा नहीं। माननीय उपाध्यक्ष मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यहां जयपुर के पास सांगानेर और दुर्गापुरा के अन्दर, इधर झोटवाड़े से थोड़ी दूर जयपुर से कुछ मील की दूरी पर, काफी जमीन सरकार ने अलॉट की है। कहीं बीड़ थे तो उनको तोड़ा गया और २००, २५० बीघा कुछ लोगों को दिया है और वह ऐसे ऐसे भूमिहीन किसानों को मिली है जिनमें श्री नरोत्तमलाल जी जोशी, श्रीमान् कुम्भाराम जी आर्य, श्रीमान् हरलालसिंह जी हैं, जिनके नाम हैं (हंसी) पालीवालजी का नाम तो शायद नहीं है लेकिन हरदेव जी का नाम अलबत्ता हो सकता है, और भूमिहीन किसानों को जमीन देनेवाली सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी के खास रिश्तेदारों के नाम भी हजारों बीघा जमीन बूंदी जिले के अन्दर अलॉट की है पिछले डेढ़-दो बरस के अन्दर। यह भूमिहीन किसानों के साथ बहुत ही रियायत का रुख सरकार ने रखा है।

सीलिंग मुकर्रर करने वाली सरकार ने कोटा जिले में फॉरेस्ट विभाग की एक जमीन थी हजारों बीघा, वह एक सज्जन को दी हैं, कुछ ले-दे का सौदा करने के बाद, जिसके बारे में फॉरेस्ट विभाग

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अलग चिल्ला रहा है, जिसके बारे में दूसरे लोग शिकायतें कर रहे हैं। वह हजारों बीघा जमीन, शायद १२००० बीघा जमीन एक व्यक्ति को मिली है। जो सीलिंग मुकर्रर करने जा रही है, जिसके दिल और आंखों में भूमिहीन किसानों के लिये प्रेम उभर आया है, वह सरकार जवाब दे इस बात का कि यह जमीन एक-दो साल के अन्दर अलॉट हुई है, यह जमीन जो सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेवेन्यु डिपार्टमेंट में ले ली है और इधर-उधर बेच दी है और अब वह कह रही है कि नये नियम बनाये जायेंगे, खेती के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं, 'सी' स्कीम के लिये नये नियम जयपुर के अन्दर बनाये गये हैं और वह भी अच्छी-अच्छी जमीन के खत्म होने के बाद में यह जमीन के नियम बनाये गये हैं, क्या उसी तरह यह नियम बनाये जायेंगे, माननीय उपाध्यक्ष ? यह क्या किया ? लेकिन अब उसके ऊपर यह जले पर नमक और छिड़कना है, ऐसी अन्धेरगर्दी का काम किया। लेकिन आप उल्टा कहना चाहते हैं कि भूमिहीन किसानों को बसाने का प्रयत्न किया, उसके लिये धन्यवाद दो। इन भूमिहीन किसानों के लिये। इसके अलावा आगे चलते हैं तो उस इलाके में क्या हुआ ? वह आम लोगों की जानकारी में है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिन लोगों को जमीनें एलॉट कर दी गई उन्होंने वहां जाकर बेदखल किया, मारपीट की, किसी पर मुकद्दमे चलाये। यह हालत उन भूमिहीन लोगों की है और ऐसी स्थिति आगे करके इस प्रकार की चीजों के लिये धन्यवाद लेना चाहते हैं।

मैं यह सुन कर बड़ा खुश हुआ कि राजस्थान के राजप्रमुख को राजस्थान की औद्योगिक उन्नति का ख्याल हो गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने उन्नति को ला देने का एक तरीका निकाल रखा है जिसका कि नाम बोर्ड है। यही उन्नति करना है। जल की योजना बनाई है तो जलबोर्ड बनाया, उद्योगों की उन्नति करनी है तो इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन बन गया, राजस्थान भर की उन्नति करनी है तो विकास बोर्ड और बना है, जिसके कई सदस्यों के नाम अखबार में आये हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन सदस्य महोदय ने कहा कि मेरे पास तो सूचना नहीं है। कलकत्ता के कोई भागीरथ जी कानोड़िया हैं जो बिड़ला जी के खास नजदीकी आदमी हैं। दूसरे टांटियाजी हैं, जो मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी में रह चुके हैं, जहां कि कुछ गबन के मामलों की शिकायतें उनके ऊपर हैं और कई सज्जन जो पानी के बोर्ड में लिये गये हैं वे सब सज्जन, ऐसा मालूम हुआ है कि उनमें ज्यादातर कलकत्ता में बैठे-बैठे दफ्तर करते हैं, पानी की सुविधा करेंगे नवलगढ़ के इलाके में अलबत्ता चुनाव के दिनों में थोड़ी बहुत सुविधा जरूर पैदा करेंगे, लेकिन पानी के सिलसिले में कलकत्ता में बैठेर क्या करेंगे ? इसके बाद में विकास का बोर्ड, खादी का बोर्ड बना जिसमें हुन्डियों के बिकने के मामले में बाद में स्थिति गड़बड़ हो गई। उसका एक आर्डीनेन्स विधान सभा के शुरू होने से पहले शाया कर दिया गया इस लिये कि मेम्बर्स की नियुक्ति करने में देरी न हो जायें।

लेकिन यह बोर्ड जो बनाये गये हैं, माननीय उपाध्यक्ष, उनमें से सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के नाम का बोर्ड जो बना है उसकी ओर। उसके बारे में एक एक्ट है, एक कायदा है, भारत सरकार द्वारा पास किया हुआ है, संसद द्वारा पास किया हुआ है, उस कायदे के मातहत राजस्थान सरकार ने न सिर्फ इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की नियुक्ति की है या लागू किया है राजस्थान में, बल्कि उसमें, उस कायदे में, जो शक्ति

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

राजस्थान सरकार को दी गई है, उस शक्ति का प्रयोग करके कुछ लोगों को बोर्ड के डाईरेक्टर्स और मेनेजिंग डाइरेक्टर्स के रूप में नामजद किया है, और बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही उदार तरीके से चीजों का विचार करके राजस्थान सरकार ने, मेरे माननीय मित्र त्यागीजी तो बोलते बोलते हिचकिचा गये, लेकिन मैं अर्ज करदूं, श्री रामनाथ जी पोद्दार को इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का चेयरमेन नियुक्त किया है, और इस चेयरमेन की कितनी ताकत होती है इसका अन्दाज तो आप इस बात से लगा लें कि केन्द्रीय इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के चेयरमेन, सर श्री राम थे, जिनके लिये भारत सरकार ने एक जांच कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और नतीजा उसका यह हुआ कि घोटालेबाजी के कारण सर श्री राम को इस्तिफा देने की नौबत आई। तो ऐसी उस कॉर्पोरेशन की विशेष जगह पर किनको नियुक्त किया है, श्रीमान् रामनाथजी पोद्दार को कैसे आदमी हैं? क्या व्यूज हैं? यह तो सरकार जाने, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन में राजस्थान सरकार ३६ लाख रुपये लगाने वाली है, और केन्द्रीय सरकार भी लगाने वाली है रुपया, और दूसरे लोग भी लगाने वाले हैं; लेकिन न मालूम क्यों यह आंकड़ा ऐसा फिट बैठा है कि जो पैसा कई सालों पहले इन अकेले श्रीमान् रामनाथजी पोद्दार को, ३६ लाख रुपया जयपुर और बीकानेर सरकारों ने मिलकर दे दिया और अब वह राजस्थान सरकार का है—१६ लाख रुपया बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को और १७ लाख रुपया जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के नाम की कम्पनियों के अन्दर है—और इन दोनों मेनेजिंग डाइरेक्टर श्रीमान् रामनाथजी पोद्दार हैं। इस प्रकार ३६ लाख रुपया इनके हाथ में सरकार ने सौंपा, यों समझ लीजिये। लेकिन उस तारीख से, १७ लाख तो यह और १६ लाख वह, पिछले साल तक एक टका भी कमाकर सरकार को उन्होंने नहीं दिया। ३६ लाख रुपये पर सरकार को एक टका भी नहीं मिला। बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को १५ लाख रुपये कर्ज के रूप में, डिबेन्चर के रूप में व्याज के ऊपर दिये थे, उसके अन्दर एक पैसा भी नहीं मिला और अब चिट्ठी में लिखा है कि कस्टम का बाकी है वह एडजस्ट कर लिया जाय, अब इसका फलांणे का बाकी है वह एडजेस्ट कर लें; लेकिन एक टका आज तक नहीं दिया। यह तो उनके डीलिंग्ज़ (dealings) इतना ही नहीं, लेकिन में आप से अर्ज करूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि तरह-तरह की सहूलियतें इस बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को सरकार ने दी है। सारी दुनियां से ३ आने की रेट से बिजली चार्ज करती है राजस्थान सरकार, लेकिन बगैर एग्रीमेंट के, नोट कर लें माननीय उद्योग मंत्रीजी, एग्रीमेंट में कहीं दर्ज नहीं है। बगैर एग्रीमेंट के स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को ६ पैसा यूनिट के हिसाब से बिजली दी गई है। क्यों दी गई? कैसे दी गई है? इसका सारा इतिहास तो श्रीमान् रामनाथजी पोद्दार और उनके लिये दौड़ धूप करने वाले श्रीमान् रामजी कोंक या राजस्थान सरकार के उस समय के मंत्री बता सकते हैं; लेकिन उनको रियायत पर रियायत दी गई है और उस पर भी एक टका नहीं आया है। ३६ लाख रुपये में इतने बड़े उद्योग पनपे, लेकिन स्पिनिंग एक वीविंग मिल्स में केवल स्पिनिंग ही रह गया और वीविंग चालू नहीं हुआ है। गंगानगर की शुगर मिल को आपकी सरकार ने पिछले साल अपने हाथ में ले लिया। उसका घाटा अपने सिर पर ओढ़ लिया। उसका विस्तृत जिक्र बजट के समय और होगा। वे उद्योग पनपने की स्थिति में नहीं हैं। जब इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन में करोड़ों रुपया उनके हाथ में रखा जायगा। सेक्रेटरी श्रीमान् भार्गव को रखा जयपुर बैंक के मेनेजर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थे और पोद्दारजी उसके चेअरमेन थे। यहां भी चेयरमेन श्रीमान् रामनाथजी पोद्दार और सेक्रेटरी श्री भार्गव साहब हैं। दो चार सज्जन हैं, जैसे श्रीमान् सोमानीजी, बिरलाजी; जो राजस्थान सरकार को ऐसे मिल गये और उनको नामज़द कर दिया। अब करोड़ों रुपया इनको जो दिया जायगा उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि जो इस ऑडिट रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट को दिखाते हुए) में दर्ज किया हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, एक बार फिर मैं इस ऑडिट रिपोर्ट के पेज २७ के पैराग्राफ २६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने भोपाल कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की एक संस्था को करीब ३५ लाख रुपया दिया और वह रुपया पूरा का पूरा साफ होगया, एक टका भी वसूल होने का नहीं; ऐसा आडिट रिपोर्ट में दर्ज है। प्रतापनगर कोलोनी नाम की कोलोनी बसाने के लिए जैसे ३५ लाख रुपये भोपाल कोआपरेटिव सोसाइटी को दिये गये, और जैसे ३६ लाख रुपये बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में लटके हुए हैं वैसे ही यह करोड़ों रुपये राजस्थान सरकार के इन्डस्ट्रियल फाईनेंश कॉर्पोरेशन में जाने वाले हैं। और फिर भी सरकार कहती है कि इसके लिए हमको बधाई दो। जिसने आज तक ५ साल तक सरकार का पैसा दबा रखा और एक टका भी सरकार को नहीं दिया वे यदि दावा करते हैं कि वे व्यक्ति सरकार के करोड़ों रुपयों का सही इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि यह जितनी चीज़ें दावे की इस भाषण में की गई हैं उनकी तो विचित्रता की कोई सीमा ही नहीं है।

यहां तक कि बिजली के लिए, बिजली घरों को रिनुएट करने के लिए २५७ लाख रुपये हमको भारत सरकार ने दे दिए, ऐसा मालूम हुआ है, यह युधिष्ठिर की तरह उधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्र उसी तरीके से कहेंगे कि "अश्वत्थामा हतो" और फिर चुपके से कह देंगे "नरो वा कुंजरो"। भारत सरकार ने २५७ लाख रुपया दिया है। इसको लिखा है; लेकिन यह नहीं बताया कि अभी वह स्कीम अधूरी है, उसका टेक्नीकल एग्जामिनेशन हो रहा है और फिर अमेरिका के पोइन्ट फोर (Point four) के मातहत जो ऑफिसर न्यू दिल्ली में बैठा है वह देखभाल करेगा, फिर अमेरिका में ऑर्डर प्लेस होगा और फिर डेढ़–दो साल में मशीनरी तैयार होगी, उस २५७ लाख को अब ले लिया है; लेकिन मशीनरी २ साल बाद आयेगी।

और मेरे कुछ माननीयमित्र, जो कि राजस्थान में ४-५ साल के बाद में केनाल आने वाली है, उसके पानी की कल्पना में अभी से उसमें डूब रहे हैं। मेरे एक माननय मित्र ने कहा कि भाखरा में जब पानी आयेगा तोकिस का दिल बाग़-बाग़ न होगा! जरूर होगा। अगर कोई यह देखे कि भाखरा का पानी आया, लेकिन नतीजा उसका क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि माइनर्स तैयार नहीं थे, और पीलीबंगा के माइनर्स तैयार नहीं होने की वजह से नहर बीच के अन्दर से फूट गई है और पानी बरबाद होता है। बीकानेर केनाल में जितना पानी आना था उतना पानी नहीं आया, लाखों का खर्चा होने के बाद में पानी नहीं आया। प्रश्न यह नहीं है कि पानी देखकर कोई खुश नहीं होगा। प्रश्न यह है कि भाखरा चालू हो गया लेकिन राजस्थान सरकार की क्या यह कामयाबियत है कि वह अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा पानी पहुँचा नहीं सकी, इसलिए कि माइनर्स नहीं बने। इसी तरह की बिजली की योजना अभी मन्जूर हुई है। गंगवाल के पॉवर स्टेशन का उद्घाटन हो गया है, लेकिन राजस्थान में तार लगेंगे तब जाकर राजस्थान सरकार को बिजली मिलेगी, और वह राजस्थान सरकार आज धन्यवाद का पात्र अपने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आपको मानती है । वह धन्यवाद का पात्र नहीं है; बल्कि राजस्थान सरकार को सफाई देनी चाहिये और इसलिए.........(समय सूचक घंटी) मैं सिर्फ ५ मिनट और लूंगा ।

(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि यह सब जो आज इस भाषण में लिखा है, उसमें इस बात की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रखी गई है कि यह एक साल में हुआ या २ साल में हुआ या ३ साल में हुआ ।

हमने डिस्प्लेस्ड परसन्स के लिए इतने मकान बना दिये । मैं आपके सामने इसके लिए बतलाना चाहूंगा, जिसके लिए मैं फिर ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ दूँ जिसमें लिखा है कि मकान तो बनाये गये, लेकिन खिड़कियें और दरवाज़े नहीं हैं, शटर्स नहीं हैं । मकान हैं लेकिन बाथ रूम और लेट्रिन्स की व्यवस्था नहीं है । मकान पूरे हो गये हैं, लेकिन उस इलाके के अन्दर पानी के नल नहीं लगाये हैं । दूकाने बनी हैं लेकिन रोशनी कहीं से नहीं आई है । तीन चौथाई खाली पड़ी हैं, किराया वसूल नहीं हो रहा है । किरायानामा सरकार ने लिखाया है लेकिन किरायेनामे के अन्दर किराया कितना है दर्ज नहीं होता है । ऐसे भी किराये नामे हैं जिस पर कि सरकारी अफसर के दस्तखत तक नहीं हैं । मकान जो बने उनका खर्चा पड़ा किन्तु किवाड़ और दरवाजे नहीं बनें, इसलिए किराये की वसूली नहीं होती है । अगर किरायानामा लिखा है तो किराया दर्ज नहीं है, लिखा पढ़ी पूरी करली तो अफसरों के दस्तखत मौजूद नहीं हैं । राजस्थान सरकार ने यह धन्यवाद का खूब काम किया है । पूरे ३ साल में जाकर कहीं यह कहना भूल गए । यह गौरव के कार्य हैं हमारे राज्य के ! ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे के पूरे भाषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि छोटी-मोटी इधर-उधर की बातों को जोड़–तोड़ कर असली योजनाओं के सबसे बड़े भाग को ढक कर राजस्थान सरकार ने दुनियां को भुलावे में डालने की कोशिश की कि देखो हमारी रफ्तार कितनी तेज़ है, लेकिन हक़ीक़त में राजस्थान की अर्थनीति की गहराई में कोई जाये तो मैं आपसे चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का आर्थिक ढांचा डोलायमान स्थिति में है ।

आज अनाज, गल्ले तथा किसानों के पैदावार की चीजों के भावों में जो कमी आई है, जो गिरावट आई है, उस गिरावट ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि राजस्थान सरकार का सारा आर्थिक ढांचा गिरने लगा है और राजस्थान सरकार को उसका कोई खयाल नहीं है । ।

बेकारी की समस्या हमारे सामने जो है उसका उल्लेख तक इसमें नहीं है ।

भूमिहीन किसान और बेरोज़गार लोग लाखों की तादाद के अन्दर घूम रहे हैं । हाथ–करघे के रूप में इतनी सहायता दी जाय, उसका इसमें उल्लेख नहीं है ।

शहरों के अन्दर छँटनी की जा रही है । सरकारी विभागों में छंटनी की जा रही है, उसके नियम बने हैं । कस्टम में छंटनी की जा रही है, सिविल सप्लाईज में छंटनी की जा रही है; उसका इसमें उल्लेख नहीं है ।

[श्रीं हरिकृष्ण व्यास]

फिर लगान के बढ़ने का बोझ किसान पर बहुत ज़्यादा है । उसको राहत देने का भी इसमें ज़िक्र नहीं है ।

मध्यभारत जैसी सरकार ने शिक्षक और चपरासियों की तनख्वाहों के नये ग्रेड मुकर्रर करने के लिए कमेटी बिठाई है, लेकिन राजस्थान सरकार जो कि शिक्षा की प्रगति पर इतना ज़ोर देती है तो हमारे माननीय मंत्रीजी द्वारा ३०), ४०) रु० के अन्दर बच्चों को उम्र भर शिक्षा देने वाले शिक्षकों की तनख्वाहों के ग्रेड के बारे में, कमेटी मुकर्रर करने का जिक्र नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में क्या होगा यह तो १० दिन बाद माननीय मन्त्री बजट पेश करेंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है । भविष्य का एक उज्ज्वल चित्र बनाना कि हम तो समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह रोम जल रहा था और नीरो सारंगी के तार पर गुनगुना रहा था, ठीक उसी तरह राजस्थान की सरकार भी अपने छोटे से बर्तन में तेल डाले हुए चली जा रही है और शेखचिल्ली की तरह सपने देखे चली जा रही है कि यह करेंगे, वह करेंगे और हमारी आमदनी बढ़ जायगी । भविष्य में इतनी चीज़ें होजाने वाली हैं, इसी बिना पर धन्यवाद देना कहां तक उचित है, और उस हालत में जब कि श्रीमन् राजप्रमुख खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वे लाखों रुपयों का खर्चा राजस्थान पर डाले हुए हैं । मैं अपनी खुद की राय देता तो माननीय मित्र एतराज करते, पर मैं अपनी नहीं राजस्थान विधान सभा की प्राक्कलन समिति की राय पेश कर रहा हूं । इस कमेटी ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया है कि ज़्यादा खर्चा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का राजप्रमुख, महाराज प्रमुख और उप-राजप्रमुख पर होता है । उन्हें मुफ्त की बिजली, हवाई जहाज के मुफ्त के ८० हजार रुपये, मकान के ८० हजार रुपये और २ कितने ही कुल मिलाकर ७३ लाख रुपये का हेवी बरडन (heavy burden) स्टेट पर है । इस पर राजप्रमुख के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव लाना, यह कैसी बात है ? यहां तो यह प्रस्ताव लाना चाहिये कि हमारे राजस्थान की हालत गई गुज़री हो रही है, घाटे का बजट पेश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा के गवर्नर को जिस तरह ढ़ाई लाख रुपये देते हैं । उसी तरह हमारे यहां पर भी ढ़ाई लाख में किसी को रख लेना चाहिये, ये ७३ लाख के सफेद हाथी क्यों पाले हुए हैं ? पर यह कहने के लिए सरकार की हिम्मत नहीं होती ।

तो इस माने में किसी तरह उनको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता । धन्यवाद न दिया जा कर सेंसर किया जाय और सरकार से जवाब पूछा जाय कि आपने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने के बजाय यह खर्चा कम करने का प्रस्ताव क्यों नहीं पेश किया ?

इन्हीं शब्दों के साथ में श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद देने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे आपके सामने यह कहने की ज़रूरत नहीं कि जो मैं खड़ा हुआ हूं, वह जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने श्रीमन् राजप्रमुख को उनके

[श्री मथुरादास माथुर]

अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव रक्खा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह ठीक है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो यहां पर मेरे बोलने के पहले दो-तीन उधर बैठने वाले साथियों के भाषण हुए उनको भी सदन ने गौर से सुना है। पहले श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में जो जो बातें कहीं वे कल आपके सामने उन्होंने अपने श्रीमुख से पढ़कर सुनाई और सदन के सभी साथियों ने उस भाषण को गौर से पढ़ा भी है। मैं ज़्यादा समय आपका उस ओर नहीं लेना चाहता कि जो बातें इसमें लिखी हैं उन्हें दोहराऊं। लेकिन मैं अन्त में जो कुछ कहा गया है उसका स्पष्टीकरण जरूर करूंगा। पर वह कहने के पहले मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता की ओर से जो भाषण आज हुआ है। उसकी ओर सदन का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा, और इसके बाद मैं हमारे विरोधी दल में बैठने वाले त्यागीजी ने और साथी हरिकिशन (हरिकृष्ण) व्यास ने जो कहा है, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

यह मैं जानता हूं कि जो भी भाषण अभी हुए हैं बड़ी निपुणता और जोश के साथ रक्खे हैं, चाहे वे राजप्रमुख को धन्यवाद देना नहीं चाहें, पर मैं इन साथियों को इस निपुणता के साथ भाषण देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य-शासन भावुकता से नहीं चलता और रिपोर्ट का एक आंकड़ा इधर से और एक आंकड़ा उधर से पढ़ कर सुना देने से काम नहीं चलता है। जो बातें उन्होंने कही है, जहां तथ्य नजर आया हो उसे स्वीकार करने में मैं नहीं हिचकता। विरोधी दल के आज खास नेता नहीं हैं। उपनेता ने जो भाषण दिया है, उसको जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होरहा था कि कल श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण दिया, उसे उन्होंने पूरा सुना नहीं और बाद में उसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वह लॉ एण्ड ऑर्डर की सिच्युएशन पर प्रकाश डालने की बात थी। श्री त्यागीजी ने भी इस बात की चर्चा की और जोधपुर से आने वाले साथी ने भी इस बात की चर्चा की है। जब तीन व्यक्ति चर्चा करते हैं तो काफी जोश के साथ बोलते हैं, सदन के उस ओर और इस ओर बैठे हुए सदस्य चर्चा करते हैं।

जब असेम्बली के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण हुआ था तो उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जो हालत उस वक्त थी उससे आज की हालत का मुकाबला किया जाय, श्रीमन् राजप्रमुख ने यह नहीं कहा कि हालत बिल्कुल ठीक हो गई है हालत एक दम फॉल्टलेस (faultless) है। श्रीमन् राजप्रमुख का भाषण हर साल जब होता है उस वक्त वे बताते हैं कि सालभर में जो स्थिति बनी उस पर कितनी तरक्की कर सके या कितने गिरे। आज जो एक साल पहले दो साल पहले भाषण हुए उन पर रोशनी डालिये। एक तरफ तो उस ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों की यह आवाज थी कि राजस्थान में रहना मुश्किल है और अगर यही हालत रही तो राजस्थान के लोग राजस्थान छोड़कर चले जायेंगे। हर सप्ताह डाके पड़ते थे जिससे कि लोगों का इधर-उधर आना-जाना, घूमना मुश्किल था। कुछ राजनैतिक पहलू भी थे जिनको इधर और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया था।

[श्री मथुरादास माथुर]

सदन के हम आभारी हैं कि राजस्थान सरकार को लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक करने के लिए काफी रुपया दिया और इससे काफी व्यवस्था ठीक हुई। आज ३ वर्ष बाद जो हालत हम देखते हैं उससे कह सकते हैं कि हालत ठीक है। हिन्दुस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं, हिन्दुस्तान ही क्या दुनियां में कोई स्टेट यह दावा नहीं कर सकती कि उनके इलाके में सालभर में डकैती या रोबेरी नहीं होती हो। बम्बई में दिन दहाड़े बैंक लूट लिये जाते हैं। बम्बई की पुलिस कितनी ही अच्छी हो, फिर भी दिन दहाड़े बैंक लूट लिए जाते हैं यह कोई गौरव की बात नहीं है।

जहां समाज के बहुत बड़े आदमी रहते हैं, हो सकता है कि वहां बुरे आदमी भी हों, जहां कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसके साथ-साथ हमको राजस्थान की हालत और पड़ोसियों की हालत को देखना पड़ेगा। यहां पर हम भाषण, किसी कॉम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्लेटफार्म भाषण देने के लिये नहीं देते, न लोगों से ताली पिटवाने के लिये भाषण देते हैं। यहां पर आपको यह देखना होगा कि राजस्थान का ७०० मील का बोर्डर है जहां पर न तो कोई दीवार है और न कोई दूसरी चीज है; अन्डिफाइन्ड बोर्डर है, जो पाकिस्तान से मिला हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान से कभी अच्छे ताल्लुकात और कभी बुरे ताल्लुकात हो जाते हैं उस ओर से डाकुओं को छोड़ दिया जाता है। हमारी पुलिस वहां (बोर्डर पर) पहुंच सकती है। मगर वहां पहुंचने में कितनी कठिनाई होती है इसको भी हमारे साथी श्री एच. के. व्यास जानते हैं। इसको उन्हें नहीं भूलना चाहिये। इसके अलावा उनको यह नहीं भूलना चाहिये कि यू. पी., मध्य भारत और उत्तर प्रदेश आदि की पुलिस एक डाकू मानसिंह को पकड़ने के लिये लगी हुई है। जब तीन बड़ी-बड़ी सरकारें, जिनके पास लाखों रुपया है, जिनका बजट राजस्थान की तरह डेफिसिट नहीं है, एक डाकू मानसिंह को पकड़ने में लगी हुई है, उन्होंने अपने यहां से भी अफसर मांगे और राजस्थान सरकार ने अफसर भेज दिये, इसके अलावा वहां पर एच. के. (श्री हरिकृष्ण व्यास) जैसे हज़ार कॉम्युनिस्ट भी डोलते हैं जो आज से नहीं, बहुत पुराने कॉम्युनिस्ट हैं, लेकिन वे सब मिल कर एक डाकू मानसिंह को नहीं पकड़ पाते हैं। ऐसे मानसिंह के लिये रास्ते है, वेसे हमारे यहां ७०० मील का लम्बा बोर्डर है, जहां से कोई भी किधर निकल जावे, पता नहीं चलता है। हमारी पुलिस काम करती है और दिन ब दिन डाकू पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, सरेन्डर होते हैं। ऐसो हालत में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद के छोटे से प्रस्ताव को ठुकरा दिया जावे, तो इसके लिये बड़ा दुःख है। इसलिये में यह अर्ज़ करूंगा कि हमारे राजप्रमुख के भाषण के इस अंग के लिये तो यह मानना ही पड़ेगा कि किसी तरह से डाकुओं में कमी हुई है। कभी कोई गैंग आगरा या यू. पी. से चला आता है और कोई डाका करके चला जाता है या चोरी करके चला जाता है तो ऐसा तो सभी जगह होता है। दुनिया में कोई ऐसी स्टेट नहीं जहां ऐसा नहीं होता हो। अगर ऐसा नहीं हो तो पुलिस की फिर कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह तभी हो सकता है जब समाज का मोरल ऊंचा हो जावे। इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे इस बात का गर्व है कि श्रीमन् राजप्रमुख के इस भाषण के इस अंग पर जिसमें यह कहा गया है कि लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है और डकैतियें, चोरियें और लूट कम हुई है और लोग आसानी से घूम फिर रहे हैं और डाकू सरेन्डर कर रहे हैं। जैसलमेर या अरावली के निवासियों की स्थिति में जो इम्प्रूवमेन्ट हुआ है उस पर उनको धन्यवाद दे तो कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिये।

[श्री मथुरादास माथुर]

मैं तो यह कहूंगा और खास तौर से जोधपुर से आने वाले सदस्य के लिये, जिनको कि तीन साल से बराबर देख रहा हूं, यहां पर यदि समाजवादी शासन-प्रणाली भी कायम कर दी जावेगी तो भी उनको संतोष नहीं होगा। फिर भी वे ऐसी चीज़ निकालेंगे जिससे कुछ न कुछ नुक्स निकलते रहें। विरोधी दल के नेता से तो मैं ऐसी आशा नहीं रखता था। इधर और उधर बैठने वाले कुछ कहें, उसका तो मुझे रंज नहीं। मगर में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह यह बतलाने की कोशिश की कि लॉ एन्ड ऑर्जर बिगड़ रहा है। लॉ एन्ड ऑर्डर १९५१, ५२ व ५३ में जो था और आज है उसकी हालत को यदि बार-बार देखते जावें और उसमें अगर गिरावट है तो वे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने में फेल हुई। इसलिये श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं दे सकते।

श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण के कई अंग हैं और यह तो विशेष अंग है इसलिये मैंने आप लोगों के सामने इसे रखा है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुछ पर्सेन्टेज बताया जावे कि किस पर्सेन्टेज से चोरी के रुपयों में, डकैती के माल में कमी हुई या किसमें कमी हुई। मगर यह साफ लिखा है कि पहले साल से क्रमशः कमी हुई है।

विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि लोग शिकायत नहीं करते किन्तु डकैती जो होती है उसकी इत्तिला सब जगह फैल जाती है। छोटे-मोटे शहरों में, चोरियें जो हो जावें उसकी इत्तिला सम्भवत पुलिस को नहीं करें, और शिकायत नहीं करें लेकिन डकैती कि इत्तिला तो हो जाती है। अगर आप पुलिस रिपोर्ट साल भर की पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि कितने आदमी मारे गये। माननीय उपाध्यक्ष, हज़ारों पुलिस के आदमी डाकुओं का मुकाबला करते हुए मारे गये। उनमें पुलिस इन्सपेक्टर, पुलिस सब इन्सपेक्टर जो मर गये उसके भी आंकड़े आपको उस रिपोर्ट में मिलेंगे। इसके अलावा वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट और अखबारों में भी ये आंकड़े निकालते हैं। जो आदमी मारे जाते हैं उसके लिये हम झूटा प्रचार नहीं कर सकते। आप उनके आंकड़े देखिये। हमें पुलिस का उत्साह बढ़ाना चाहिये जिससे कि वे अपनी जान को जोखम में डाल कर लॉ एन्ड ऑर्डर की व्यवस्था को टीक कर सकें। मुझे विरोधी दल के नेता से जरूर ऐसी आशा थी, क्योंकि वे बार-बार यह कहा करते थे कि हम सहयोग देना चाहते हैं और देते रहें। उनके लिये यह कहना शोभा नहीं देता। उधर बैठने वाले साथी जानते हैं कि उनको क्या कहना चाहिये और उन्होंने क्या कहा है।

मैं दूसरी बात जो कही गई है कि राजस्थान सरकार पूंजीपतियों के यहां गिरवे रखदी है। इस बात पर खास तौर से बड़े ज़ोर से बता देना चाहता हूं कि उनके अखबार जो निकलते हैं वह भी झूटा प्रचार करते हैं। किन्हीं लोगों को पूंजिपतियों से नफरत है और उनकी विचारधारा नहीं मिलती तो वे अपने विचारों को यहां पर प्लेटफॉर्म बना कर बाहर उगल देते हैं। अगर पोद्दारजी का कर्जा है तो उसको यहां कहने की कोई जरूरत नहीं। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने उनको कर्जा नहीं दिया। वे अगर किसी कॉर्पोरेशन के डाइरेक्टर हैं तो उन्होंने रुपया काम में ले लिया। उन्होंने अपने घरू काम में तो लिया नहीं। वे सैकड़ों मिलों के डाईरेक्टर होंगे। अगर सदन के सदस्यों के पास रुपया है तो वे भी लगावें, पब्लिक के पास रुपया है तो पब्लिक लगावे और भारत सरकार के पास

[श्री मथुरादास माथुर]

हो तो भारत सरकार दे। राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से ऐसा किया हो, ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ने इस चीज की जांच करके ऐसा किया था।

हमारे यहां छोटे-मोटे उद्योगों के लिये कई दरख्वास्ते पेंडिंग हैं, जिसमें लोग २ लाख, ३ लाख, ५० हज़ार आदि रुपयों से छोटे-मोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं? किन्तु उन पर कोई विचार नहीं हो रहा है और मार्केट में पूंजी मिल नहीं सकती। मिसाल के तौर पर, हमारे यहां एक दरख्वास्त आई। हीरे को काटने का काम यहां पर बहुत मशहूर है। होता यह है कि बाहर से सिन्थेटिक स्टौन्स आते हैं और यहां पर काटे जाते हैं और बाहर भेज दिये जाते हैं जिससे उनकी वेल्यू बहुत बढ़ जाती है। यह हालत थी और इस तरह से हीरा काटने वाले सैकड़ों घर, यहां पर जो काम करते हैं, वे बेरोजगार हो जाते थे, इसलिए सिन्थेटिक इन्डस्ट्री यहां बनवाने की कोशिश की। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी। अमेरिकन कम्पनी मिल कर काम करती है। यहां के लोगों के पास पूंजी नही थी, दरख्वास्त दी तो उन्हें इससे पैसा दिया है! इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि पैसा दिया जाय, जैसे बैंक लोन देता है, रूल्स बने हुए हैं, उसी प्रकार गाइड होते हैं। उसके अन्दर डाइरेक्टर एक साहब बने। जो कोई पैसा लगायेगा, शेयर खरीदेगा, वह डाईरेक्टर बनेगा। मथुरादास माथुर जैसा तो नहीं बन सकता जिसके पास पैसा नही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मथुरादास बन सकते हैं, एच. के व्यास नही बन सकता।

श्रीमथुरादास माथुर--मैं इस में नही जाता। यह एच. के व्यास नहीं बन सकता तो दूसरा एच. के व्यास बन सकता है।

तो खेर मुझे खुशी होगी यदि मि० एच. के. व्यास बने डाईरेक्टर। मि० एच. के व्यास तो अकाउन्ट रखते नहीं, पहले से सावधान हैं। (हंसी) इसलिए व्यक्ति विशेष पर इतना महत्व दिया जाय सदन में, मैं उचित नहीं मानता। एच. के. व्यास की बात मंजूर करता हूं कि जो कर्जा है उसके लिए सरकार कदम उठाये। उनके ऊपर पर्सनल हैसियत से कर्जा नहीं है। आज वे डाईक्टर कई मिलों के है। बम्बई, अहमदाबाद, जयपुर आदि कई जगहों पर सिरीज़ आँफ इन्डस्ट्रीज़ के वे डाईरेक्टर हैं। राजस्थान सरकार का कर्जा है। किन्तु इस सरकार ने कर्जा नहीं दिया। राजस्थान बनने के पहले कर्जा दिया जा चुका था। देशी रियासतों का मामला था, कर्जा मिल जाया करता था। वही कर्जा चला आ रहा है, कर्जा चुकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ गंगानगर शुगर फेक्टरी है उसको सरकार को खुद को चलाना पड़ रहा है। उसके कुछ पहलू हैं। यह नहीं है कि सरकार पूंजीपति को प्रोत्साहन देना चाहती है। लेकिन लोगों की इकोनोमिक लाइफ को उठाना पड़ रहा है। कई सरकम्स्टान्सेज हैं, सोशियल और इकोनोमिक लाइफ के। इसके लिए यह चीज जो की गई हैं उन पर एतराज है। किसानों का गन्ना क्या सड़ता रहे पंजाब में चले जावेंगे, इस तरह के नारे लगाते रहते हैं और इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है, तो भी उसको पूंजीपति को मदद देने की बात समझी जा रही है। तो मैं यह कहूं कि सरकार को उलटने का षडयंत्र जैसा भाषण का तरीका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—१, २० हजार रुपया उनको दिया, किसानों को नहीं।

श्री मथुरा दास माथुर—लोन इस आधार पर दिया था कि शुगरकेन ग्रोअर्स गन्ना कहां बेचें। दूसरी फेक्टरी तो नहीं थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्डस्ट्रीज़ रेगुलेशन्स के मातहत एक्वायर हो जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर—आप सुन लीजिये, जो होगा हम जवाब दे देंगे और संतोष न हो तो चौपड़ का मैदान आपके लिए खुला है। (हंसी)

माननीन उपाध्यक्षजी, मैं अर्ज करना चहता हूं कि जिनके द्वारा कई इन्डस्ट्रीज पनपाई जाय और यह मांग होती है कि जोधपुर और जैसलमेर के अन्दर हजारों पाउन्ड ऊन निकल कर व्यावर की मंडी से बाहर चली जाती है और सरकार सहयोग देकर उसको अपनाले और जोधपुर में इन्डस्ट्री कायम की जाय और वह मिल बन्द हो जाय तो सरकार उस मिल को लेकर चलावे नहीं तो धन्धा करने वाले बर्बाद हो जाते हैं और यह कहा जा सकता है कि पूंजीपति की मिल है, कहां तक उचित है ? जब नेशनेलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) की नीति बन रही है, जब सोशलिस्ट पेटर्न बन रहा है। पहले जो हालत थी, उसमें पूंजीपति होंगें, एच. के. व्यास नहीं होंगें। होंगे तो भी सेठ एच. के व्यास होंगे लेकिन एच. के व्यास तो नहीं होंगे।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूँजीपति से उनको नफरत होती है, यह स्वाभाविक चीज़ है। जिस आहिडियोलोजी को वे बिलोंग करते हैं, जिसके पीछे वे चलने का दावा करते हैं; लेकिन हर वक्त घर में चूहे भी खटका कर दें तो यह समझें कि पूँजीपति घर में डाइनेमाइट लगा रहे हैं तो यह अच्छी चीज़ नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्षजो, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उन्हें तसल्ली है कि उन बड़े विचारों में परिवर्तन करने की कोशिश की हो, ऐसी बात नहीं। साफ बात है। काम होता है, सरकार काम करती है। काम किसी मकसद से किया जाता है। लोन दिया गया महाराजा गंगासिंहजी और सादूलसिंहजी के वक्त में। सेठ साहब को मुफ्त में नहीं दिया। गंगानगर में नहरें बनीं। किसानों ने गन्ना पैदा किया, तो गन्ना जाय कहां ? पंजाब दूर पड़ता है। जोधपुर और आस-पास में फैक्टरी नहीं थी तो उन्होंने वहां फैक्टरी कायम करवाई। आज के वातावरण में यह चीज़ मौजू नहीं लगती होगी। जिस समय रुपया दिया उस वक्त हालत और थी। रुपया वसूल कैसे किया जाय ? सरकार इसको चला रही है, किसानों को इससे फायदा हो रहा है और रुपया भी हल्के हल्के वसूल होगा।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिसके बारे में बड़ी चर्चाएँ की गई और कहा गया कि जमीनें बांटी जारही हैं। मैंने शुरू में कह दिया है कि हमारे साथी बड़े निपुणाचार्य हैं वे अलग-अलग चीजों को अलग-अलग रूप में रखते हैं। वे सोचते हैं, जमीनें बांटी जा रही हैं, जमीनें किसे मिलेगी, सिलिंग कमेटी क्या काम करेगी ? मैं भी सीलिंग कमेटी का सदस्य हूँ और इसमें काफी दिलचस्पी लेता रहा हूँ। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चाहे किसी के पास ज़मीन दस हज़ार बीघा हो,

[श्री मथुरादास माथुर]

चाहे वह बड़ा पूँजीपति हो, चाहे बड़ा मिनिस्टर हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे बड़े प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति हो, सीलिंग कमेटी के सामने सब बराबर हैं और सीलिंग कमेटी किसी इलाके में जो हद मुकर्रर कर देगी। उसका सब पर असर पड़नेवाला है। उनकी जमीनें लेगी जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं और उनको देगी जिनके पास कम जमीनें हैं अथवा बिल्कुल जमीन नहीं है। बँटवारा किस तरह से होगा, उसका कुल टोटल हमारे पास आयेगा, वह उसके आधार पर किया जावेगा। जब हम कोटा में सीलिंग कमेटी की बैठक कर रहे थे तो कोटा के साथियों ने कहा था कि यहां सीलिंग करने की क्या आवश्यकता है, यहां जमीन बहुत है जमीन को उठाने वाला नहीं, जोतने वाला नहीं, यहां बड़े-बड़े बीड़ पड़े हुए हैं, बड़े बड़े फार्म डेवलप हो रहे हैं।

श्री राज हिम्मतसिंह—I think you are mistaken, Sir.

श्री मथुरादास माथुर—I am not mistakan. I am repeating the opinion of the members representing Kotah, excuse me. It is on the record of the Government. I do not mean what you have said, but mean what some of the Hon'ble Members have said.

श्री राज हिम्मत सिंह—Of the same feather, I believe.

श्री मथुरादास माथुर—Not of the same feather, but your feather.

(विराम)

हो सकता है कि किसी को जमीन अलॉट कर दी गई हो, किसी भी हालत में। मैं इसके लिए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सीलिंग कमेटी द्वारा रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस रिपोर्ट के बिना असेम्बली भी कोई कानून पास नही कर सकती; जब तक एग्जीक्युटिव गवर्नमेंट जो है वह जमीन अलॉट कर सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। जो अलॉटमेन्ट किया गया है वह... (अश्रव्य) एच० के० व्यास को इस बात से संतोष होगा कि २५ बीघा जो ज़मीन दी गई है उसका सीलिंग हो जायगा। अगर वह कम ज़मीन है तो और दे दी जायगी और इस तरह से ज़मीन देने का सरकार को हक़ है इसमें उनको एतराज नहीं हो सकता। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस सदन के सदस्य चाहे इस ओर बैठने वाला हो या चाहे उस ओर, अगर वह ज़मीन जोतकर कमाना चाहता है, और जिसके पास ज़मीन या जो ज़मीन बंजर पड़ी है उसको उपजाऊ करना चाहता है या किसी को जयपुर के आसपास कोई २५ बीघा ज़मीन मिल जाय चाहे वह बड़ा मिनिस्टर हो या कोई सरकारी आदमी हो, जिसके पास नौकरी के अलावा कमाने का साधन नहीं और उसको यदि जमीन मिल जाती है तो आपको क्यों एतराज होना चाहिये ?...

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे तो कोई एतरात नहीं है भूमिहीन किसानों को है।

श्री माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) हो सकता है कि उसके लिए किसी भूमिहीन किसान की दरख्वास्त न हो। आपको क्या पता कि आज जो एम० एल० ए० है वह यदि कल असेम्बली से हट जाता है तो कम से कम उसके लिए अपनी आजीविका के लिए रोज़गार तो होना

[श्री मथुरादास माथुर]

चाहिए। यह भी हालत आपको देखनी चाहिए। इस माने में आपको अपना नुक़्ते-निगाह बदलना पड़ेगा। अगर आपके दल को किसी वजह से किसी से रुपया मिल जाता है जिससे आप दलका काम करते हैं तो हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं...

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो आप अपने तक ही रखिए।

श्री माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इस लिए मेरी अर्ज़ यह है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप दीजिए। अगर कोई सरकारी अधिकारी गैर मुनासिब तरीके से फ़ायदा उठा कर दूसरे का शोषण करके पैसा कमाने की कोशिश करता है तो ऐसी हालत में मैं एच० के० व्यास के साथ होऊंगा......

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसे भी सरकारी मुलाज़िम है जिनके पास हज़ारों बीघा जमीन है जो एबसेन्टी लेन्ड (absentee land) के नाम पर हज़ारों रुपया मुनाफे के रूप में कमाते हैं।

श्री माथुर—टीनेन्ट प्रोटेक्शन लॉज़ के अनुसार उसको नही मिल सकता, यह लॉ आप ही ने पास किया, आपका भी उसमें मत है।

श्री व्यास—मेरा वोट तो खिलाफ रहेगा और रहा है।

श्री माथुर—यह तो आपकी आदत ही है। चूंकि अब समय होगया है और मुझे अभी काफी कहना है और मुझे आशा है कि मेरे कहने के बाद मेरे इस ओर बैठने वाले सदस्य अपना नाम विथ्ड्रा करलेंगे, उधर से तो कोई अपना नाम विथड्रा करने वाला नहीं, अतः, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिऐ मुझे कल भी समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि अब समय होगया है इसलिए आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल प्रातः ८॥ बजे फिर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी और श्री मथुरादास जी माथुर अपना भाषण जारी रक्खेंगे।

(सदन की बैठक १२ बजकर ३५ मिनट मध्यान्होत्तर, दिनांक २ मार्च, १९५५, के ८॥ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।